वर्ष-11, अंक-5,फरवरी-2026

मूल्यः ₹20

वेलकम इंडिया

RNI No. UPHIN/2015/61611

राष्ट्रीय मासिक हिन्दी पत्रिका

आम बजट 2026-27 से विकसित बनेगा भारत

प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट

9.13 लाख करोड़ से संवरेगा उत्तर प्रदेश

विकसित भारत
विकसित उत्तर प्रदेश

ONE DISTRICT ONE CUISINE

व्यञ्जनेषु वसति संस्कृतिः

UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश दिवस (24 जनवरी, 2026) के अवसर पर

एक जनपद-एक व्यञ्जन योजना लॉन्च

- प्रदेश के हर जनपद के विशिष्ट व्यंञ्जनों को मिलेगी नई पहचान
- पारंपरिक कारीगरों, हलवाइयों, छोटे उद्यमियों को स्थायी आजीविका के अवसर

प्रगति की गति अपार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UPGovtOfficial | CMOUttarpradesh | CMOfficeUP

वर्ष- 11 अंक- 5
फरवरी -2026

सम्पादक ललित कुमार शर्मा

कार्यकारी सम्पादक
अनादि शुक्ल, प्रशांत शर्मा
संजय बंसल, संजीव शर्मा

संरक्षक
स्व. वेद प्रकाश शर्मा
अभिषेक गर्ग, एनके शर्मा, प्रवीण चौधरी
अमिताभ शुक्ल, अरुण शर्मा,
प्रभाकर त्यागी, डॉ. निमित त्यागी

वरिष्ठ सलाहकार
विजय अरोडा, राहुल अग्रवाल,
सचिन तोमर, देवनाथ कुमार

सम्पादकीय सहयोगी
डॉ. बी. जमां

बिजनेस हेड
रजनीकांत शर्मा/विकास पंडित

कानूनी सलाहकार
कीर्तिकर सुकुल (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
वंदना शर्मा भंडारी (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
अनिल आनंद, नीरज सत्संगी

मुद्रक, स्वामी, प्रकाशक, सम्पादक ललित कुमार द्वारा अवनीर एन्टरप्राईजेज, ए-7/105, इंडस्ट्रीयल एरिया साउथ साईड जी.टी. रोड गाजियाबाद से मुद्रित कराकर ग्राउंड फ्लोर 150, दुर्गा टॉवर, आरडीसी राजनगर गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
सम्पादक - ललित कुमार शर्मा
RNI No. UPHIN/2015/61611
ई-मेल: winews.in@gmail.com
वेबसाइट: www.winews.in
सम्पर्क सूत्र: 9891116568

नोट: पत्रिका में प्रकाशित सभी लेखों आदि से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है तथा किसी भी कानूनी वाद-विवाद के लिए गाजियाबाद न्यायालय मान्य होगा।

अन्दर के पेजों में...

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: मोदी नेतृत्व की वैश्विक दृढ़ता पेज 05

संसद बनी बंधक- संविधान का अपमान कौन कर रहा है ? पेज 08

भारत टैक्सी : सहकारिता का नया आयाम पेज 14

डराने लगी है ऑनलाइन गेमिंग की लत एवं आभासी दुनिया पेज 20

रश्मिका मंदाना 26 फरवरी को विजय देवरकोंडा से करेंगी शादी पेज 53

BBC 'इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025' बनीं स्मृति मंधाना पेज 55

विज्ञापन, समाचार के लिए वेलकम इंडिया दैनिक एवं मासिक पत्रिका के जोनल सम्पादक कृष्णराज अरुण से मोबाइल नम्बर 9802414328 /9813221734 पर सम्पर्क करें।

आठ लाख से ज्यादा लोग लापता दिल्ली के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

ललित कुमार
सम्पादक

देश भर में हर साल बड़ी संख्या में लोग लापता हो जाते हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे, महिलाएं और लड़कियां शामिल होती हैं। इस वर्ष जनवरी के पहले पखवाड़े में दिल्ली से आठ सौ से अधिक लोगों के लापता होने की खबरों ने इस मसले की गंभीरता को फिर से उजागर किया है। मगर हैरत की बात है कि इस आपराधिक समस्या से निपटने के लिए अब तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई एकीकृत प्रयास होते नजर नहीं आए हैं। यहां तक कि लापता होने की घटनाएं और उनमें से कितने लोगों को ढूंढ़ लिया गया तथा ऐसे मामलों के पीछे किसका हाथ था, इसका एकीकृत राज्यवार ब्योरा भी मुश्किल से दर्ज हो पाता है। यही वजह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को इस मसले पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वह इस बात का पता लगाए कि देश के विभिन्न हिस्सों में बच्चों के लापता होने की घटनाओं के पीछे किसी देशव्यापी गिरोह या राज्य-विशिष्ट समूह का हाथ तो नहीं है। इसके लिए तमाम राज्यों से ऐसे मामलों की संख्या और कार्रवाई का ब्योरा संकलित कर उनका विश्लेषण करने का निर्देश भी दिया गया है। गौरतलब है कि देश भर में बच्चों की गुमशुदगी के मामलों से संबंधित आंकड़ों के संकलन के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से एक पोर्टल बनाया गया है, जिस पर सभी राज्य ऐसी घटनाओं का ब्योरा दर्ज करा सकते हैं। मगर, इस प्रक्रिया में भी सरकारी तंत्र की उदासीनता साफ देखी जा सकती है। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में खुद यह बात स्वीकार की है कि कुछ राज्यों ने लापता बच्चों और उनसे संबंधित अभियोजन से जुड़े आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं। दरअसल, पिछले वर्ष दिसंबर में शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को लापता बच्चों के सिलसिले में छह साल के राष्ट्रव्यापी आंकड़े उपलब्ध कराने और ऐसे आंकड़ों के संकलन में राज्यों के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने को कहा था। इससे पहले राज्यों को बच्चों की गुमशुदगी के मामलों की निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश भी दिया गया था। इसके बावजूद अगर राज्यों की ओर से संबंधित ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, तो इससे सरकारी तंत्र में व्यवस्थागत खामियों का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। इसमें दोराय नहीं कि देश की राजधानी दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों में विशेषकर बच्चों, महिलाओं और लड़कियों के लापता होने की घटनाएं जितनी बड़ी संख्या में सामने आ रही हैं, उससे इस आशंका को दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि इसके पीछे देशव्यापी या राज्य स्तरीय गिरोहों का हाथ हो सकता है। इसलिए इस बात की गहन जांच-पड़ताल जरूरी है कि लापता होने की ज्यादातर घटनाओं में किसी तरह कोई समानता तो नहीं है! मगर यह तभी संभव होगा, जब राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे मामलों से जुड़े आंकड़ों का संकलन हो पाएगा। इस मसले की गंभीरता का अंदाजा राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की एक रपट से लगाया जा सकता है, जिसके मुताबिक, वर्ष 2023 में देश भर में आठ लाख से ज्यादा लोग लापता हुए थे। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में यह समस्या ज्यादा गंभीर है। ऐसे में जरूरी है कि हर राज्य अपनी जिम्मेदारी को समझे और लापता होने के मामलों में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अगर कहीं कोई लापरवाही बरती जाती है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए, ताकि व्यवस्था में आम लोगों का भरोसा कायम रह सके।

देश भर में बच्चों की गुमशुदगी के मामलों से संबंधित आंकड़ों के संकलन के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से एक पोर्टल बनाया गया है, जिस पर सभी राज्य ऐसी घटनाओं का ब्योरा दर्ज करा सकते हैं। मगर, इस प्रक्रिया में भी सरकारी तंत्र की उदासीनता साफ देखी जा सकती है। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में खुद यह बात स्वीकार की है कि कुछ राज्यों ने लापता बच्चों और उनसे संबंधित अभियोजन से जुड़े आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: मोदी नेतृत्व की वैश्विक दृढ़ता

इस व्यापारिक प्रगति से मोदी सरकार की अंतरराष्ट्रीय साख में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह साख किसी प्रचार या दावे पर नहीं, बल्कि ठोस परिणामों पर आधारित है। भारत आज विश्व मंच पर एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है, जो अपने हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक स्थिरता और सहयोग में भी सकारात्मक भूमिका निभाता है।

संजीव कुमार

अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यापार के परिदृश्य में कोई भी समझौता केवल आंकड़ों या कर-प्रतिशतों तक सीमित नहीं होता, वह राष्ट्र की संप्रभुता, नेतृत्व की दृढ़ता और भविष्य की दिशा का भी संकेतक होता है। भारत और अमेरिका के बीच हालिया व्यापारिक सहमति, जिसके अंतर्गत प्रस्तावित 50 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है, इसी दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी घटना है। यह निर्णय केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति-संतुलन और भारत की बढ़ती सौदेबाजी क्षमता का प्रमाण है। यहां 'देर आए, दुरुस्त आए' की कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है। जब अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर ऊँचे टैरिफ का दबाव बनाया गया था, तब यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था को अंततः झुकना पड़ेगा। वैश्विक व्यापार का हालिया इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि बड़ी शक्तियां अक्सर दबाव की राजनीति के माध्यम से अपने हित साधती हैं। किंतु फरवरी 2025 में आरंभ हुई इस व्यापारिक प्रक्रिया का फरवरी 2026 में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना यह दर्शाता है कि भारत ने न तो जल्दबाजी दिखाई और न ही अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता किया। भारत ने समय लिया, परिस्थितियों का मूल्यांकन किया और अंततः संतुलित व सम्मानजनक परिणाम प्राप्त किया।

50 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक की टैरिफ कटौती का तात्कालिक प्रभाव व्यापारिक जगत और शेयर बाजार में दिखाई दिया। निवेशकों का भरोसा लौटा, निर्यातकों को राहत मिली और बाजार में सकारात्मक संकेत उभरे। किंतु इस निर्णय का वास्तविक महत्व इससे कहीं अधिक व्यापक है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि भारत अब केवल नियमों का पालन करने वाला देश नहीं, बल्कि नियमों के निर्माण और पुनर्परिभाषा में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने वाला राष्ट्र बन चुका है। अमेरिका जैसी महाशक्ति का अपने रुख में नरमी लाना भारत की आर्थिक ताकत, रणनीतिक धैर्य और राजनीतिक आत्मविश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि उसमें संवाद है, पर दबाव के आगे समर्पण नहीं। चाहे वह रक्षा सहयोग हो, ऊर्जा सुरक्षा हो या व्यापारिक समझौते-हर क्षेत्र में भारत ने अपने हितों को केंद्र में रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस व्यापारिक डील में भी भारत ने बिना झुके, बिना रुके और बिना कमजोर पड़े अपनी शर्तें स्पष्ट रूप से रखीं। यही कारण है कि अंततः अमेरिका को अपने प्रस्तावों में संशोधन करना पड़ा। यह केवल एक व्यापारिक जीत नहीं, बल्कि राजनीतिक परिपक्वता और नेतृत्व की दृढ़ता का उदाहरण है। इस समझौते से भारतीय उद्योगों को वैश्विक

प्रतिस्पर्धा में एक उन्नत स्थिति प्राप्त होगी। कम टैरिफ का अर्थ है कि भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे, उनकी पहुंच बढ़ेगी और 'मेक इन इंडिया' को नया प्रोत्साहन मिलेगा। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, कृषि-आधारित उत्पाद और उभरते तकनीकी क्षेत्र-सभी को इससे दीर्घकालिक लाभ होने की संभावना है। भारत अब केवल सस्ता श्रम या कच्चा माल उपलब्ध कराने वाला देश नहीं, बल्कि मूल्यवर्धित उत्पादन और नवाचार की दिशा में अग्रसर अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में जिस संयम और आत्मविश्वास के साथ भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को 'निरंतर धैर्य का परिणाम' बताया, वह उनकी कूटनीतिक शैली का सार है। यह समझौता किसी अचानक हुए घटनाक्रम का नतीजा नहीं, बल्कि एक वर्ष तक चली रणनीतिक प्रतीक्षा, विकल्पों के विस्तार और संतुलित संवाद का परिणाम है। मोदी ने स्पष्ट संकेत दिया कि सरकार ने विपक्ष की आलोचनाओं और तात्कालिक दबावों के बावजूद धैर्य नहीं छोड़ा, क्योंकि वैश्विक व्यापार और भू-राजनीति में जल्दबाजी अक्सर महंगी पड़ती है। अमेरिका का झुकना किसी भावनात्मक मित्रता का परिणाम नहीं, बल्कि ठोस रणनीतिक विवशता का नतीजा है। बीते एक वर्ष में भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसके पास विकल्प हैं-रूस के साथ ऊर्जा सहयोग, यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में अपनी बढ़ती भूमिका। यदि वाशिंगटन भारत पर एकतरफा दबाव बनाए रखता, तो अमेरिकी कंपनियां दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बड़े बाजार से बाहर हो जातीं। ट्रंप द्वारा 500 अरब डॉलर के आयात, शून्य टैरिफ और रूसी तेल त्यागने जैसे नाटकीय दावे इसी दबाव की राजनीति का हिस्सा थे, जिन्हें भारत ने न तो सार्वजनिक टकराव का मुद्दा बनाया और न ही स्वीकारोक्ति दी। मोदी का इन पर मौन यह दशार्ता है कि भारत इस घटनाक्रम को अंतिम समझौते के रूप में नहीं, बल्कि दिशा-निर्धारण के रूप में देख रहा है। इसके विपरीत, भारतीय विपक्ष इस पूरे प्रकरण में अपनी राजनीतिक अधीरता और रणनीतिक अपरिपक्वता को उजागर करता रहा। उसने टैरिफ को लेकर तात्कालिक लाभ-हानि की भाषा में सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ताएं समय, धैर्य और बहुस्तरीय गणनाओं की मांग करती हैं। विपक्ष यह समझने में असफल रहा कि कूटनीति में कभी-कभी पीछे हटना नहीं, बल्कि प्रतीक्षा करना ही सबसे बड़ा कदम होता है। आज जब अमेरिका को अपना अड़ियल रुख छोड़ना पड़ा है और भारत फिर से वैश्विक प्रतिस्पर्धा की अग्रिम पंक्ति में खड़ा दिख रहा है, तब यह स्पष्ट है कि मोदी की नीति न केवल दबाव से मुक्त थी, बल्कि दूरदर्शी भी। यही नीति भारत को एक आत्मविश्वासी, प्रभावशाली और सौदे की शर्तें तय करने वाली शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है।

इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि यह वैश्विक व्यापार में दबाव आधारित राजनीति के अंत का संकेत देता है। लंबे समय से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं टैरिफ, प्रतिबंध और नीतिगत दबावों के माध्यम से छोटे या उभरते देशों को अपनी शर्तें मानने के लिए विवश करती रही हैं। भारत ने इस प्रवृत्ति को न केवल चुनौती दी, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि आत्मविश्वास, आर्थिक क्षमता और राजनीतिक इच्छाशक्ति के बल पर किसी भी दबाव को संतुलित संवाद में बदला जा सकता है। भारत-अमेरिका संबंधों के संदर्भ में यह समझौता एक नए राजनीतिक आभामंडल के निर्माण का भी संकेत देता है। यह संबंध अब केवल रणनीतिक या सामरिक सहयोग तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आर्थिक साझेदारी के एक नए स्तर की ओर बढ़ रहा है। इसका प्रभाव केवल इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक राजनीति में बहुध्रुवीय व्यवस्था को और अधिक मजबूती देगा। दुनिया धीरे-धीरे यह स्वीकार कर रही है कि भविष्य का नेतृत्व किसी एक शक्ति के हाथ में नहीं, बल्कि संतुलित साझेदारियों के माध्यम से उभरेगा, और भारत उसमें एक केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इस व्यापारिक प्रगति से मोदी सरकार की अंतरराष्ट्रीय साख में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

यह साख किसी प्रचार या दावे पर नहीं, बल्कि ठोस परिणामों पर आधारित है। भारत आज विश्व मंच पर एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है, जो अपने हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक स्थिरता और सहयोग में भी सकारात्मक भूमिका निभाता है। यही संतुलन उसे अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं से अलग पहचान देता है। महाशक्ति बनने की भारत की यात्रा भावनात्मक नारों पर नहीं, बल्कि आर्थिक आंकड़ों, रणनीतिक समझौतों और वैश्विक स्वीकार्यता पर आधारित है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इस प्रकार के व्यापारिक समझौते उस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। यह स्पष्ट होता जा रहा है कि भारत को आगे बढ़ने से रोक पाना अब किसी के लिए आसान नहीं है। निश्चित तौर पर यह व्यापारिक समझौता भारत की परिपक्व कूटनीति और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यापार की दुनिया में कोई भी निर्णय केवल आर्थिक गणित नहीं होता, वह राष्ट्र की संप्रभुता, आत्मसम्मान और नेतृत्व की परिपक्वता का भी प्रमाण होता है। देर से लिया गया सही निर्णय, जल्दबाजी में किए गए गलत समझौतों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। भारत ने धैर्य रखा, आत्मसम्मान बनाए रखा और अंततः अपने हितों के अनुरूप परिणाम हासिल किया। निश्चित ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत न केवल सुरक्षित है, बल्कि आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है और यह विश्वास ही उसे महाशक्ति बनने की उड़ान देता है।

विकसित राष्ट्र बनने का रास्ता

अनादि शुक्ल

बजट के प्रावधानों से प्रकट होता है कि भारत अपनी क्षमताओं का विस्तार करने वाला है ताकि दुनिया के बाजार में भारत के उत्पादों की पहुंच बढ़ाई जाए। अमेरिका के साथ समझौते का फ्रेमवर्क जारी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे मेक इन इंडिया कार्यक्रम को लाभ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि देश की महिलाओं व युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे।

इस वर्ष संसद का बजट सत्र कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार संधि हुई और सत्र के बीच में अमेरिका के साथ दोपक्षीय व्यापार संधि की घोषणा हुई। इसका फ्रेमवर्क जारी हो गया है और आगे की वार्ता 13 फरवरी को शुरू होगी। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि पिछले साल जुलाई में अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ लगाया था उसे 25 से घटा कर 18 फीसदी कर दिया है और रूस से तेल खरीदने की वजह से जो अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाया था उसे समाप्त कर दिया है। यह फैसला भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की तस्वीर बदलने वाला है। यह ध्यान रखने की जरुरत है कि जुलाई के बाद जब भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा हुआ था तब भी अमेरिका के साथ होने वाले व्यापार में कमी नहीं आई थी। एक साल पहले की तुलना में इस अवधि में भारत का निर्यात ज्यादा टैरिफ होने के बावजूद बढ़ा था। कल्पना करें कि 50 प्रतिशत टैरिफ होने पर जब निर्यात बढ़ा था तो 18 फीसदी हो जाने पर उसमें कितनी तेजी आएगी!

अमेरिका के साथ जो दोपक्षीय व्यापार संधि यानी बीटीए होनी है उसके अंतरिम फ्रेमवर्क पर बात करें उससे पहले बजट को संक्षेप में समझने की आवश्यकता है। उसी से पता चलेगा कि कैसे भारत ने दुनिया के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की तैयारी पर काम करना शुरू किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण की शुरूआत भारत के विनिर्माण सेक्टर को मजबूती देने के उपायों से की। भारत उन सभी क्षेत्रों में विनिर्माण को मजबूत करेगा, जिन क्षेत्रों के उत्पादों के लिए विदेशी बाजार खुल रहा है। यूरोपीय संघ के 27 देशों के अलावा ब्रिटेन, न्यूजीलैंड जैसे देश और अब अमेरिका का बाजार भारत के निर्यातकों के लिए खुल रहा है। भारत इन देशों को खिलौने बेचता है साथ ही कपड़े, चमड़े के उत्पाद, रत्न व जेवरात, समुद्री उत्पाद आदि भी बेचता है। औषधि, आयुर्वेदिक उत्पाद और कई तरह के कृषि उत्पाद भी बड़ी मात्रा में अमेरिका और यूरोप के बाजारों में जाते हैं। अमेरिका में बिकने

वाली ज्यादातर जेनेरिक दवाएं भारत से जाती हैं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में इन सभी उत्पादों से जुड़े क्षेत्रों को सशक्त बनाने के प्रावधान किए। ध्यान रहे बजट से पहले ही पिछले साल केंद्र सरकार ने श्रम सुधार कर दिए हैं। साथ ही जीएसटी के दूसरे चरण को भी लागू कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने विनिर्माण सेक्टर को बढ़ावा देने के उपायों के साथ साथ सीमा शुल्क से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है। इसका मकसद भी भारतीय कंपनियों को निर्यात के लिए तैयार करना और सक्षम बनाना का है। यह सब किया गया वित्तीय अनुशासन को कायम रखते हुए और अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाते हुए।

बजट के प्रावधानों से प्रकट होता है कि भारत अपनी क्षमताओं का विस्तार करने वाला है ताकि दुनिया के बाजार में भारत के उत्पादों की पहुंच बढ़ाई जाए। अमेरिका के साथ समझौते का फ्रेमवर्क जारी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे मेक इन इंडिया कार्यक्रम को लाभ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि देश की महिलाओं व युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। निश्चित रूप से यह बड़ी बात है और इसे समझना व स्वीकार करना बहुत मुश्किल नहीं है। जब अमेरिका अपना 27 लाख करोड रुपए का बाजार भारत के लिए खोल रहा है, यूरोपीय संघ के साथ भी 25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होना है और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी 25 लाख करोड़ रुपए के व्यापार की सहमति बनी है तो निश्चित रूप से भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा और जब उत्पादन बढ़ेगा तो उसमें महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। यूरोपीय संघ के साथ तो मोबिलिटी का समझौता अलग से हुआ है, जिससे भारत के युवाओं को यूरोपीय देशों में ज्यादा आसानी से शिक्षा व रोजगार के अवसर मिलेंगे। एक और अच्छी बात यह है कि अमेरिका के साथ समझौते से पहले जितने तरह की आशंकाएं जताई जा रही थीं वो सारी गलत साबित हुई हैं। भारत ने अपने किसानों और पशुपालकों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की है। सोयाबीन सहित सभी फसलों को अंतरिम समझौते से बाहर रखा गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका के कृषि व डेयरी उत्पादों पर पहले पूरी तरह से पाबंदी थी। पहले भी ये उत्पाद भारत के बाजार में आते थे लेकिन उन पर मात्रात्मक पाबंदी थी और टैरिफ ज्यादा था। वह स्थिति बनी रहेगी।

बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक तरफ वाणिज्य मंत्रालय की टीम दुनिया के देशों के साथ व्यापार संधियां कर रही है तो दूसरी ओर वित्त मंत्रालय ने ऐसा बजट तैयार किया, जो इन व्यापार संधियों के लिए पूरक की तरह काम करे। बजट में ऐसे प्रावधान किए, जिनसे भारत को इन संधियों का अधिकतम लाभ मिल सके। बजट में विनिर्माण सेक्टर से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। वित्त मंत्री ने 12.20 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च का ऐलान किया। इसमें से लगभग आधा खर्च सड़क और रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। यह मानने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि सरकार के इस मध्यावधि बजट में लोक लुभावन घोषणाओं से ज्यादा देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, नीतिगत स्तर पर एक दिशा देने और विनिर्माण सेक्टर को शक्तिशाली बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका लाभ आने वाले वर्षों में देश के सभी 140 करोड़ नागरिकों को मिलेगा। बजट प्रावधानों और दुनिया भर के देशों के साथ हो रहे व्यापार समझौतों से 2047 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प को शक्ति मिलेगी।

संसद का बजट सत्र और भी कई कारणों से बहुत अहम हो गया है। बजट सत्र होने के बावजूद विपक्ष ने रचनात्मक भूमिका निभाने की बजाय टकराव का रास्ता चुना। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में नियमों का उल्लंघन करके एक अप्रकाशित किताब के अंश पढ़ने शुरू कर दिए और जब नियम 349 के हवाले उनको रोका गया तो उन्होंने इसे अपने अहंकार का मुद्दा बना दिया। उनकी पार्टी अपने नेता के अहंकार की रक्षा के लिए उतर गई और इसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार की ओर से पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा नहीं हो सकी। जब चर्चा नहीं हो पाई तो प्रधानमंत्री का जवाब भी नहीं हो पाया। विपक्षी पार्टियों ने महिला सांसदों को आगे करके ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि स्पीकर महोदय को कहना पड़ा कि कुछ अप्रत्याशित घटित हो सकता था। इसलिए प्रधानमंत्री ने लोकसभा में जवाब नहीं दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यसभा में जवाब दिया। पता नहीं विपक्षी पार्टियों को इसका अनुमान है या नहीं कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर भी संसद को बाधित करके वे अंततः अपना नुकसान करते हैं।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब

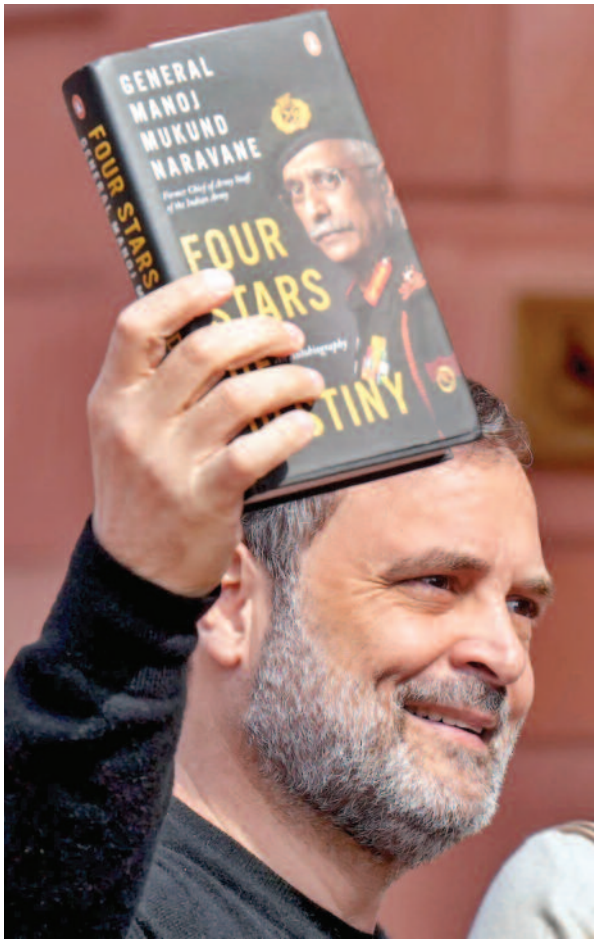

के हवाले जो सवाल उठा रहे थे वो सवाल पलट कर उनकी पार्टी और सरकार के ऊपर आ गए। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2007 में सेना के रिटायर मेजर जनरल वीके सिंह के गुड़गांव स्थिति आवास पर छापा मरवाया था। उनके खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया था। उनका कसूर इतना था कि उन्होंने 'इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलीजेंसः सीक्रेट्स ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग' नाम से एक किताब लिखी थी। इससे कांग्रेस सरकार की ढेर सारी कमियां सामने आ रही थीं। ध्यान रहे मेजर जनरल वीके सिंह चार साल तक भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी में तैनात रहे थे। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर किताब लिखी थी लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इसके लिए उनके खिलाफ सीबीआई में मुकदमा कराया और छापा मरवाया। कांग्रेस और उसके नेताओं को समझना चाहिए सेना का मामला बहुत संवेदनशील होता है और उस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। लगातार हार से परेशान कांग्रेस को एक मुद्दे की तलाश है और उस तलाश में उसके नेता सेना को घसीटने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। परंतु बजट सत्र में कांग्रेस का यह प्रयास भी नाकाम रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस विवाद का कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन उन्होंने बताया कि कांग्रेस की पहले की सरकारों ने कितनी गड़बड़ी की है, जिसे ठीक करने में उनका सबसे ज्यादा समय जाया हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जो कहा उसे समझने के लिए उनकी ओर से दिया गया एक उदाहरण काफी है। उन्होंने बताया कि उनके जन्म से पहले नर्मदा बांधी की आधारशिला रखी गई थी और जब वे मुख्यमंत्री बने तो उनके प्रयास से यह कार्य पूरा हुआ। उनके स्वंय मुख्यमंत्री रहते इसके लिए तीन दिन तक धरना देना पड़ा था। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे कांग्रेस की इस कार्य संस्कृति को बदलते हुए देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। उनको परवाह नहीं है कि विपक्ष उनके बारे में क्या कहता है। उन्होंने कहा कि उनका रिमोट 140 करोड़ लोग हैं। इसका अर्थ है कि वे वही करते हैं, जो 140 करोड़ लोग चाहते हैं और जो उनके हित का है। इसमें अड़ंगा डाल कर विपक्ष अपना नुकसान करता है।

संसद बनी बंधक-संविधान का अपमान कौन कर रहा है?

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय हंगामा करके देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान करने के बाद जब समय आने पर राहुल गांधी को बोलने का अवसर दिया गया तो उन्होंने विषय से इतर जाकर पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की एक अप्रकाशित पुस्तक कोट करते हुए चीनी घुसपैठ का पुराना मुद्दा उछालने का प्रयास किया।

इंद्रेश शर्मा

वर्ष -2026 का बजट सत्र हल्ले-गुल्ले और अराजकता की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ बजट के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों को उठाए जाने का प्रयास हो रहा है। स्थितियां इतनी विकट हैं कि संसदीय इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री लोकसभा में उत्तर नहीं दे सके और राष्ट्रपति का अभिभाषण बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। यद्यपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में 97 मिनट लंबा और प्रभावशाली उत्तर दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष द्वारा की गई सभी टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन देश के स्वर्णिम भविष्य और विकास की दिशा को भी दशार्ता है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय हंगामा करके देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान करने के बाद जब समय आने पर राहुल गांधी को बोलने का अवसर दिया गया तो उन्होंने विषय से इतर जाकर पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की एक अप्रकाशित पुस्तक कोट करते हुए चीनी घुसपैठ का पुराना मुद्दा उछालने का प्रयास किया। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियमों के अंतर्गत व्यवस्था दिए जाने के बाद भी राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े रहे। यह एक आश्चर्यजनक व्यवहार है कि नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के स्थान पर पुराने मुद्दे उठाए और उनको भी आपत्तिजनक रूप से रखकर देश की सेना और सदन का अपमान करे। लोकसभा में कांग्रेस तथा इंडी गठबंधन की महिला

सांसदों ने जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता रोकने की योजना बनायी और लोकसभा अध्यक्ष को प्रधानमंत्री से सदन न आने का अनुरोध करना पड़ा वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। विडम्बना ये है कि यही लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बाते करते हैं। राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में भाग न लेकर विपक्षी दलों ने न केवल राष्ट्रपति पद का अपमान किया है अपितु एक गरीब परिवार से निकलकर आई आदिवासी महिला का भी अपमान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में राहुल गांधी व कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और केंद्रीय रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर भी राहुल गांधी घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनका अहंकार सातवें आसमान पर पहुंच गया है । कांग्रेस छोड़कर कितने ही लोग निकले हैं किसी और को तो गद्दार नहीं कहा, ये सिख हैं इसलिए कहा, ये सिखों का, गुरुओं का अपमान था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकसभा में चेयर पर कागज फेकें गए जब असम के सदस्य चेयर की कुर्सी पर विराजमान थे क्या यह असम का अपमान नहीं? जब आंध्र प्रदेश के एक दलित सदस्य चेयर की कुर्सी पर बैठे थे तब उन पर भी कागज फेंके गए क्या यह एक दलित बेटे और संविधान का अपमान नहीं है ?

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आखिर कांग्रेस उनके लिए कब्र खुदेगी का नारा क्यों देती है ? हमने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 से हटाई इसलिए या हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उबारा है इसलिए? प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के किसी नागरिक की कब्र खोदने के सपने देखती है? आजकल मोहब्बत की दुकान खोलने वाले 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी' के नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है। हमने नार्थ ईस्ट में बम बंदूक और आतंक का जो साया बना रहता था वहां शांति और विकास की राह अपनाई इसलिए वह मोदी की कब्र खोद रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियो को घर में घुसकर मारते हैं, ऑपरेशन सिंदूर करते हैं और इसलिए वे मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं।

मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये जो उनके भीतर नफरत भरी हुई है मोहब्बत की दुकान में जो आग भरी पड़ी हुई है, उसका कारण है किकांग्रेस इस बात को पचा नहीं पा रही है कि कोई और क्यों प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, ये तो हमारा पैतृक अधिकार था इसलिए वे हताशा में मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगे जोड़ा कि कांग्रेस को ये सहन नही हो रहा हे कि जो समस्याएं उसने 60 सालो में पाल- पोस कर बड़ी की थीं मोदी उनका एक-एक करके समाधान क्यों कर रहा है? कांग्रेस को ये सब पसंद नहीं आ रहा है इसलिए अब कांग्रेस के नेता मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन यूनियन और फिर अमेरिका के साथ जो व्यापार समझौते हुए उनके विषय में जानकारी देते हुए बताया कि अब पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और समझौते कर रही है। कांग्रेस को भी यह अवसर मिला था, उन्होंने यह क्यों नही कर दिखाया?

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के माध्यम से कांग्रेस,लेफ्ट व डीएमके सहित टीएमसी पर भी तीखा हमला बोला और उन्होंने बंगाल की टीएसमी सरकार को देश की सबसे निर्मम सरकार बताते हुए कहा कि यह लोग अपने अंदर नहीं झाकते अपितु हमको यहां बैठकर उपदेश देते हैं। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा सांसद सदानंद मास्टर के भाषण का संज्ञान लेते हुए वैचारिक सहिष्णुता की चर्चा की, ज्ञातव्य है कि सदानंद मास्टर के दोनों पैर वामपंथी विचारधारा के लोगों ने निर्ममता से केवल उनकी विचारधारा अलग होने के कारण काट दिए थे। संसद के वर्तमान सत्र में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने जो रवैया अपनाया है उसने देश के वास्तविक मुद्दों को उठाने का एक सुनहरा अवसर खो दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा को घेरने के बजे उन्होंने भाजपा व प्रधानमंत्री मोदी को ही अपने ऊपर आक्रमण करने का अवसर दे दिया है। भाजपा अब सिख व दलित सांसदों के अपमान का राजनैतिक लाभ उठाने का पूरा प्रयास करेगी। भाजपा चुनाव वाले राज्यों में विरोधी दलों के संसदीय आचरण को भी मुद्दा बनाएगी।

चरण सिंह

नारी देह, नारी अधिकार

माहवारी पर सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि

विडंबना यह है कि जिस माहवारी को प्रकृति ने जीवन-चक्र का अनिवार्य और स्वस्थ हिस्सा बनाया है, उसे हमारे समाज ने सदियों से अपवित्रता, अशुद्धता और वर्जना से जोड़ दिया। परिणामस्वरूप, करोड़ों महिलाएँ और किशोरियाँ न केवल शारीरिक कष्ट झेलती हैं, बल्कि मानसिक पीड़ा, हीनभावना और सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करती हैं।

भारत के सामाजिक विकास की यात्रा में महिलाओं की स्थिति हमेशा एक निर्णायक कसौटी रही है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल आर्थिक आँकड़ों या बुनियादी ढाँचे से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से आँकी जाती है कि वह अपने समाज के आधे हिस्से-महिलाओं को कितना सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर देता है। इसी सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मासिक धर्म स्वास्थ्य को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है। कोर्ट ने देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त और सुरक्षित बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मासिक धर्म स्वच्छता को गरिमा और स्वास्थ्य के साथ जीने के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है। स्कूलों में साफ-सुथरे शौचालय और पानी की उचित व्यवस्था अनिवार्य है। इस निर्णय का उद्देश्य पीरियड्स के कारण लड़कियों की पढ़ाई में होने वाली बाधा को रोकना और उन्हें शर्मिंदगी से बचाना है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महिलाओं और विशेषकर स्कूली लड़कियों की माहवारी से जुड़ी समस्या पर दिया गया ऐतिहासिक निर्णय, एक सशक्त और दूरदर्शी कदम है। कर्नाटक सरकार ने सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र की महिला कर्मचारियों के लिए 12 दिन का सवेतन पीरियड लीव नीति को भी मंजूरी दी है। यह फैसला स्कूलों में मासिक धर्म प्रबंधन की कमी को दूर करने और छात्राओं के सम्मानजनक शिक्षा के अधिकार की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। स्कूलों में अनिवार्य रूप से सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने का

निर्देश केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना को झकझोरने वाला संदेश है कि अब माहवारी जैसे विषय को चुप्पी, लज्जा और अज्ञान के अंधेरे में नहीं छोड़ा जा सकता।

विडंबना यह है कि जिस माहवारी को प्रकृति ने जीवन-चक्र का अनिवार्य और स्वस्थ हिस्सा बनाया है, उसे हमारे समाज ने सदियों से अपवित्रता, अशुद्धता और वर्जना से जोड़ दिया। परिणामस्वरूप, करोड़ों महिलाएँ और किशोरियाँ न केवल शारीरिक कष्ट झेलती हैं, बल्कि मानसिक पीड़ा, हीनभावना और सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करती हैं। आज भी भारत के अनेक हिस्सों में माहवारी के दौरान लड़कियों को रसोई, पूजा, स्कूल और सामाजिक गतिविधियों से दूर रखा जाता है। यह व्यवहार केवल परंपरा नहीं, बल्कि स्त्री की गरिमा और अधिकारों का प्रत्यक्ष हनन है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि 'माहवारी स्वच्छता की कमी महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाती है' इस पूरे विमर्श को एक नई संवैधानिक दृष्टि देती है। संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन और गरिमा के अधिकार को यदि वास्तविक अर्थों में लागू करना है, तो महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देनी ही होगी। स्कूलों में सेनेटरी पैड की अनिवार्य व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई अध्ययन बताते हैं कि स्वच्छता सुविधाओं के अभाव में बड़ी संख्या में लड़कियाँ किशोरावस्था में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। यह केवल शिक्षा का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे समाज की बौद्धिक और नैतिक पूंजी की क्षति है। न्यायालय ने शिक्षा को एक 'मल्टीप्लायर राइट' बताया जो अन्य मानवाधिकारों के उपयोग की कुंजी है। न्यायालय ने इस निर्णय को केवल आदर्शों की घोषणा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जमीन पर उतारने के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक निर्देश दिए। कक्षा 6 से 12 तक की सभी छात्राओं को मुफ्त, उच्च गुणवत्ता वाले ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। इन पैड्स का एएसटीएम डी-6954 जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य किया गया, ताकि स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके। साथ ही, पैड्स की सहज, सुरक्षित और गोपनीय उपलब्धता के लिए स्कूलों में वेंडिंग मशीन या नामित अधिकारी की व्यवस्था तय की गई, जिससे छात्राओं की झिझक और असहजता पूरी तरह दूर की जा सके। इसके साथ ही स्कूलों में 'मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन कॉर्नर' स्थापित करने का आदेश दिया गया, जहाँ अतिरिक्त यूनिफॉर्म, स्पेयर इनरवियर, डिस्पोजेबल बैग और आवश्यक स्वच्छता सामग्री उपलब्ध होगी। दिव्यांग छात्राओं के लिए व्हीलचेयर-अनुकूल शौचालय और सहायक उपकरण जैसी विशेष सुविधाएँ अनिवार्य की गईं। निजी स्कूलों द्वारा निर्देशों की अवहेलना पर मान्यता रद्द करने का प्रावधान रखकर जवाबदेही को मजबूत किया गया, ताकि यह फैसला केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि हर छात्रा के जीवन में वास्तविक बदलाव ला सके।

माहवारी स्वच्छता केवल पैड उपलब्ध कराने तक सीमित विषय नहीं है। इसके साथ जुड़ा है स्वच्छ शौचालय, साफ पानी, कचरा निस्तारण की व्यवस्था और सबसे महत्वपूर्ण कृसही जानकारी। आज भी अनेक लड़कियाँ पहली माहवारी के समय भय, भ्रम और अपराधबोध से घिर जाती हैं क्योंकि उन्हें पहले से कोई वैज्ञानिक और संवेदनशील जानकारी नहीं दी जाती। स्कूलों में यदि स्वास्थ्य शिक्षा को गंभीरता से लागू किया जाए और माहवारी को एक सामान्य जैविक प्रक्रिया के रूप में समझाया जाए, तो यह डर और संकोच स्वतः समाप्त हो सकता है। यह भी सच है कि माहवारी को लेकर समाज में फैली चुप्पी पुरुषों की भूमिका को भी प्रश्नों के घेरे में लाती है। जब तक पुरुष-चाहे वे पिता हों, शिक्षक हों, प्रशासक हों या नीति-निमार्ता, इस विषय को केवल 'महिलाओं का मामला' मानकर किनारे करते रहेंगे, तब तक वास्तविक बदलाव संभव नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं कि उन्होंने समाज और खासकर पुरुषों को संवेदनशील बनने का अवसर दिया है। जागरूकता का अर्थ केवल महिलाओं को सशक्त बनाना नहीं, बल्कि पुरुषों को सहृदय और जिम्मेदार बनाना भी है।

> मीडिया, शिक्षा संस्थान, धार्मिक और सामाजिक संगठन सभी को मिलकर माहवारी को लेकर फैली भ्रांतियों को तोड़ना होगा। इसे शर्म का नहीं, स्वास्थ्य और स्वाभिमान का विषय बनाना होगा।

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में माहवारी से जुड़ी चुनौतियाँ और भी गंभीर हैं। वहाँ आज भी कपड़े, राख या अस्वच्छ साधनों का उपयोग आम है, जिससे संक्रमण और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। सरकारी योजनाएँ और गैर-सरकारी प्रयास मौजूद हैं, परंतु उनकी पहुँच और प्रभावशीलता अभी भी सीमित है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यदि ईमानदारी से लागू होता है, तो यह नीति और जमीन के बीच की खाई को पाटने में सहायक हो सकता है। यह भी विचारणीय है कि माहवारी स्वच्छता को केवल कल्याणकारी योजना न मानकर महिला अधिकारों के व्यापक ढाँचे में देखा जाए। स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और समानता का अधिकार-तीनों इस विषय से सीधे जुड़े हैं। एक ऐसी व्यवस्था जहाँ लड़की केवल इसलिए स्कूल न जा सके क्योंकि उसके पास सेनेटरी पैड नहीं हैं, वह व्यवस्था संविधान की आत्मा के विपरीत है। इसलिए यह फैसला सामाजिक न्याय की अवधारणा को भी मजबूती देता है। आज भारत 'नए प्रवेश' के साथ आगे बढ़ने की बात करता है-डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विश्वगुरु बनने की आकांक्षा रखता है। किंतु यदि इस विकास की गाथा में महिलाओं की बुनियादी आवश्यकताएँ और सम्मान शामिल नहीं हैं, तो यह प्रगति खोखली सिद्ध होगी। वास्तविक विकास वही है जो सबसे कमजोर वर्ग की पीड़ा को समझे और उसे दूर करने का साहस रखे। माहवारी जैसे विषय पर खुली चर्चा उसी साहस का प्रतीक है। समाज में जन-जागृति लाना इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। कानून और आदेश दिशा दिखा सकते हैं, परंतु मानसिकता बदलना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। मीडिया, शिक्षा संस्थान, धार्मिक और सामाजिक संगठन सभी को मिलकर माहवारी को लेकर फैली भ्रांतियों को तोड़ना होगा। इसे शर्म का नहीं, स्वास्थ्य और स्वाभिमान का विषय बनाना होगा। अंततः, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक शुरूआत है, मंजिल नहीं। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम इसे कितनी ईमानदारी से लागू करते हैं और कितनी संवेदनशीलता से अपनाते हैं। यदि हम सचमुच एक समावेशी, न्यायपूर्ण और मानवीय भारत का निर्माण चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास के साथ नया भारत बनाना चाहते हैं तो महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों को विकास के केंद्र में रखना ही होगा। माहवारी से मुक्ति का अर्थ केवल शारीरिक सुविधा नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और संवैधानिक स्वतंत्रता है।

एआई के क्षेत्र में नई संभावनाएं

हरेन्द्र शर्मा

यह भी जरूरी है कि देश के कोने-कोने में विशेषतया ग्रामीण और पिछड़े हुए क्षेत्रों में एआई से रोजगार के मद्देनजर एआई स्किल्स से जुड़ी प्रोग्रामिक भाषाओं से बड़ी संख्या में युवाओं को कुशल बनाने के प्रयास करने होंगे...

इन दिनों देश ही नहीं, दुनिया की निगाहें दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इम्पैक्ट समिट-2026 की ओर लगी हुई है। इस समिट में दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल, बड़ी-बड़ी कंपनियों के सीईओ समेत करीब 35 हजार से अधिक एआई एक्सपर्ट शामिल होंगे। इस समिट की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और समिट में 700 से अधिक सत्र होंगे। समिट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि सभी के साथ मिलकर हम एआई के मद्देनजर बेहतर विश्व बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। गौरतलब है कि इन दिनों एआई पर प्रकाशित हो रही वैश्विक रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि अब भारत एआई के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेगा। वस्तुतः भारत में हेल्थकेयर, शिक्षा, गवर्नेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में एआई टेक्नोलॉजी को सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का टूल नहीं, बल्कि देश को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। पिछले दिनों प्रकाशित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल आर्टिफिशियल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में भारत को तीसरी रैंकिंग दी गई है। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर चीन है। 2023 में भारत सातवें स्थान पर था। इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारत जैसे-जैसे रणनीतिक रूप से एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे भारत की नई पीढ़ी एआई कामों में लगातार अपना योगदान बढ़ा रही है।

पिछले दिनों ओपन एआई के सीईओ सैम आल्ट मैन ने कहा कि अब ऊंचे वेतन वाली नई नौकरियां सिर्फ एआई पेशेवरों को मिलते हुए दिखाई देंगी। उनके मुताबिक एआई के लिए दुनिया में भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के मुताबिक भारत एआई के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। माइक्रोसाफ्ट के सीईओ सत्या नडेला के मुताबिक भारत की गणित में दक्ष नई पीढ़ी के लिए एआई के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। यह बात महत्वपूर्ण है कि हाल ही में विश्व प्रसिद्ध अमेरिका की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एमेजोन ने 2030 तक भारत में एआई को लेकर 35 अरब डॉलर के नए निवेश करने का ऐलान किया है। इसके पहले माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 17.5 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया था। यह कंपनी द्वारा पूरे एशिया में अभी तक का सबसे बड़ा निवेश होगा। इनके अलावा गूगल और टीपीजी ने भी भारत में 16 अरब डॉलर निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अमेरिका की वैश्विक वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधक कंपनी ब्रुकफील्ड ऐसेट मैनेजमेंट ने मुंबई के पवई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) बनाने पर एक अरब डॉलर का निवेश किए जाने का ऐलान किया है। देश के वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में एआई को अत्यधिक महत्व दिया गया है। साथ ही विदेशी डेटा कंपनियों के जो जीसीसी भारत में आएंगे, उन्हें 2047 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। एआई को

लेकर नई निवेश प्रतिबद्धताओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब एआई की बात आती है तब दुनिया भारत को लेकर आशावादी है। भारत के युवा ऐसे एआई निवेश का फायदा उठाकर नवाचार करेंगे और एआई की शक्ति का उपयोग आर्थिक और सामाजिक विकास में करेंगे। यदि हम इस समय भारत में एआई पारिस्थितिकी तंत्र को देखें तो पाते हैं कि यह तेजी से विस्तार कर रहा है। फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट्स के मुताबिक भारत में एआई का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। जहां वर्ष 2025 में भारत का एआई बाजार 13.05 अरब डॉलर मूल्य की ऊंचाई पर रहा है, वहीं यह बाजार आकार 2032 में 130.63 अरब डॉलर मूल्य का अनुमानित है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि भारत में प्रौद्योगिकी और एआई पारिस्थितिकी तंत्र में 60 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं।

देश में 1800 से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र हैं, जिनमें 500 से अधिक एआई पर केंद्रित हैं। भारत में लगभग 1.8 लाख स्टार्टअप हैं, और पिछले वर्ष शुरू किए गए नए स्टार्टअप में से लगभग 89 फीसदी ने अपने उत्पादों या सेवाओं में एआई का उपयोग किया है। यह बात महत्वपूर्ण है कि दुनिया का 16 फीसदी एआई टैलेंट भारत के पास है और भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में अभी 6 लाख से अधिक एआई प्रोफेशनल्स हैं। इनकी संख्या वर्ष 2027 तक तेजी से बढकर 12.5 लाख पर पहुंच जाने की उम्मीद है। इस समय गूगल की एआई अवसर एजेंडा नामक जिस रिपोर्ट को करोड़ों लोगों के द्वारा पढ़ा जा रहा है, उसमें कहा गया है कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, तकनीकी प्रतिभा और जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम के चलते भारत एआई से लाभान्वित होने की बेहतर स्थिति में है। भारत में एआई प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने से उत्पादकता में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। अब उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, सर्विस सेक्टर तथा अन्य क्षेत्रों में एआई के अधिक उपयोग से भारत को 2030 तक 33.8 लाख करोड़ का आर्थिक लाभ हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई के प्रति एक व्यापक और जिम्मेदार दृष्टिकोण भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को संभव बना सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय श्रम शक्ति नीति 2025 के मसौदे के तहत स्वीकार किया है कि भारत का श्रम बाजार ढांचागत बदलाव से गुजर रहा है और अब एआई और नए कौशल विकास पर जोर देना जरूरी है। नीति आयोग की रिपोर्ट रोडमैप फॉर जॉब क्रिएशन इन द एआई इकोनॉमी 2025 के मुताबिक एआई के बढ़ते प्रभाव से जहां 2031 तक बड़ी संख्या में पारंपारिक नौकरियां खत्म हो सकती हैं, वहीं एआई से जुड़ी करीब 40 लाख नई नौकरियां निर्मित होते हुए दिखाई देंगी। ऐसे में देश की नई पीढ़ी के लिए एआई आधारित नौकरियों के बढ़ते अवसरों के बीच नई पीढ़ी को एआई पेशेवर के रूप में सुसज्जित करने की बड़ी चुनौती भी सामने खड़ी हुई है। स्थिति यह है कि अगर इस परिप्रेक्ष्य में तुरंत कदम नहीं उठाए गए, तो भारत न केवल दूसरे देशों से एआई प्रतिभा के क्षेत्र में पीछे हो जाएगा, बल्कि एआई से होने वाले बहुआयामी विकास में भी पिछड़ जाएगा।

ऐसे में हमें देश की नई पीढ़ी को एआई स्किल्स से सुसज्जित करने की नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। यह सराहनीय कदम है कि शिक्षा मंत्रालय ने नई पीढ़ी को प्रारंभिक स्तर से ही भविष्य की तकनीक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जोड़े जाने के मद्देनजर आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से देशभर के सभी स्कूलों में तीसरी कक्षा से ही एआई पढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ-साथ माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि हैदराबाद स्थित उसका 'इंडिया साउथ सेंट्रल क्लाउड रीजन' साल 2026 के मध्य में शुरू हो जाएगा, जिसका कुल आकार लगभग दो ईडन गार्डन स्टेडियम के बराबर है। कंपनी ने भारत में एआई स्किल्स से लैस टैलेंट डेवलप करने के अपने लक्ष्य को एक करोड़ से दोगुना करते हुए 2030 तक दो करोड़ लोगों को एआई स्किल्स देने का संकल्प लिया है। ऐसे में यह भी जरूरी है कि देश के कोने-कोने में विशेषतया ग्रामीण और पिछड़े हुए क्षेत्रों में एआई से रोजगार के मद्देनजर एआई स्किल्स से जुड़ी प्रोग्रामिक भाषाओं से बड़ी संख्या में युवाओं को कुशल बनाने के कई गुना प्रयास करने होंगे। उम्मीद करें कि दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इम्पैक्ट समिट-2026 का आयोजन भारत के लिए विशेष रूप से हितकर होगा। साथ ही एआई से भारत सभी क्षेत्रों में विकास करते हुए दुनिया में भी एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।

भारत टैक्सी : सहकारिता का नया आयाम

भारत टैक्सी रोजगार, मोबिलिटी, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। यह एक जीता-जागता उदाहरण है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे देश के हित में काम कर सकता है। जैसे यूपीआई ने भुगतान को बदला, वैसे ही भारत टैक्सी जैसे ओएनडीसी पर आधारित प्लेटफॉर्म सेवा और ई-कॉमर्स को बदल देंगे...

5 फरवरी 2026 को, गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अमूल समेत कई सहकारी संस्थाओं के साथ मिलकर सहकारिता मंत्रालय की पहल के तौर पर भारत टैक्सी लॉन्च की। प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए भारत टैक्सी उबर और ओला की तर्ज पर टैक्सी सेवाएं प्रदान करेगी। यानी भारत टैक्सी ऐप इस्तेमाल द्वारा अब यात्री अपनी यात्रा बुक कर सकेंगे। भारत टैक्सी की खासियत यह है कि यह किसी कंपनी द्वारा चलाई गई ऐप नहीं है। इस उपक्रम के मालिक स्वयं ड्राइवर होंगे, और अब वे ड्राइवर नहीं सारथी कहलाएंगे। जो यात्रा इस ऐप के माध्यम से बुक की जाएगी उस पर सारथी यानी ड्राइवर को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। गौरतलब है कि उबर, ओला और अन्य टैक्सी

अजीत शर्मा

ऐप में ड्राइवरों को वर्तमान में 10 से 30 प्रतिशत तक का शुल्क देना पड़ता है। यह आत्मनिर्भर भारत और सहकार से समृद्धि की दिशा में एक मजबूत कदम है। भारत टैक्सी, जो एक कोऑपरेटिव मॉडल पर बनी है, जहां ड्राइवर सिर्फ सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि हितधारक भी हैं। पूर्व के ऐप प्लेटफॉर्म के उलट, भारत टैक्सी का मॉडल जीरो-कमीशन का है, जिससे यह पक्का होता है कि ड्राइवरों को उनकी सही कमाई मिलती रहे। भारत टैक्सी मॉडल के चार स्तंभ हैं सारथियों को ज्यादा आमदनी, सम्मान, सुरक्षा और लाभ में हिस्सा।

कैसे बढ़ेगी आमदनी : एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे एक ड्राइवर उबर, ओला या किसी अन्य कंपनी के ऐप पर ट्रिप खोजते हुए काम करता है। इन ऐप्स के कारण कमीशन, आय के नुकसान के कारण नाहक शोषण का शिकार होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई ड्राइवर दिन में 14 ट्रिप करता है और लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा करता है, जिसमें 300 रुपए प्रति ट्रिप का औसत किराया होता है, जिसका मतलब लगभग 14-15 घंटे काम करना हो सकता है, तो उसे 4200 रुपए की आय होगी। लेकिन यह आय वास्तव में उसकी नहीं है, वास्तव में इस आय का

आधा भी उसका नहीं है। वास्तव में कंपनी औसतन इस आय का लगभग 25 प्रतिशत प्लेटफॉर्म शुल्क के रूप में लेती है, यानी 1050 रुपए सीधे कंपनी को जाते हैं। फिर, ड्राइवर को टैक्सी चलाने के लिए पेट्रोल/सीएनजी का भुगतान करना पड़ता है, 4 रुपए प्रति किलोमीटर माने तो लगभग 1000 रुपए। या फिर अगर कार किसी बैंक या संस्था से फाइनेंस करवाई गई है तो ईएमआई देनी पड़ सकती है और मेंटेनेंस के लिए भी रकम खर्च करनी पड़ सकती है। इसलिए, ड्राइवर को एक दिन में 14-15 घंटे काम करने पर सिर्फ 1150 रुपए बचेंगे, औसतन लगभग 80-85 रुपए प्रति घंटा। अब, भारत टैक्सी से जुड़ने वाले ड्राइवरों के बिना किसी कमीशन मॉडल के, अच्छे-खासी राशि की कमीशन बचाने से, उतने काम से उनकी आमदनी बढकर 2150 रुपए प्रति दिन हो जाएगी, यानी 160 से 170 रुपए प्रति घंटा। इससे वह ज्यादा आराम के घंटे चुन सकते हैं, जिन्हें वह अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं, जिससे उनका आराम और इनकम दोनों बेहतर होंगे। इसलिए, भारत टैक्सी न सिर्फ ड्राइवर, जो अब सारथी है, की आमदनी बेहतर करती है, बल्कि उसकी और उसके परिवार की खुशी भी बढ़ाती है।

सम्मान : सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब ड्राइवर को सम्मान के साथ काम मिलेगा। अब वो इस सहकारी टैक्सी सेवा हेतु बनी सहकारी समिति का स्वयं सदस्य भी होगा। यह मोबिलिटी इकोसिस्टम की रीढ़ ड्राइवर को सम्मान वापस दिलाता है, जिसके वो हकदार हैं।

सुरक्षा : यही नहीं अब भारत टैक्सी से जुड़े सारथियों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, बीमा, सस्ते लोन, सब्सिडी और गिग वर्कर्स के लिए सभी स्कीम जैसे फायदे मिलेंगे।

लाभ में हिस्सेदारी : चूंकि भारत टैक्सी मॉडल में ड्राइवर यानी सारथी अब स्वयं भारत टैक्सी सहकारी संस्था के सदस्य होंगे, उन्हें इसके लाभों में भी बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। ये हिस्सेदारी अमूल मॉडल की तर्ज पर होगी। सर्वविदित है कि अमूल मॉडल में दुग्ध उत्पादक किसानों को अमूल सहकारी संस्था में न केवल दूध का सही मूल्य मिलता है, बल्कि उसके लाभ में भी हिस्सेदारी मिलती है।

यात्रियों को फायदा : अपना मुनाफा ज्यादा से ज्यादा करने के लिए, टैक्सी प्लेटफॉर्म आम तौर पर ज्यादा मांग के नाम पर सर्ज प्राइसिंग करते हैं, जिससे यात्रियों को ज्यादा किराया देना पड़ता है, कभी-कभी तो सामान्य किराए से 2 से 3 गुना ज्यादा। भारत टैक्सी के साथ यह तरीका खत्म हो जाएगा, जिससे यात्रियों को ज्यादा मांग के नाम पर ऊंचा किराया देने से राहत मिल जाएगी।

सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर : भारत टैक्सी ओएनडीसी (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स) पर बनी है, जो कि फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे कोऑपरेशन मंत्रालय की देखरेख में विकसित किया गया है। ओएनडीसी एक खुला, पारदर्शी और एकाधिकार विहीन डिजिटल फ्रेमवर्क है, जो भारत के खुलेपन और निष्पक्षता के सभ्यागत मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है। ओएनडीसी बंद प्लेटफॉर्म के दबदबे को तोड़ता है और छोटे ऑपरेटरों और कोऑपरेटिव के लिए बराबर मौके पक्का करता है। भारत टैक्सी का ओएनडीसी फ्रेमवर्क पर चलाया जाना इस आशा को भी बलवती करता है कि ई-कॉमर्स के अन्य क्षेत्रों में भी सहकारिता के आधार पर ही डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से निजी काम करने वाले लोगों, जैसे छोटे व्यापारियों, रेहड़ी पटरी विक्रेताओं, और बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, एसी मरम्मत करने वालों जैसे अन्य कर्मियों को संगठित कर उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सकता है और उन्हें सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार दिया जा सकता है।

भारत टैक्सी, एक गेम चेंजर : भारत टैक्सी का जीरो कमीशन मॉडल यह सुनिश्चित करेगा कि उबर ओला जैसी कंपनियां भी अपनी कमीशन को कम करें और ड्राइवरों की ज्यादा आमदनी सुनिश्चित करें। यही नहीं भारत टैक्सी का यह मॉडल विश्व का भी मार्ग प्रशस्त कर सकता है कि दूसरे देश भी इस मॉडल को अपनाकर मोबिलिटी सेवाओं में शोषण की समाप्ति कर सकें। कोऑपरेटिव ओनरशिप मॉडल शोषण को रोकता है और लंबे समय तक चलने वाली टिकाऊ व्यवस्था को पक्का करता है। जैसा कि यह योजना है कि भारत टैक्सी को छोटे शहरों, ग्रामीण इलाकों तक ले जाया जाएगा, यह मॉडल कोऑपरेटिव के ड्राइवरों को डिजिटल इकॉनमी में हिस्सा लेने लायक बनाएगा। डेटा या पूंजी के नियंत्रण से अलग यह मॉडल सेवा की गुणवत्ता के आधार पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।

सहकारिता मंत्रालय की भूमिका : अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने आधुनिक डिजिटल प्लेटफार्म में सहकारिता के सिद्धांत को शामिल करने में अहम भूमिका निभाई है। यह पहल सहकारिता को 21वीं सदी के डिजिटल ढांचे में लाती है।

राष्ट्रीय प्रभाव : भारत टैक्सी रोजगार, मोबिलिटी, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। यह एक जीता-जागता उदाहरण है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे देश के हित में काम कर सकता है। जैसे यूपीआई ने भुगतान को बदला, वैसे ही भारत टैक्सी जैसे ओएनडीसी पर आधारित प्लेटफॉर्म सेवा और ई-कॉमर्स को बदल देंगे। हमें यह समझना होगा कि भारत टैक्सी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म नहीं है, यह आर्थिक निष्पक्षता के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन है। यह पहल एक मजबूत, आत्मनिर्भर और बराबरी वाले भारत की भावना को दिखाती है।

सरल नहीं पर प्रभावशाली थे, आदर्शवादी नहीं पर निर्णायक थे अजित पवार

सचिन तोमर

महाराष्ट्र की राजनीति को आज तब गहरा आघात लगा जब उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बारामती में विमान हादसे में निधन हो गया। लैंडिंग के दौरान विमान में आई तकनीकी खराबी के बाद यह दुर्घटना हुई। हादसे की खबर फैलते ही राज्य भर में शोक की लहर दौड़ गई। देखा जाये तो अजित पवार महाराष्ट्र के उन नेताओं में थे जिन्होंने सत्ता के केंद्र में रहते हुए भी जमीन से नाता नहीं तोड़ा। वह भले ही कभी मुख्यमंत्री न बने हों, लेकिन राज्य में सबसे लंबे समय तक उपमुख्यमंत्री रहने का इतिहास उनके नाम दर्ज है। छह बार उपमुख्यमंत्री के रूप में सेवा देने वाले अजित पवार ने अलग-अलग सरकारों में अपनी प्रशासनिक पकड़ और राजनीतिक प्रभाव बनाए रखा। बारामती में अजित पवार की राजनीति का सबसे बड़ा प्रमाण उनका काम खुद था। वह उन गिने चुने नेताओं में थे जिनके लिए अपना खुद का चुनाव प्रचार एक औपचारिकता भर था। विधानसभा चुनावों में वह हमेशा समय पर अपना नामांकन दाखिल करते थे, लेकिन उसके बाद बारामती की गलियों में शायद ही कभी उन्हें प्रचार करते देखा गया। जनता जानती थी कि किसे वोट देना है, इसलिए जनता ही उनका प्रचार करती थी। अजित पवार का भरोसा नारों पर नहीं, काम पर था। इसी आत्मविश्वास के चलते वह बारामती से निश्चिंत रहकर राज्य के दूसरे इलाकों में पार्टी उम्मीदवारों के प्रचार में जुट जाते थे। बारामती उनके लिए सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं था, वह उनका कर्मक्षेत्र था, जहां उन्होंने यह साबित किया कि जब विकास बोलता है तो नेता को खुद बोलने की जरूरत नहीं पड़ती।

अजित पवार ने 1982 में सहकारी क्षेत्र से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। वह चीनी मिल के बोर्ड में चुने गए और यहीं से बारामती की राजनीति में उनकी जड़ें मजबूत होती गईं। 1991 में वह पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने और उसी वर्ष बारामती से लोकसभा सांसद चुने गए। बाद में उन्होंने यह सीट शरद पवार के लिए खाली की। इसके बाद वह बारामती से सात बार विधायक बने। उनके परिवार में पत्नी सुनेत्रा पवार और दो पुत्र जय और पार्थ हैं। सहकार से सत्ता तक का उनका सफर बारामती से शुरू हुआ और वहीं समाप्त हुआ।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को चुनाव आयोग ने पार्टी का मूल नाम और चुनाव चिन्ह सौंपा था। यह गुट भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति के साथ जुड़ा। वहीं उनके चाचा और वरिष्ठ नेता शरद पवार ने अलग रह कर एनसीपी-एससीपी का नेतृत्व संभाला। यह विभाजन महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे भावनात्मक और निर्णायक मोड़ माना गया। दोनों पक्षों का विवाद अदालत के दरवाजे तक पहुँचा लेकिन हाल के दिनों में पवार परिवार एकजुट नजर आ रहा था। हम आपको याद दिला दें कि 2024 के लोकसभा चुनावों में अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ उतार कर पारिवारिक और राजनीतिक रिश्तों में तीखापन ला दिया था, लेकिन समय के साथ उन्होंने यह स्वीकार किया था कि वह फैसला एक भूल था। राजनीति के उस कठोर दौर के बाद हालिया निकाय चुनावों में उन्होंने जिस परिपक्वता का परिचय दिया, वह उनके व्यक्तित्व का दूसरा और अधिक मानवीय पक्ष सामने लाता है। शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन कर दोनों एनसीपी को एक मंच पर लाने की पहल उन्होंने खुद की थी। बहन सुप्रिया के साथ संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में

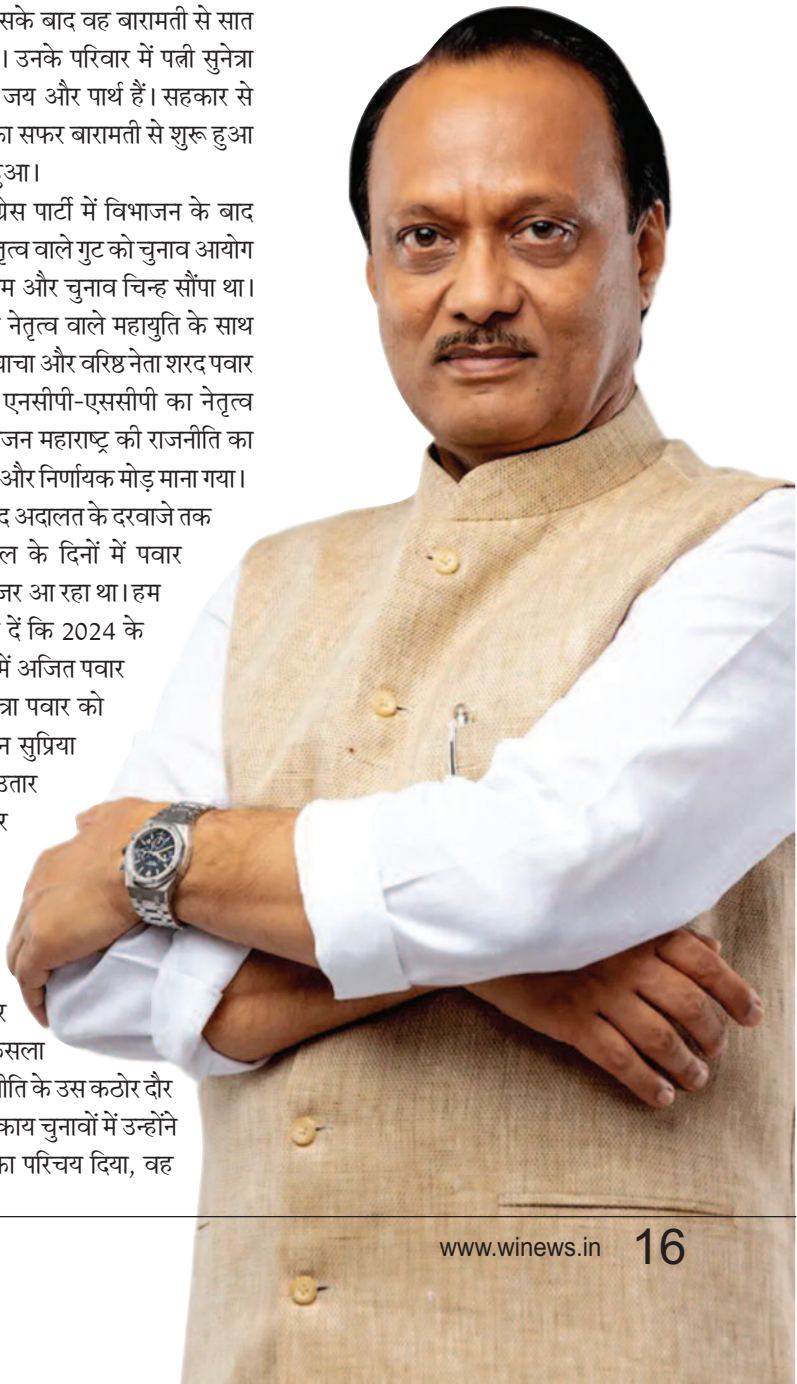

उन्होंने साफ कहा था कि परिवार में कोई मतभेद नहीं हैं और जनता चाहती है कि दोनों दल साथ मिलकर काम करें। यह सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक स्वीकारोक्ति भी थी। देखा जाये तो अपने निधन से पहले अजित पवार कम से कम इतना तो कर ही गए कि उन्होंने परिवार से सुलह कर ली, टूटे रिश्तों को जोड़ दिया और महाराष्ट्र की राजनीति को यह संकेत दे दिया कि टकराव नहीं, संवाद ही आगे का रास्ता है।

अपने लंबे राजनीतिक जीवन में अजित पवार ने पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे जैसे मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। गठबंधनों के बदलते दौर में भी अपनी उपयोगिता और असर बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी रही। अजित पवार चूंकि केंद्र और महाराष्ट्र में सत्तारुढ़ एनडीए के प्रमुख घटक थे इसलिए उनका निधन बड़ा राजनीतिक नुकसान भी है। देखा जाये तो अजित पवार का जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं है, यह उस राजनीतिक शैली का अंत है जो चुपचाप काम करने में यकीन रखती थी। उनकी राजनीति प्रशासनिक पकड़, आंकड़ों की समझ और सत्ता की नस पहचानने की कला से बनी थी। शरद पवार की विशाल छाया में राजनीति शुरू करना आसान था, लेकिन उस छाया से निकलकर अपनी पहचान बनाना बेहद कठिन था। अजित पवार ने यह कठिन रास्ता चुना। वह हमेशा इस द्वंद्व में रहे कि उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाए या एक स्वतंत्र नेता के रूप में। शायद इसी बेचैनी ने उन्हें बार-बार जोखिम लेने के लिए प्रेरित किया।

2023 की वह सुबह भारतीय राजनीति के सबसे नाटकीय क्षणों में गिनी जाती है जब उन्होंने अचानक सत्ता का समीकरण बदल दिया था। उनकी काफी आलोचना हुई, अविश्वास भी पैदा हुआ, लेकिन यह भी सच है कि उसी क्षण ने उन्हें निर्णायक नेता के रूप में स्थापित किया। बाद में चुनाव आयोग का फैसला उनके पक्ष में जाना इस बात का संकेत था कि राजनीति में साहस कई बार वैधता भी दिला देता है। अजित पवार की राजनीति नैतिकता के आदर्शों की किताब से कम और यथार्थ की जमीन से ज्यादा निकली थी। यही कारण है कि वह आलोचकों के निशाने पर भी रहे और समर्थकों के भरोसे का केंद्र भी बने। वह जानते थे कि सत्ता स्थायी नहीं होती, लेकिन प्रभाव बनाया जा सकता है। उन्होंने वही किया। विभिन्न लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान मैंने खुद देखा कि वह समर्थकों और कार्यकताओं के कितने करीब रहते हैं और सबकी बातें ध्यान से सुनते हैं। यही कारण था कि बारामती में खासतौर पर अजित दादा के नाम का बोलबाला हर जगह देखने को मिलता है।

आज जब उनका जाना अचानक और असमय हुआ है, महाराष्ट्र की राजनीति एक खालीपन महसूस कर रही है। यह खालीपन सिर्फ पद का नहीं, उस अनुभव का है जो दशकों में गढ़ा जाता है। आने वाले समय में यह सवाल और तीखा होगा कि क्या कोई नेता सहकार से सत्ता तक के इस रास्ते को फिर उसी धार और दृढ़ता से तय कर पाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि अजित पवार की विरासत विरोधाभासों से भरी रही, लेकिन शायद यही उनकी सच्ची पहचान भी है। वह सरल नहीं थे, पर प्रभावशाली थे। वह आदर्शवादी नहीं थे, पर निर्णायक थे। और इसी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में उनका नाम लंबे समय तक याद रखा जाएगा।

छह बार उपमुख्यमंत्री के रूप में सेवा देने वाले अजित पवार ने अलग-अलग सरकारों में अपनी प्रशासनिक पकड़ और राजनीतिक प्रभाव बनाए रखा। बारामती में अजित पवार की राजनीति का सबसे बड़ा प्रमाण उनका काम खुद था। वह उन गिने चुने नेताओं में थे जिनके लिए अपना खुद का चुनाव प्रचार एक औपचारिकता भर था।

भारत के लिए पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक है चीन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगातार अपमानजनक व्यवहार और धमकी भरे बयान झेलने के बाद अब भारत की नरेन्द्र मोदी सरकार और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर चीन की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। चीन के नेताओं से अतीत में किसी मौके पर कांग्रेस और वामपंथी दलों के नेताओं की मुलाकातों को लेकर उन्हें अक्सर 'चीन का एजेंट' और 'देशद्रोही' तक करार देते रहने वाली भाजपा और उसके मार्गदर्शक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं ने हाल ही में अपने दिल्ली स्थित मुख्यालय में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से लंबी मुलाकात की है। हैरानी की बात है कि 12 जनवरी को यह मुलाकात हुई, ठीक उसी दिन चीन ने जम्मू-कश्मीर में स्थित शक्सगाम घाटी पर अपने क्षेत्रीय दावे को दोहराते हुए कहा कि -'इस घाटी में जारी चीन की बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं पूरी

ब्रिज पंवार

तरह वैध हैं।'

इस घटनाक्रम से एक बार फिर इस बात की तसदीक होती है कि भारत की सुरक्षा के लिए चीन ही सबसे बड़ा खतरा है और भाजपा व उसकी सरकार अपनी घरेलू राजनीति और दिशाहीन विदेश नीति के चलते चीन को खतरा मानने के लिए तैयार नहीं है। यह स्थिति तब है जब पिछले एक दशक के दौरान ही चीन ने कभी लद्दाख तो कभी सिक्किम और कभी अरुणाचल प्रदेश पर न सिर्फ अपना दावा जताया है बल्कि उन इलाकों के नाम बदल कर वहां अपनी सैन्य चौकियां भी कायम की हैं। इतना ही नहीं, कुछ महीनों पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ हुए भारत के सैन्य टकराव में भी चीन ने खुल कर पाकिस्तान की मदद की थी।

चीन का यह रवैया देश के रक्षा मंत्री रहे दिवंगत समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडीस की उस चेतावनी की याद दिलाता है जिसमें उन्होंने चीन को 'भारत का दुश्मन नंबर-1इ करार दिया था। यह बात करीब ढाई दशक पुरानी है। तब भी केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी उसका नेतृत्व कर रहे थे।

मई, 1998 में वाजपेयी सरकार ने पोखरण-2 परमाणु परीक्षण किया था, जिसकी वजह से अमेरिका ने भारत को काली सूची में डाल दिया था। उस विस्फोट के बाद ही एनडीए सरकार के रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडीस ने अपने एक चौंकाने वाले बयान में सामरिक दृष्टि से चीन को भारत का दुश्मन नंबर एक करार दिया था। जार्ज का यह बयान निश्चित ही किन्हीं ठोस सूचनाओं पर आधारित रहा होगा, जो रक्षा मंत्री

होने के नाते उन्हें हासिल हुई होगी। लेकिन उनका यह बयान कई लोगों को रास नहीं आया था। उनके ही कई साथी मंत्रियों ने उनके इस बयान पर नाक-भौंह सिकोड़ी थी। आज की तरह उस समय भी कांग्रेस विपक्ष में थी और उसे ही नहीं, बल्कि एनडीए की नेतृत्वकारी भाजपा और आरएसएस को भी जॉर्ज का यह बयान नागवार गुजरा था। वामपंथी दलों को तो स्वाभाविक रूप से जॉर्ज की यह साफगोई नहीं ही सुहा सकती थी, सो नहीं सुहाई थी।

यह दिलचस्प था कि संघ और वामपंथियों के रूप में दो परस्पर विरोधी विचारधारा वाली ताकतें इस मुद्दे पर एक सुर में बोल रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे दोनों ने अलग-अलग कारणों से 1942 में 'भारत छोड़ो' आंदोलन का विरोध किया था। जॉर्ज के इस बयान के विरोध के पीछे भी दोनों की प्रेरणाएं अलग-अलग थीं। संघी कुनबा जहां अपनी चिर-परिचित मुस्लिम विरोधी ग्रंथि के चलते पाकिस्तान के अलावा किसी और देश को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं मान सकता था, वहीं वामपंथी दल चीन के साथ अपने वैचारिक बिरादराना रिश्तों के चलते जॉर्ज के बयान को खारिज कर रहे थे। कई तथाकथित रक्षा विशेषज्ञों और विश्लेषकों समेत मीडिया के एक बड़े हिस्से ने भी इसके लिए जॉर्ज की काफी लानत-मलानत की थी।

जॉर्ज अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन चीन को लेकर उनका आकलन समय की कसौटी पर बीते ढाई दशकों के दौरान और खास कर पिछले एक दशक में ही कई बार सही साबित हुआ है। इस समय भी चीन का रवैया जॉर्ज के कहे की तसदीक कर रहा है। वैसे न तो चीनी खतरा भारत के लिए नया है और न ही उससे आगाह करने वाले जॉर्ज अकेले राजनेता रहे। 2017 में चीन की सेना जब डोकलाम में कई किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी, तब संयुक्त मोर्चा सरकार में रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने भी अपने अनुभव के आधार पर चीनी खतरे के प्रति सरकार को आगाह किया था। इस मसले पर लोकसभा में बहस के दौरान मुलायम सिंह ने दो टूक कहा था कि भारत की सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा चीन से ही है और सरकार उसे हल्के में न ले। दरअसल, चीन ने जब तिब्बत पर कब्जा किया था, तभी से वह भारत के लिए खतरा बना हुआ है। देश को सबसे पहले इस खतरे की चेतावनी राममनोहर लोहिया ने दी थी। तिब्बत पर चीनी हमले को उन्होंने 'शिशु हत्याइ करार देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि वे तिब्बत पर चीनी कब्जे को मान्यता न दे, लेकिन नेहरू ने लोहिया की सलाह मानने के बजाय चीनी नेता चाऊ एन लाई से अपनी दोस्ती को तरजीह देते हुए तिब्बत को चीन का अविभाज्य अंग मानने में जरा भी देरी नहीं की। यह वह समय था जब भारत को आजाद हुए महज 11 वर्ष हुए थे और माओ की सरपरस्ती में चीन की लाल क्रांति भी नौ साल पुरानी ही थी। हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू तब समाजवादी भारत का सपना देख रहे थे जिसमें चीन से युद्ध की कोई जगह नहीं थी। उधर माओ को पूरी दुनिया के सामने जाहिर करना था कि साम्यवादी कट्टरता के मामले में वे लेनिन और स्टालिन से भी आगे हैं। तिब्बत पर कब्जा उनके इसी मंसूबे का नतीजा था।

इतना सब होने के बावजूद लगभग एक दशक तक भारत-चीन के बीच राजनयिक रिश्ते अच्छे रहे। लेकिन 1960 का दशक शुरू होते-होते चीनी नेतृत्व के विस्तारवादी इरादों ने अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी थी और भारत के साथ उसके रिश्ते शीतकाल में प्रवेश कर गए। तिब्बत जब तक आजाद देश था, तब तक चीन और भारत के बीच कोई सीमा विवाद नहीं था, क्योंकि तब भारतीय सीमाएं सिर्फ तिब्बत से मिलती थीं। मगर चीन द्वारा तिब्बत को हथिया लिए जाने के बाद वहां तैनात चीनी सेना भारतीय सीमा का अतिक्रमण करने लगी। उन्हीं दिनों चीन की ओर से जारी किए गए नक्शों से भारत को पहली बार झटका लगा। उन नक्शों में भारत के सीमावर्ती इलाकों के साथ ही भूटान के भी कुछ हिस्से को चीन का भू-भाग बताया गया था। चूंकि इसी दौरान भारत यात्रा पर आए चाऊ एन लाई नई दिल्ली में पंडित नेहरू के साथ 'हिंदी-चीनी, भाई-भाई' का नारा लगाते हुए शांति के कबूतर उड़ा चुके थे, भावुक भारतीय नेतृत्व को भरोसा था कि सीमा विवाद बातचीत के जरिए निपट जाएगा। 1962 का अक्टूबर महीना भारतीय नेतृत्व के भावुक सपनों के ध्वस्त होने का रहा, जब चीन की सेना ने पूरी तैयारी के साथ भारत पर हमला बोल दिया। हमारी सेना के पास मौजूं सैन्य साज-ओ-सामान का अभाव था, लिहाजा भारत को पराजय का कड़ुवा घूंट पीना पड़ा और चीन ने हमारी हजारों वर्ग मील जमीन हथिया ली। इस तरह तिब्बत पर चीनी कब्जे के वक्त लोहिया द्वारा जताई गई आशंका सही साबित हुई।

चीन से मिले इस गहरे जख्म के बाद दोनों देशों के रिश्तों पर लगभग डेढ़ दशकों तक बर्फ जमी रही, जो 1970 के दशक के उत्तरार्ध में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनने पर कुछ हद तक हटी। दोनों देशों के बीच एक बार फिर राजनयिक रिश्तों की बहाली हुई। तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते भी बने हुए हैं और पिछले दो दशकों के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार में 25 गुना से भी ज्यादा इजाफा हुआ है।

अब वह 100 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इस सबके बावजूद चीन के विस्तारवादी इरादों में कोई तब्दीली नहीं आई है। उसके इस रवैये की सबसे बड़ी वजह भारत के राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी है, जो कभी भारतीय सीमा में चीन की घुसपैठ होने से इनकार कर देता है तो कभी कहता है कि चीन के मुकाबले हमारी अर्थव्यवस्था छोटी है, इसलिए उससे नहीं लड़ा जा सकता। अलबत्ता वह कभी-कभी चीनी सामान का बहिष्कार करने और आत्मनिर्भर बनने जैसे शगूफे भी छोड़ता रहता है, जिसे चीनी नेतृत्व खूब समझता है। इस समय भी यही सब हो रहा है।

डराने लगी है ऑनलाइन गेमिंग की लत एवं आभासी दुनिया

ऑनलाइन गेमिंग की लत एवं आभासी दुनिया कितनी भयावह एवं घातक हो सकती है, इसकी एक ही दिन में दो अलग-अलग जगह घटी घटनाओं ने न केवल झकझोरा है, बल्कि यह हमारे समय, हमारी सामाजिक संरचना और हमारी सामूहिक असावधानी पर लगा हुआ एक गहरा प्रश्नचिह्न बना है। धीरे-धीरे किशोरवय को अपने चपेट में लेने वाली यह प्रवृत्ति कितनी हृदयविदारक हो सकती है, उसका उदाहरण बुधवार को घटी ये दो भयावह घटनाएं हैं। एक हृदयविदारक घटना में गाजियाबाद की तीन अल्पवयस्क बहनों ने नौवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 12, 14 और 16 साल की तीन सुकोमल बहनें असमय काल-कवलित हो गईं। ऑनलाइन कोरियन गेम की दीवानी बहनें कोरिया में जाकर बसने और वहीं नया जीवन शुरू करने का सपना देखती थीं। घर वालों ने जब उनकी ऑनलाइन सनक से परेशान होकर उनसे मोबाइल छीन लिए, तो वे तनाव व

प्रवीण सिंह कुशवाहा

अवसाद में घिर गई। फिर तीनों बहनों ने नौवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। ऐसी ही घटना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी घटी जहां एक पंद्रह वर्षीय किशोर ने ऑनलाइन गेम के अपने एक विदेशी साथी के बिछुड़ने के गम में घर में आत्महत्या कर ली। किशोर दसवीं का छात्र था। इन घटनाओं ने समाज को स्तब्ध ही नहीं किया, बल्कि भीतर तक गहरा घाव दिया है। यह कोई आकस्मिक या अलग-थलग घटना नहीं है। इससे पहले झाबुआ, भोपाल और देश के अन्य हिस्सों में सामने आई ऐसी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि आभासी दुनिया किस तरह वास्तविक जीवन पर हावी होती जा रही है और हम अनजाने में एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां संवेदनाएं, संवाद और जीवन-मूल्य स्क्रीन के पीछे दम तोड़ते जा रहे हैं।

ऑनलाइन गेमिंग अपने आप में अपराध नहीं है, न ही तकनीक शत्रु है, लेकिन जब यह बच्चों और किशोरों के लिए लत बन जाए, तो यह एक धीमा जहर बन जाती है। यह जहर चुपचाप बच्चों के मस्तिष्क में प्रवेश करता है, उनकी सोच, उनकी भावनात्मक संरचना और उनके निर्णय लेने की क्षमता को विकृत करता है। गेमिंग की दुनिया बच्चों को तात्कालिक रोमांच, आभासी जीत और काल्पनिक पहचान देती है, लेकिन धीरे-धीरे वही दुनिया उन्हें वास्तविक जीवन से काट देती है। परिवार, मित्र, पढ़ाई, प्रकृति, खेल और संवाद-सब कुछ पीछे छूटने लगता है। गाजियाबाद की तीनों बहनों का यह कदम इसी कटाव का चरम और भयावह परिणाम है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अत्यधिक ऑनलाइन गेमिंग बच्चों के मस्तिष्क में आवेग नियंत्रण को कमजोर करती है। जोखिम का आकलन करने की क्षमता घटती है और भावनात्मक अस्थिरता बढ़ती है। हार, असफलता या गेम से

वंचित किए जाने की स्थिति में अवसाद, क्रोध और निराशा गहराने लगती है। कई बार बच्चे आत्महत्या जैसे चरम कदम को भी एक 'गेम ओवर' की तरह देखने लगते हैं। यह सोच अपने आप में अत्यंत खतरनाक है। आत्महत्या की प्रवृत्ति का बढ़ना केवल मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक चुनौती है, जो हमारी परवरिश, हमारी प्राथमिकताओं और हमारी नीतियों पर सवाल उठाती है।

आज के परिवारों में माता-पिता की व्यस्तता, एकल परिवारों की बढ़ती संख्या और संवाद की कमी ने बच्चों को अकेलेपन की ओर धकेला है। स्मार्टफोन कई घरों में बच्चों की चुप्पी खरीदने का सबसे आसान साधन बन गया है। रोता बच्चा हो, जिद करता बच्चा हो या समय न देने की मजबूरी- मोबाइल फोन एक त्वरित समाधान बन चुका है। लेकिन यही समाधान आगे चलकर सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। हम यह भूल जाते हैं कि बच्चा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मार्गदर्शन, स्नेह और समय चाहता है। जब यह सब उसे स्क्रीन से मिलने लगता है, तो परिवार की भूमिका स्वतः कमजोर हो जाती है।

यह भी एक कठोर सत्य है कि कई माता-पिता स्वयं डिजिटल लत के शिकार हैं। ऐसे में बच्चों को रोकने का नैतिक और व्यवहारिक अधिकार भी कमजोर पड़ जाता है। हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वे मोबाइल कम चलाएं, जबकि हमारे अपने हाथों में हर समय फोन रहता है। यह दोहरा व्यवहार बच्चों के मन में भ्रम और विद्रोह दोनों पैदा करता है। इसलिए समस्या का समाधान केवल बच्चों पर नियंत्रण नहीं, बल्कि पूरे पारिवारिक वातावरण में संतुलन लाने से जुड़ा है।

सरकार और समाज की भूमिका भी इस संकट में कम महत्वपूर्ण नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके सामाजिक प्रभावों पर पर्याप्त नियंत्रण और निगरानी का अभाव है। कई गेम्स में हिंसा, आक्रामकता और जोखिम भरे व्यवहार को सामान्य और रोमांचक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बच्चों के लिए आयु-उपयुक्त सामग्री, समय-सीमा और चेतावनी संकेतों को सख्ती से लागू करना अब विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन चुका है। सरकार को चाहिए कि वह ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल कंटेंट के लिए स्पष्ट और कठोर नियामक ढाँचा विकसित करे, जिसमें बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि हो। विद्यालयों की भूमिका भी अत्यंत

निशिका (16 साल) | **प्राची** (14 साल) | **पाखी** (12 साल)

महत्वपूर्ण है। शिक्षा केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रह सकती। डिजिटल साक्षरता, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन-कौशल को शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए। बच्चों को यह सिखाना आवश्यक है कि तकनीक का उपयोग कैसे किया जाए, न कि तकनीक के गुलाम कैसे बना जाए। शिक्षकों को भी बच्चों के व्यवहार में होने वाले बदलावों, अकेलेपन, चिड़चिड़ेपन और अचानक गिरते शैक्षणिक प्रदर्शन जैसे संकेतों को गंभीरता से लेना होगा।

मनोवैज्ञानिक सहायता को लेकर समाज में जो झिझक और संकोच है, उसे भी तोड़ना होगा। मानसिक स्वास्थ्य को कमजोरी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। यदि किसी बच्चे में अवसाद, अत्यधिक चुप्पी, आक्रामकता या आत्मघाती विचारों के संकेत दिखें, तो समय रहते विशेषज्ञ की मदद लेना अत्यंत आवश्यक है। देर करना कई बार अपूरणीय क्षति में बदल जाता है। निस्संदेह, ये आत्मघात की घटनाएं, ऑनलाइन गतिविधियों के अतिरेक से मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक प्रभाव को लेकर गंभीर सवालों को जन्म देती हैं। निश्चित रूप से आत्मघात की ये घटनाएं हमारे नीति-नियंताओं और अभिभावकों को आसन्न संकट के प्रति सचेत करती हैं।

दरअसल,ये दुखद घटनाएं एक घातक प्रवृत्ति को ही उजागर करती हैं कि गेमिंग और डिजिटल संपर्क लाखों युवाओं को आभासी समुदाय और मनोरंजन तो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भावनात्मक कमजोरियों,सामाजिक अलगाव और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों की पूर्ति न होने जैसी समस्याओं को भी जन्म दे सकते हैं। हालांकि, वहीं दूसरी ओर समाज विज्ञानी इस बात पर भी बल देते हैं कि केवल गेमिंग या ऑनलाइन मित्रता ही आत्महत्या का कारण नहीं बन सकती हैं। निस्संदेह, आत्महत्या एक जटिल और बहुआयामी घटना है। लेकिन समस्याग्रस्त डिजिटल जुड़ाव, विशेष रूप से जब यह ऑफलाइन जीवन से अलगाव, बाधित शिक्षा और तीव्र भावनात्मक तनाव के साथ होता है तो संवेदनशील युवा मन में परेशानी को और बढ़ा सकता है।

गाजियाबाद की यह घटना हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि हमने बच्चों के लिए कैसी दुनिया बनाई है। क्या हमने उन्हें संवाद दिया, या केवल उपकरण थमा दिए? क्या हमने उन्हें संस्कार दिए, या केवल सुविधाएं? क्या हमने उन्हें सुनने का समय दिया, या केवल आदेश? यह आत्ममंथन केवल पीड़ित परिवारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पूरे समाज को अपने भीतर झांककर देखना होगा। यह घटना एक चेतावनी है, एक टर्निंग पॉइंट है। यदि अब भी हमने इसे एक सामान्य समाचार की तरह भुला दिया, तो भविष्य में ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी। समाज को, सरकार को और प्रत्येक परिवार को मिलकर कड़े और संवेदनशील कदम उठाने होंगे। तकनीक को नकारना समाधान नहीं है, लेकिन उसे बिना नियंत्रण स्वीकार करना भी आत्मघाती है। संतुलन, संवाद और सहभागिता ही बच्चों की सुरक्षा का वास्तविक आधार हैं। गाजियाबाद की तीनों बहनों हो या कूल्लु के किशोर की असमय मृत्यु हमें यह याद दिलाती है कि अगर हमने अभी नहीं संभला, तो यह इलेक्ट्रॉनिक खतरा हमारे घरों, हमारे भविष्य और हमारी संवेदनाओं को निगलता चला जाएगा। यह समय है जागने का, सोचने का और ठोस कदम उठाने का-क्योंकि यह सवाल केवल तकनीक का नहीं, बल्कि जीवन का है।

गड्ढों वाली व्यवस्था और खतरे में पड़ता जीवन

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदा गया गड्ढा हो या नोएडा की किसी एजेंसी का, जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया हर बार एक जैसी रहती है। अफसर निलंबित कर दिए जाते हैं, जांच समितियां बना दी जाती हैं, 24 या 48 घंटे में रिपोर्ट देने की घोषणा होती है और कुछ समय बाद वही फाइलें धूल फांकने लगती हैं।

संजय बैंसला

गड्ढों में गिरी व्यवस्था में समाप्त होता जीवन आज के भारत की एक ऐसी विडंबना बन चुका है, जिसे देखकर मन भीतर तक सिहर उठता है। नोएडा में कार सवार युवा इंजीनियर की गड्ढे में गिरकर मौत का दर्द अभी समाज के मन से उतरा भी नहीं था कि दिल्ली में बाइक सवार युवक की जान एक खुले गड्ढे ने लील ली। दोनों घटनाओं में समानता यह है कि गड्ढे प्रशासन द्वारा विकास या मरम्मत के नाम पर खोदे गए थे और दोनों जगह न तो कोई बैरिकेडिंग थी, न चेतावनी बोर्ड, न रोशनी की व्यवस्था। मानो व्यवस्था ने पहले गड्ढा खोदा और फिर निश्चिंत होकर वहां से हट गई कि अब जो होगा, वह नागरिक की किस्मत है। यही वह सोच है जो किसी भी समाज को भीतर से खोखला कर देती है।

प्रश्न यह नहीं है कि गड्ढे क्यों खोदे गए, प्रश्न यह है कि गड्ढे खोदकर लोगों को मौत के मुंह में धकेलने का अधिकार प्रशासन को किसने दिया। क्या विकास का अर्थ यह हो गया है कि सड़कों पर चलते हुए हर नागरिक अपनी जान हथेली पर रखे। क्या शहरों की चमक-दमक और बड़े-बड़े दावों के बीच आम आदमी का जीवन इतना सस्ता हो गया है कि उसकी मौत पर सिर्फ एक खबर छप जाए, दो दिन बहस हो और फिर सब कुछ सामान्य हो जाए। यह सामान्य हो जाना ही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब मौतें सामान्य लगने लगें, तब व्यवस्था की संवेदनशीलता मर चुकी होती है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदा गया गड्ढा हो या नोएडा की किसी एजेंसी का, जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया हर बार एक जैसी रहती है। अफसर निलंबित कर दिए जाते हैं, जांच समितियां बना दी जाती हैं, 24 या 48 घंटे में रिपोर्ट देने की घोषणा होती है और कुछ समय बाद वही फाइलें धूल फांकने लगती हैं। निलंबन और जांच अब समाधान

नहीं, बल्कि एक औपचारिक रस्म बन गई है। सवाल यह है कि क्या निलंबन से मरे हुए बेटे लौट आते हैं, क्या जांच समितियों से टूटे हुए परिवार फिर से जुड़ जाते हैं। जब तक जवाबदेही केवल कागजों पर सिमटी रहेगी, तब तक गड्ढों में गिरती जिंदगियां यूं ही व्यवस्था का शिकार बनती रहेंगी।

इस पूरी तस्वीर का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं कम से कम चर्चा में तो आती हैं, मीडिया सवाल तो उठाता है, लेकिन छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में यही गड्ढे रोज जिंदगियां निगल रहे हैं और खबर तक नहीं बनते। वहां न कैमरा पहुंचता है, न कोई प्रतिनिधि, न कोई जांच समिति। वहां मौतें सिर्फ परिवारों की निजी त्रासदी बनकर रह जाती हैं। क्या नागरिक का मूल्य शहर के आकार से तय होगा। क्या महानगरों का नागरिक ज्यादा कीमती है और छोटे शहरों का नागरिक सस्ता। यह असमानता केवल संसाधनों की नहीं, बल्कि संवेदनाओं की भी है।

हम एक ओर विकसित भारत, सशक्त भारत, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात करते हैं, दूसरी ओर हमारी सड़कों पर खुले गड्ढे हमें आईना दिखाते हैं। विकास की रफ्तार तेज हो सकती है, लेकिन यदि उस रफ्तार में सुरक्षा, जिम्मेदारी और मानवीय संवेदना नहीं जुड़ी, तो वह रफ्तार विनाश की ओर ही ले जाएगी। यह विडंबना ही है कि हम स्मार्ट सिटी की बातें करते हैं, लेकिन स्मार्ट बैरिकेडिंग, स्मार्ट चेतावनी और स्मार्ट जिम्मेदारी पर बात करना भूल जाते हैं। तकनीक के युग में भी एक साधारण चेतावनी बोर्ड लगाना हमारे तंत्र को याद नहीं रहता।

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदा गया गड्ढा हो या नोएडा की किसी एजेंसी का, जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया हर बार एक जैसी रहती है। अफसर निलंबित कर दिए जाते हैं, जांच समितियां बना दी जाती हैं, 24 या 48 घंटे में रिपोर्ट देने की घोषणा होती है और कुछ समय बाद वही फाइलें धूल फांकने लगती हैं। निलंबन और जांच अब समाधान नहीं, बल्कि एक औपचारिक रस्म बन गई है।

दरअसल समस्या केवल लापरवाही की नहीं, बल्कि उस मानसिकता की है जिसमें नागरिक को एक आंकड़ा समझ लिया गया है। फाइलों में वह एक केस नंबर है, सड़क पर वह एक बाधा और हादसे के बाद वह एक आंकड़ा। जब तक प्रशासन और शासन की दृष्टि में नागरिक का जीवन सर्वोपरि मूल्य नहीं बनेगा, तब तक हर नया गड्ढा एक नई मौत की संभावना बनकर खड़ा रहेगा। सवाल यह भी है कि क्या इन गड्ढों के लिए कभी उच्च स्तर पर नैतिक जिम्मेदारी तय होगी। क्या कभी ऐसा होगा कि किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति से पूछा जाए कि आपके विभाग की लापरवाही से एक जान गई, इसलिए आप पद पर बने रहने के नैतिक अधिकारी नहीं हैं।

भ्रष्ट शासन के समाप्त होने की बड़ी-बड़ी घोषणाएं हर चुनाव में सुनाई देती हैं। पोस्टर बदलते हैं, नारे बदलते हैं, लेकिन जमीन पर गड्ढे वैसे ही रहते हैं। यदि भ्रष्टाचार केवल रिश्वत लेने तक सीमित होता तो शायद उसे पहचानना आसान होता, लेकिन यह जो संवेदनहीन भ्रष्टाचार है, जहां नियमों की अनदेखी, सुरक्षा मानकों की उपेक्षा और समय पर काम पूरा न करना शामिल है, यह ज्यादा खतरनाक है। इसमें पैसा दिखता नहीं, लेकिन इसकी कीमत किसी की जान से चुकानी पड़ती है।

आज जब हम अमृत काल और शताब्दी वर्ष में नए भारत की कल्पना कर रहे हैं, तब यह प्रश्न और भी तीखा हो जाता है कि क्या खुले गड्ढों वाला देश महान बन सकता है। क्या वह देश विकसित कहलाने योग्य है, जहां नागरिक रात को सड़क पर निकलते समय यह दुआ करे कि कहीं कोई गड्ढा उसकी जिंदगी न छीन ले। विकास केवल पुलों, सड़कों और इमारतों से नहीं मापा जाता, बल्कि इस बात से मापा जाता है कि आम आदमी खुद को कितना सुरक्षित महसूस करता है। यदि सुरक्षा का भरोसा नहीं, तो सारी उपलब्धियां खोखली हैं।

गड्ढों में गिरी व्यवस्था केवल सड़कों की समस्या नहीं है, यह हमारे शासन तंत्र की नैतिक गिरावट का प्रतीक है। यह उस दूरी को दिखाता है जो सत्ता और नागरिक के बीच बढ़ती जा रही है। जब तक हर गड्ढे को सिर्फ तकनीकी खामी समझा जाएगा और हर मौत को दुर्भाग्य कहकर टाल दिया जाएगा, तब तक यह सिलसिला रुकेगा नहीं। जरूरत इस बात की है कि हर गड्ढा एक सवाल बने, हर मौत एक चेतावनी और हर लापरवाही एक अपराध मानी जाए।

कब वे गड्ढे भरेंगे, कब व्यवस्था की दरारें बंद होंगी और कब विकास की दौड़ में भागता देश यह भरोसा पाएगा कि वह सुरक्षित हाथों में है, यह सवाल आज हर नागरिक के मन में है। शायद उस दिन हम सचमुच कह सकेंगे कि हमारा देश महान बनने की राह पर है। अभी तो लगता है कि हम महान नहीं, बल्कि परेशान हैं और यह परेशानी सिर्फ गड्ढों की नहीं, गड्ढों में गिरती संवेदनाओं की है।

भारत के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है बजट

रवि जैन

भारत की वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने भारतीय संसद में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया। इस बजट में की गई घोषणाओं के माध्यम से वैश्विक स्तर पर घटित हो रही उथल पुथल से भारत को बचाने की पुरजोर कोशिश की गई दिखती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा अपने द्वितीय कार्यकाल में वर्ष 2025 के दौरान पूरे वर्षभर लगातार कई देशों के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर टैरिफ की घोषणाएं की जाती रहीं एवं इसके विरोध स्वरूप कुछ देशों ने अमरीका से इन देशों को होने वाले निर्यात पर प्रतिकारी टैरिफ लगाने की घोषणाएं की जाती रहीं। चीन ने तो प्रतिशोध में अमेरिका को दुर्लभ खनिज पदार्थों की आपूर्ति ही रोक दी थी। हालांकि इसके पूर्व अमेरिका ने भी चीन को सेमीकंडक्टर एवं चिप्स की आपूर्ति को प्रभावित करने का प्रयास किया था। कुल मिलाकर, कुछ देश तो आपस में विभिन्न वस्तुओं के आयात एवं निर्यात को रोकने के प्रयत्न करते रहे। इन सभी घोषणाओं से वैश्विक स्तर पर विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में माहौल विपरीत रूप से प्रभावित होता रहा। ट्रम्प प्रशासन ने भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न वस्तुओं के निर्यात पर भी 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है, जो अमेरिका द्वारा विभिन्न देशों से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर लगाए गए टैरिफ में संभवतः आज अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक है।

इस वित्तीय वर्ष के बजट में तीन कर्तव्यों को ध्यान में रखा गया है। (1) विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हुए भारत की आर्थिक विकास दर को और अधिक तेज किया जाय ताकि भारत को वैश्विक स्तर पर चल रही उथल पुथल से बचाया जा सके; (2) भारतीय युवाओं में कौशल का विकास करना ताकि तकनीकी क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर हो रहे परिवर्तनों के लिए वे अपने आप को तैयार कर सकें; (3) देश में समावेशी विकास हो सके एवं भारत के संसाधनों का उपयोग समस्त नागरिकों की भलाई में किया जा सके और कोई भी नागरिक, नगर एवं राज्य आर्थिक विकास की धारा से बाहर नहीं रहे।

वैश्विक स्तर पर उक्त वर्णित परिस्थितियों के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी रही। परंतु, भारत की विकास दर की इस गति को आगामी वर्षों में भी बनाए रखने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27

के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। भारत आज दुर्लभ खनिज पदार्थों तथा सेमीकंडक्टर एवं चिप्स का भारी मात्रा आयात करता है। चिप्स को तो आज के उत्पादों के निर्माण में तेल की भूमिका के रूप में देखा जा रहा है। इन दोनों पदार्थों पर चीन एवं अमेरिका का लगभग पूर्णतः एकाधिकार है। भारत अपने आप को इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, इस दृष्टि से बजट में भारत में ही दुर्लभ खनिज पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ओड़िसा, केरल, तमिलनाडु एवं आन्ध्रप्रदेश स्थित खदानों में से कच्चे माल को निकालकर इसे संसाधित करते हुए भारत में ही दुर्लभ खनिज पदार्थों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट में उक्त चारों राज्यों में एक कोरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। इसी प्रकार, भारत में ही सेमीकंडक्टर एवं चिप्स के निर्माण हेतु विनिर्माण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए बजट में कई उपायों की घोषणा की गई है एवं इस हेतु 40,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही, इसके लिए बजट में सेमीकंडकर मिशन 2.0 को लागू करने की भी घोषणा की गई है। इससे कम्पनियों को भारत में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विनिर्माण इकाईयों को स्थापित करने का प्रोत्साहन मिलेगा।

वैश्विक स्तर पर उक्त वर्णित परिस्थितियों के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी रही। परंतु, भारत की विकास दर की इस गति को आगामी वर्षों में भी बनाए रखने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है।

हाल ही में भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते सम्पन्न किए हैं, इन समझौतों में 27 विकसित देशों के समूह, यूरोपीयन यूनियन से किया गया मुक्त व्यापार समझौता भी शामिल है। इसे 'मदर आफ ऑल डील्स' कहा जा रहा है क्योंकि यह समझौता 28 देशों (27+1) के बीच एक साथ किया गया सबसे बड़ा समझौता है। इन मुक्त व्यापार समझौतों से भारत में वस्त्र एवं परिधान उद्योग, समुद्रीय पदार्थ उद्योग, चमड़ा उद्योग, खिलौना उद्योग एवं जेम्स एवं ज्वेलरी उद्योग, आदि को सबसे अधिक लाभ होने जा रहा है। इन उद्योगों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम भारी मात्रा में कार्यरत हैं। भारत में उक्त वर्णित पदार्थों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को रियायतें देने का प्रयास किया गया है ताकि उक्त वर्णित उत्पादों की मांग में होने वाली वृद्धि को पूर्ण किया जा सके। इस उद्देश्य हेतु 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई फंड भी बनाया गया है। टेक्स्टायल उद्योग को भी विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि भारत में निर्मित वस्त्र एवं परिधानों को विश्व के पटल पर रखा जा सके। साथ ही, बायोफार्मा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड की व्यवस्था, बायोफार्मा शक्ति के रूप में, इस बजट में की गई है। इससे भारतीय दवा उद्योग को विश्व के मानचित्र पर और आगे ले जाने में सहायता मिलेगी।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में विकसित आधारभूत संरचना की अहम भूमिका रहती है। इस बजट के माध्यम से भारत में आधारभूत संरचना को विकसित करने के उद्देश्य से पूंजीगत खर्चों में भारी भरकम वृद्धि की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत खर्चों के लिए 11.2 लाख करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई थी, इसे वर्ष 2026-27 के बजट में बढ़ाकर 12.20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष की

तुलना में 9 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2014-15 के बजट में पूंजीगत खर्चों के लिए केवल 2 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया था। पिछले 13 वर्षों में पूंजीगत खर्चों में 6 गुना से भी अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। पूंजीगत खर्चों में वृद्धि से कई क्षेत्रों में सरकारी निवेश भी बढ़ता है एवं इससे अंततः रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित होते हैं। बल्कि, अब तो सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी अपने पूंजी निवेश को बढ़ाना होगा। क्योंकि, सरकार के पूंजीगत खर्चों में अतुलनीय वृद्धि से देश में ही विभिन्न उत्पादों के निर्माण में तेज गति से वृद्धि होगी और वर्तमान विनिर्माण इकाईयों की उत्पादन क्षमता का उपयोग 80 प्रतिशत से ऊपर निकल जाएगा, जो वर्तमान में लगभग 75 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है, इससे नई उत्पादन इकाईयों को स्थापित करना आवश्यक होगा। अतः भारत में अब निजी क्षेत्र में भी निवेश बढ़ेगा, इसमें विदेशी निवेश भी शामिल है।

भारत में उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में रेल्वे की मुख्य भूमिका रहती है। भारत में इन उत्पादों की गतिशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से 7 नए हाई स्पीड रेल कोरिडोर बनाए जाने की घोषणा भी इस बजट में की गई है। यह कोरिडोर मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बैंगलोर, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बैंगलोर, दिल्ली से वाराणसी एवं वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच विकसित किए जाएंगे। यह क्षेत्र विकास के नए केंद्र बन जाएंगे।

भारत को विश्व में लाजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने के लिए इस बजट में 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया जा रहा है ताकि भारत में ही कंटेनर के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। भारत में मेडिकल टुरिजम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 हब बनाए जाएंगे। इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र एवं राज्यों को भी साथ में लिया जाएगा। इससे भारत में उच्च गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगी एवं अन्य देशों के नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत की ओर आकर्षित होंगे। इसी प्रकार, भारत में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बौद्ध सर्किट का निर्माण भी किया जा रहा है। इससे अन्य देशों के बौद्ध धर्म के अनुयायी भारत में धार्मिक पर्यटन हेतु आकर्षित हो सकेंगे। भारत को पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है क्योंकि भारत में समस्त धर्मों का आदर किया जाता है।

पूरे विश्व में ऐनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एवं कॉमिक क्षेत्र तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारतीय युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर तलाशने एवं इस क्षेत्र को भारत में ही बढ़ाने के उद्देश्य से इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का निर्णय इस बजट में किया गया है। इस क्षेत्र में वर्ष 2030 तक 20 लाख युवाओं की आवश्यकता पड़ेगी। अतः इस हेतु भारत में ही विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में इस क्षेत्र में शिक्षा एवं कौशल प्रदान करने हेतु उच्च शिक्षा प्रदान किए जाने की व्यवस्था की जा रही है।

आयकर की दरों में किसी प्रकार की वृद्धि प्रस्तावित नहीं है। जबकि आयकर के नियमों को सरल बनाया गया है। आय कर की नई योजना के अंतर्गत अब 12 लाख रुपए तक की आय पर शून्य आयकर लगाया जाएगा। आयकर रिटर्न फाइल करने हेतु समय सीमा को भी बढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार, इस संदर्भ में आयकर नियमों को सरल बनाया जा रहा है

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट की कुछ मुख्य विशेषताओं में वित्तीय अनुशासन का अनुपालन किया जाना भी शामिल है। बजटीय घाटे को 4.5 प्रतिशत के अंदर रखने का प्रयास सफल रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजटीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत रखने में सफलता हासिल हुई है। जबकि, अमेरिका जैसे विकसित देश में भी आज बजटीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजटीय घाटे को कम करते हुए इसे 4.3 प्रतिशत तक नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान पूंजीगत खर्चों में 1.1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि भी प्रस्तावित है।

आम बजट 2026-27 से विकसित बनेगा भारत

राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा ने अमृत काल में विकसित भारत के दृष्टिगत विगत एक दशक से जारी अनवरत समावेशी विकास के तहत एनडीए सहयोगियों को भरोसे में लेकर जिस प्रकार से आम बजट 2026-27 को प्रस्तुत किया, उसमें आरएसएस की जनोन्मुखी सोच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासी दूरदर्शिता और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आर्थिक शिल्पकारिता का सटीक संदेश मिलता है। इससे विगत 12 वर्षों से जारी चतुर्दिक विकास को और अधिक बढ़ावा मिलेगा, और सियासी संसारमें मजबूत भारत का डंका बजेगा। भारत अब अमेरिका और चीन से प्रतियोगिता करेगा और राष्ट्रवादी कार्यकताओं के कठिन परिश्रम से अगले दशक तक उन्हें भी मात देगा। दुनियादारी के विशेषज्ञों की टिप्पणियों से भी इस बात की तस्दीक की जा सकती है।

आम बजट 2026-27 साफगोई पूर्वक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की नीतियों और सुशासन की निरंतरता को रेखांकित करता है। यह केंद्रीय बजट भारत को 2047 तक विकसित बनाने की दिशा में अगला महत्वपूर्ण कदम प्रतीत होता है। दरअसल, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की अर्थव्यवस्था को निरंतर मजबूत बनाए रखने के लिए जो निर्णायक कदम उठाए हैं, उससे देश के विकास को रफ्तार मिलेगी। चूंकि जनता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भरोसा करती है, इसलिए उसकी समग्र बेहतरी के लिए लाया हुआ यह युवा बजट हरेक दृष्टि जनकल्याणकारी है।

वर्तमान बजट में समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ खास जरूर है, जिससे सबका साथ, सबका विकास जैसी लोकतांत्रिक जनभावना को जनविश्वास हासिल होता है और सरकार को मजबूती मिलती है। सरकार ने कोशिश की है कि युवाओं, किसानों, महिलाओं, कामगारों, उद्यमियों और बुजुर्गों के निजी व सार्वजनिक हितों का संबर्धन होता रहे। मौजूदा बजट हमारे लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की प्रगति करता है, देश में उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है, पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में काम करने वालों के उज्ज्वल भविष्य को मजबूत बनाता है, नए रोजगार और कौशल बढ़ाता है, जिससे निश्चय ही विकास की गति तेज होगी। इसलिए मैं इस बजट को विकसित भारत 2047 के स्वर्णिम भविष्य के लिए तैयार युवा बजट कहूंगा। क्योंकि यह वास्तव में एक ऐसा बजट है जो भारत की जरूरत और लक्ष्य को हासिल करने की नींव रखता है।

जैसा कि हमारे दिग्गज नेताओं ने एक स्वर से कहा भी है कि यह आम बजट देश और इसकी जनता के अरमानों को पंख लगाता है, जिससे गरीब, युवा और बेरोजगार सबको आगे बढ़ने के सुनिश्चित साधन मिलते हैं। चूंकि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास और भरोसा करती है, इसलिए बजट का मुख्य उद्देश्य विकास और प्रगति दोनों है, क्योंकि इसमें देश और उसकी जनता की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाया गया है।इसके सभी प्रावधान आम जनता के लिए ही बनाए गए हैं। इसलिए आम बजट 2026-27 विकास और प्रगति पर केंद्रित बजट है। जिससे देश के लोग खुश हैं। इस बजट की सियासी आलोचना के अलावा अन्य की कोई गुंजाइश नहीं है। इससे मोदी है तो मुमकिन है, का भाव और मजबूत हुआ है।

वाकई संसद में पेश केंद्रीय बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण जोशीला अगला कदम है, जो गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं समेत समाज के हर वर्ग की जरूरत पूरी करता है और उनकी व्यापक भलाई सुनिश्चित करता है। यह युवा बजट पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी कार्यकुशल सियासी व प्रशासनिक टीम पर लोगों के अटूट भरोसे को दिखाता है। यह इस बजट के हर पहलू में साफ दिखता है।

सच कहूं तो भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई चौथी अर्थव्यवस्था है, जिसे शीघ्र ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के निमित्त यह बजट प्रस्तुत किया गया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजन में तेजी आएगी। इस प्रकार यह बजट स्पष्ट रूप से भविष्य में भारत को और अधिक समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए सरकार के संकल्प को दर्शाता है। जब महज 12 वर्षों के भाजपा और राजग शासनकाल में भारत, अमेरिका और चीन को रणनीतिक कूटनीतिक स्वायत्तता जैसी टक्कर देने की स्थिति में पहुंच चुका है तो अगले 10 वर्षों और खासकर विकसित भारत 2047 तक भारत की अंतरराष्ट्रीय हैसियत क्या होगी, समझना मुश्किल नहीं है।

प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट

9.13 लाख करोड़ से संवरेगा उत्तर प्रदेश

बजट में प्रदेश सरकार का वित्तीय अनुशासन के साथ समग्र विकास पर भी फोकस

ललित कुमार

उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में योगी सरकार का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। 'नव निर्माण के नौ वर्ष' की थीम पर प्रस्तुत बजट 2026-27 का कुल आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 12.9 प्रतिशत अधिक है। आकार के लिहाज से योगी सरकार ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन को बताया कि यह बजट राज्य की बढ़ती आर्थिक क्षमता, निवेश के अनुकूल माहौल और सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन का परिणाम है। यह बजट न केवल राज्य की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है, बल्कि दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और सतत विकास की स्पष्ट रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है। बजट 2026-27 सरकार की उस सोच को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें विकास, वित्तीय अनुशासन और भविष्य की तैयारी तीनों को समान महत्व दिया गया है। इस बजट में अन्नदाता किसान, युवा, महिला, छात्र-छात्राओं समेत हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को प्राथमिकता

वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में 19.5 प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जो आधारभूत ढांचे, औद्योगिक विकास, सड़क, ऊर्जा और शहरी-ग्रामीण अधोसंरचना को नई गति देगा। पूंजीगत निवेश से रोजगार सृजन होगा और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। योगी सरकार ने सामाजिक क्षेत्रों को बजट में प्रमुख स्थान दिया है। इसके अंतर्गत शिक्षा के लिए कुल बजट का 12.4 प्रतिशत, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए 6 प्रतिशत और कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिए 9 प्रतिशत का आवंटन किया गया है। यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार मानव संसाधन विकास और किसानों की आय बढ़ाने को विकास की धुरी मानकर चल रही है।

राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत की सीमा में

उन्होंने बताया कि 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3 प्रतिशत निर्धारित की गई है, जो वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि वह राजकोषीय अनुशासन से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा

1,18,480.59 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो राज्य के अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2.98 प्रतिशत है। यह 3 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर है और वित्तीय अनुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। समग्र परिप्रेक्ष्य में, बजट 2026-27 में एक ओर जहां विकासोन्मुख नई योजनाओं का विस्तार है, वहीं दूसरी ओर राजस्व बचत और नियंत्रित राजकोषीय घाटे के माध्यम से वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का स्पष्ट प्रयास किया गया है।

डीजल से सोलर की ओर बड़ा कदम

बजट में विशेष रूप से कृषि विभाग के अंतर्गत डीजल पंप सेट को सोलर पंप में परिवर्तित करने की महत्वाकांक्षी योजना के लिए 637.84 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों की डीजल पर निर्भरता कम होगी, लागत घटेगी और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम कृषि क्षेत्र में हरित ऊर्जा संक्रमण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष और एफपीओ को मजबूती

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किए जाने के मद्देनजर सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए रिवॉल्विंग फंड योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपये का कोष नाबार्ड की सहभागी संस्था 'नैब किसान' के साथ मिलकर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसमें सरकार 75 करोड़ रुपये का अंशदान देगी। प्रत्येक पात्र एफपीओ को अधिकतम 50 लाख रुपये तक की ऋण सीमा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, यूपी एग्रीज के अंतर्गत प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए 245 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ना है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत 38 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रदेश में 2 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी, जिसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, बजट में स्वच्छताकर्मियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके अकाउंट में सीधे 16 से 20 हजार रुपये भेजने का भी प्राविधान किया गया है। इसके लिए सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जल्द ही स्कीम का फायदा स्वच्छताकर्मियों को मिलेगा।

शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा

बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, विशेष शिक्षकों, अनुदेशकों,

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कार्मिकों तथा पीएम पोषण योजना की रसोइयों एवं उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के लिए 357.84 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 89.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को निशुल्क सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्कूल उपस्थिति में सुधार की उम्मीद है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एआई प्रमाणन शुल्क प्रतिपूर्ति योजना हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों के शिक्षा ऋण पर अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी के लिए 30 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

एमएसएमई और रोजगार को बढ़ावा

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के तहत सरदार वल्लभभाई पटेल इंप्लॉइमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना के लिए 575 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एक जनपद एक व्यंजन (ओडीओसी) योजना के लिए 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे स्थानीय खाद्य उत्पादों को पहचान और बाजार मिलेगा। इसके साथ ही, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत इंटरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश में फिल्म उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

श्रमजीवी महिला छात्रावास के लिए 80 करोड़ रुपये का बजट

मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के अंतर्गत गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद और लखनऊ में निर्माण कार्य चल रहा है। अन्य जनपदों (अयोध्या, बरेली, अलीगढ़, मिजार्पुर, सहारनपुर एवं मुरादाबाद) में विस्तार के लिए 80 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। जनमानस के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एसजीपीजीआई में क्वाटर्नरी हेल्थ केयर सुविधा प्रारंभ करने के लिए 359 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके साथ ही कैंसर मिशन के अंतर्गत हब एवं स्पोक मॉडल पर राज्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों तथा निजी क्षेत्र के समन्वय से कैंसर उपचार व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना: वाराणसी रीजन चयनित

केन्द्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना में 7 रीजन की पहचान की गई है, जिनमें वाराणसी रीजन भी शामिल है। नीति आयोग की जनवरी 2026 की रिपोर्ट में काशी-विन्ध्य क्षेत्र को 'इकोनॉमिक हब' के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसमें 34 प्राथमिकता

यूपी एआई मिशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के तहत 'उत्तर प्रदेश एआई मिशन' (यूपीएआई मिशन) शुरू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अगले तीन वर्षों में लगभग 2000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से लागू किए जाएंगे। इसके लिए 225 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। स्टेट डाटा सेंटर 2.0 के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके साथ नियोजन विभाग के अंतर्गत स्टेट डाटा अथॉरिटी की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 53 विभागों में 'जन विश्वास सिद्धांत' लागू किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

परियोजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, पर्यटन, विनिर्माण, ऊर्जा और आवास क्षेत्रों में समेकित विकास किया जाएगा।

ऋण प्रबंधन में योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि

वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2016-17 में राज्य को 29.3 प्रतिशत ऋण-जीएसडीपी की अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जिसे 2019-20 तक घटाकर 27.9 प्रतिशत कर दिया गया। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण यह अनुपात वर्ष 2021-22 में बढ़कर 33.4 प्रतिशत हो गया था, लेकिन सुनियोजित राजकोषीय प्रबंधन के चलते वर्ष 2024-25 में इसे पुनः 27 प्रतिशत से नीचे लाया गया है। सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में ऋण-जीएसडीपी अनुपात को 23.1 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य तय किया है। इतना ही नहीं, बजट के साथ प्रस्तुत मध्यकालीन राजकोषीय नीति में इसे चरणबद्ध रूप से 20 प्रतिशत से नीचे लाने का संकल्प भी दोहराया गया है। इसका उद्देश्य राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और सतत विकास सुनिश्चित करना है।

नई योजनाओं और सुदृढ़ वित्तीय संरचना की दिशा में बड़ा कदम

प्रदेश सरकार ने अपने बजट में 43,565.33 करोड़ रुपये की नई योजनाओं को शामिल किया है, जिनका उद्देश्य अधोसंरचना विकास, सामाजिक क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और उत्पादक निवेश को गति देना है। यह प्रावधान राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्य की कुल प्राप्तियां 8,48,233.18 करोड़ रुपये अनुमानित की गई हैं। इसमें से राजस्व प्राप्तियां 7,28,928.12 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत प्राप्तियां 1,19,305.06 करोड़ रुपये निर्धारित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का बड़ा हिस्सा 6,03,401.76 करोड़ रुपये है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 3,34,491 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 2,68,910.76 करोड़ रुपये शामिल है। यह वित्तीय संरचना स्पष्ट रूप से दशार्ती है कि राज्य की आय में स्वयं के संसाधनों की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है, जिससे राज्य आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनता जा रहा है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर

यूपी बजट में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से महिलाओं को आसान, ब्याज-मुक्त एवं चरणबद्ध पूंजी उपलब्ध कराकर 'लखपति दीदी' लक्ष्य को गति दी जाएगी। वहीं महिला उद्यमियों द्वारा उत्पादित सामान की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट और बड़े बाजारों में महिलाओं द्वारा संचालित शोरूम व दुकानों की व्यवस्था की जाएगी, जिनका किराया शुरूआती तीन वर्षों तक राज्य सरकार वहन करेगी।

पूंजीगत निवेश पर स्पष्ट बल

राज्य सरकार ने कुल 9,12,696.35 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव रखा है, जिसमें पूंजीगत निवेश को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसमें से 6,64,470.55 करोड़ रुपये राजस्व लेखा व्यय तथा 2,48,225.81 करोड़ रुपये पूंजी लेखा व्यय के रूप में निर्धारित किए गए हैं। पूंजीगत व्यय का यह उच्च स्तर राज्य में दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के निर्माण, आधारभूत संरचना के विस्तार और आर्थिक गतिविधियों को गति देने की स्पष्ट प्रतिबद्धता को दशार्ता है। वित्त मंत्री ने बताया कि समेकित निधि की प्राप्तियों में से कुल व्यय घटाने पर 64,463.17 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित है। वहीं लोक लेखे से 9,500 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित की गई हैं। इन दोनों को समायोजित करने पर समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 54,963.17 करोड़ रुपये ऋणात्मक आंका गया है, जो वित्तीय प्रबंधन के संतुलन की आवश्यकता को इंगित करता है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रारंभिक शेष 96.41 करोड़ रुपये ऋणात्मक को जोड़ने पर अंतिम शेष 55,059.58 करोड़ रुपये ऋणात्मक अनुमानित है। एक सकारात्मक संकेत यह भी है कि राजस्व बचत 64,457.57 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है, जो दशार्ता है कि राज्य की नियमित आय उसके नियमित व्यय से अधिक है और राजकोषीय संतुलन को बनाए रखने में सहायता कर रही है।

9 वर्षों में तीन गुना बढ़ा प्रदेश का बजट

यूपी बना 'अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट'

अनिल वशिष्ठ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के सभागार में पत्रकारों को संबोधित करते हुए वर्ष 2026-27 के बजट की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्षों के दौरान अपना परसेप्शन बदलने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश ने इस दौरान पॉलिसी पैरालिसिस से उभर कर परसेप्शन को बदलकर खुद को अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट के रूप में प्रस्तुत किया है, आज का यह बजट उन्हीं भावों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रदेश का यह बजट 9 वर्षों में तीन गुना से अधिक बढ़ा है। आज 9,12,000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। बजट की थीम सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होते उत्तर प्रदेश पर आधारित है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 43,565 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि नई योजनाओं के लिए बजट में प्रस्तावित की गई हैं। वहीं 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आंवटित की गई है। परिसंपत्तियों के नवनिर्माण, इन्फ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट और अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहीं से रोजगार का सृजन होता है। यह प्रदेश में पहली बार है, जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। पिछले 9 वर्षों में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। इसके साथ ही यूपी में जो कर चोरी और लीकेज थे, इन सबको रोक कर कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेकथ्रू के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। वर्ष 2017 में 30 फीसदी से अधिक राज्य में ऋणग्रस्तता थी। हम लोगों ने इसे घटाकर पिछले दो-तीन वर्षों में 27 फीसदी लाने में सफलता प्राप्त की। इस वित्तीय वर्ष में इसे 23 फीसदी तक लाने का लक्ष्य है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार किसी भी राज्य की जो कुल जीएसडीपी होगी, उस पर 30 फीसदी से अधिक ऋण नहीं होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है, जिन्होंने अपने वित्तीय प्रबंधन को एफआरबीएम की निर्धारित सीमा के अधीन रखा है। यह हमारा कुशल वित्तीय अनुशासन है। कोई नया टैक्स लगाए बिना प्रदेश ने जन-कल्याण व इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्कीम के साथ प्रत्येक सेक्टर में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। आज उत्तर प्रदेश देश की टॉप तीन इकॉनमी में से एक है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम लोगों ने प्रदेश में अनइंप्लॉयमेंट रेट को 2.24 प्रतिशत तक नीचे लाने में सफलता प्राप्त की है। वर्ष 2017 के पहले यह लगभग 17 से 19 फीसदी तक था। बजट में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एमएसएमई, स्टार्टअप, ओडीओपी और स्थानीय उद्यमों को विकसित करते हुए वृहद निवेश की नई योजनाओं को शुरू करने का प्रावधान किया गया है। बजट में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं। पहले प्रदेश में अलग-अलग विभाग अलग-अलग समय में अलग-अलग डेटा प्रस्तुत करते थे। हमारी सरकार ने तय किया है कि हम एक स्टेट डेटा अथॉरिटी का गठन करेंगे। यह स्टेट डेटा अथॉरिटी प्रदेश में रियल टाइम डेटा और इसकी मॉनिटरिंग के साथ भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। वहीं बजट में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डेटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

मेडटेक और डीपटेक के लिए एआई मिशन की घोषणा की गई है, ताकि युवाओं को अधिक से अधिक जॉब उपलब्ध कराए जा सकें। इसके लिए उनकी स्किल डेवलपमेंट की प्लानिंग भी बजट में की गई है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों के जरिये महिलाओं की उद्यमिता को प्रोत्साहन देने और उनके उत्पादों के लिए शी-मार्ट विपणन केंद्र विकसित करने की बात भी बजट में कही गई है। इस योजना से स्थानीय महिलाओं को काफी मदद मिलेगी, जो एसएचजी के माध्यम से लोकल गांवों और शहरी क्षेत्र में अपना प्रोडक्ट बनाती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सिटी इकॉनमिक जोन, एससीआर, काशी-मीरजापुर इकॉनमिक जोन, प्रयागराज-चित्रकूट इकॉनमिक जोन, कानपुर-झांसी इकॉनमिक जोन को विकिसत करने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2017 में यूपी की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग 13-14 पर थी। आज नंबर दो पर है। इसके बाद यूपी ने चीफ अचीवर स्टेट के रूप में खुद को स्थापित किया। प्रदेश में डिजिटल आन्त्रोप्रेन्योरशिप योजना को आगे बढ़ाने के लिए बजट में व्यवस्था की गयी है। इन सभी सफलता को प्राप्त करने में रूल ऑफ लॉ की बड़ी भूमिका है, यही रियल ग्रोथ है। हर व्यक्ति सुरक्षा की गारंटी चाहता है और वह गारंटी आज यूपी दे रहा है। पहले यूपी में कोई नहीं सोच सकता था कि 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव आएंगे।

यूपी का एमएसएमई सेक्टर जो पहले मृत हो गया था, आज उसने 3 करोड़ से अधिक नौजवानों को नौकरी दी है। प्रदेश के अन्नदाताओं को उद्यमी बनाने के लिए नए प्रयास किये जा रहे हैं। विकास की यात्रा में प्रदेश का अन्नदाता भी सक्रिय साझेदार बने, इस दृष्टि से कृषि को इनकम बेस्ड और वैल्यू एडिशन मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। प्रदेश में सिंचाई की क्षमता का विस्तार किया गया है। प्रदेश में 16 लाख ट्यूबवेल का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। वहीं 23 लाख से अधिक डीजल से संचालित ट्यूबवेल को सोलर से जोड़ने के लिए बजट में घोषणा की गई है। इसके साथ पीएम कुसुम योजना को भी जोड़ा जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति-जनजाति, महिला और लघु सीमांत किसानों को 90 फीसदी अनुदान और अन्य किसानों के लिए 80 फीसदी सब्सिडी की घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 के तहत नाबार्ड ने किसान के साथ एफपीओ के लिए रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था की है। इन्हें अतिरिक्त सुविधा और फैसिलिटेट किया जा सके, इसके लिए भी बजट में व्यवस्था की गयी है। गन्ना के साथ तिलहन और दलहन फसलों के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। यूपी के किसानों के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एग्री एक्सपोर्ट हब्स के रूप में विकसित करने की कार्यवाही को आगे बढ़ाया है।

उत्तर प्रदेश में कृषि और बागवानी उत्पादों की क्वालिटी है और उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। वर्ल्ड बैंक के साथ यूपी एग्रीज प्लेटफॉर्म, यूपी एग्रीज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसको एआई से जोड़ने के लिए भी घोषणा की गयी है। बजट में 2 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण की क्षमता विकसित करने का टारगेट तय किया गया है। यहां पर वेयरहाउसिंग का निर्माण हो, बड़े-बड़े गोदाम बने इसके लिए विशेष सब्सिडी की व्यवस्था की

गई है।

वहीं पशुओं को बीमा सुरक्षा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन और पशुधन बीमा योजना का प्रावधान किया गया है, जिसमें 85 फीसदी तक जो प्रीमियम होगा, वह सरकार देगी। प्रदेश में मछुआरों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मंडी और फिश प्रोसेसिंग सेंटर के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा वर्ल्ड फिश, फिशरीज प्रोजेक्ट सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। चार चीनी मिलों की क्षमता संवर्धन का प्रावधान किया गया है, जिसमें छाता मथुरा के अश्वनी और लॉजिस्टिक हब वेयरहाउसिंग कांप्लेक्स के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है और अन्य चीनी मिलों में भी इसकी व्यवस्था के प्रावधान किए गए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अवस्थापना और औद्योगिक विकास के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है। आगरा-लखनऊ से हरदोई-फरुर्खाबाद गंगा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। गंगा एक्सप्रेसवे से प्रयागराज, मीरजापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र तक यानी शक्तिनगर तक इसके विस्तार की घोषणा हुई है। गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ-हरिद्वार तक ले जाने के लिए भी बजट में घोषणा की गई है और पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को सोनभद्र के शक्तिनगर तक, चंदौली, गाजीपुर के गाजीपुर तक ले जाने के लिए बजट में व्यवस्था की गई है।

यूपी में बायोफ्यूल प्लास्टिक संस्थान केंद्र को भी विकसित करने की कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया है। इसके अलावा एफडीआई फॉर्च्यून 500 में आने वाली कंपनियों के लिए भी बजट में घोषणा की गई। हर जिले में स्किल डेवलपमेंट के एक बड़े केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसे हब और स्पोक मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत सरदार वल्लभभाई पटेल इंप्लायमेंट जोन के लिए भी घोषणा की गई, जिसमें 50 एकड़ से लेकर 100 एकड़ क्षेत्रफल के एक बड़े क्लस्टर में स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। वहीं वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना के तहत स्थानीय खाद्य पदार्थों की ब्रांडिंग की जा सके, इसको प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान बजट में किया गया है।

यूजीसी बिल को लेकर देशभर में हो रहा विरोध प्रदर्शन

उच्च शिक्षा में छात्रों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा लागू किए गए नए इक्विटी नियम अब देशभर में बहस और टकराव की वजह बनते जा रहे हैं। गंभीर बात यह है कि इस नियम में एससी-एसटी के साथ ओबीसी को भी शामिल किया गया। यानी नियम बनाने वाली सरकारी कमेटी ने ओबीसी को भी भेदभाव में शामिल कर लिया है। वहीं, एक और गंभीर बात है कि देश में 41 प्रतिशत मुसलमान भी ओबीसी में शामिल हैं और कई प्रदेशों में यह आंकड़ा 80 से 95 प्रतिशत तक भी है। ऐसे में सवर्ण छात्र मुसलमानों के भी निशाने पर आ जाएंगे। 15 जनवरी से लागू उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 को जहां शैक्षणिक सुधार की दिशा में अहम कदम बताया जा रहा है,

वहीं दूसरी ओर सामान्य वर्ग के छात्रों के बीच इसे लेकर गहरी नाराजगी उभरकर सामने आ रही है। सामान्य वर्ग के छात्रों को आशंका है कि यह नियम कहीं योग्यता, अवसर और निष्पक्षता के सिद्धांतों को प्रभावित कर सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 15 जनवरी 2026 से 'उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026' लागू कर दिए हैं। इस नए नियम का मकसद उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव रोकना और सभी छात्रों को बराबरी के अवसर देना है। खास बात यह है कि अब अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किए गए हैं। नए नियम के तहत हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में समानता समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसमें ओबीसी, महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि होंगे। समानता समिति में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को भी शामिल नहीं किया गया है। समिति हर छह महीने में अपनी रिपोर्ट यूजीसी को भेजेगी। इसके अलावा, अब ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायत सक्षम अधिकारी के पास दर्ज करा सकते हैं। हर संस्थान में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ होना अनिवार्य है, ताकि सभी के अधिकार सुरक्षित रहे।

यूजीसी के नए रेगुलेशन लागू होने के बाद छात्रों के बीच असंतोष बढ़ गया है। विरोध करने वाले संगठनों का मानना है कि इस नियम का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और छात्रों या शिक्षकों को झूठे आरोपों में फंसाया जा सकता है। इसी चिंता के चलते जयपुर में करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर 'सवर्ण समाज समन्वय समिति (एस-4)' का गठन किया है, ताकि रेगुलेशन के खिलाफ संगठित विरोध किया जा सके।

पालन न करने पर सख्त कार्रवाई

यूजीसी ने नए इक्विटी नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है। आयोग ने कहा है कि जो भी कॉलेज या विश्वविद्यालय इन नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें संस्थान को यूजीसी की योजनाओं से बाहर करना, कोर्स बंद करना, ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन पर रोक लगाना और संस्थान की मान्यता रद्द करना शामिल है। यूजीसी के नए नियमों में जातिगत भेदभाव की शिकायत करने का तरीका भी बताया गया है। नियमों के अनुसार, कोई भी पीड़ित छात्र, शिक्षक या कर्मचारी हेल्पलाइन, ईमेल या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। वह अपनी कंप्लेंट लिखित रूप में भी दे सकता है। अगर मामला गंभीर और आपराधिक है, तो उसे सीधे पुलिस के पास भेजा जाएगा। यूजीसी ने कहा है कि अगर शिकायतकर्ता इक्विटी कमेटी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह एक महीने के भीतर कॉलेज या विश्वविद्यालय में बनाए गए ओम्बड्समैन के पास अपील कर सकता है। वहां तय समय में निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा, यूजीसी पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा और कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों का रैंडम इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट भी मांगेगा, ताकि नियम सही ढंग से लागू हो रहे हैं या नहीं, यह सुनिश्चित किया जा सके। 27 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (यूजीसी) दफ्तर के सामने सवर्ण सेना नाम की संगठन की ओर से यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन का विरोध किया गया। इससे पहले यूजीसी के हेडक्वार्टर के बाहर विरोध-प्रदर्शन करने छात्र भी पहुंचे। छात्रों का कहना है कि यूजीसी की ओर से जारी नए नियम कैंपस में अराजकता की स्थिति पैदा कर सकते हैं। उन्होंने 'नो टू यूजीसी डिस्क्रीमिनेशन' का नारा देते हुए यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर बड़ी संख्या में पहुंचकर विरोध दर्ज कराने की अपील की। छात्रों का कहना है कि नए नियम उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। इन नियमों के खिलाफ सबसे पहले छात्र और शिक्षक सामने आए। उनका कहना है कि नियम बहुत उलझे और भेदभाव वाले हैं। आलोचकों का मानना है कि नियमों में कई बातें साफ नहीं लिखी गई हैं। संस्थानों की समितियों को बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए है, जिसके तहत झूठे आरोपों से बचाव के लिए कोई मजबूत सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। अलग-अलग कॉलेजों में नियमों का गलत या असमान इस्तेमाल हो सकता है और इसी वजह से कई राज्यों में छात्रों और शिक्षकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं।

क्या है विरोध और क्यों आक्रोशित हैं छात्र?

- सबसे पहले विरोध और हंगामा है असमानता का जो जनरल कैटेगरी के साथ हुआ है। उनका कहना है कि इस बिल में उनको ही टारगेट किया गया है और उनके खिलाफ एक पक्षपाती माहौल बन सकता है। जबकि एससी/एसटी/ओबीसी/महिलाओं/दिव्यांगों का जोरदार समावेशन किया गया है।
- नए नियम के तहत अगर कोई पीड़ित भेदभाव की घटना शिकायत करता है तो वो अपनी पहचान छुपा सकता है। इसका उद्देश्य पीड़ित को किसी प्रतिशोध से बचाता है, लेकिन इसी के साथ ये डर भी आता है कि कोई भी अपनी पहचान छुपा कर इस कानून का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। हो सकता है कॉलेजों में होने वाली दुश्मनियां या झगड़ों में हुई आपसी रंजिश इस नियम के जरिए देखने को मिलेगी।
- सिर्फ पीड़ित ही नहीं, नियमों के तहत सूचना देने वाला व्यक्ति भी अपनी पहचान गोपनीय रख सकता है। इसको लेकर के भी सवाल है कि क्या इसका मिसयूज नहीं होगा? इन दोनों ही नियमों पर आक्रोश है।
- नए नियमों में झूठी या गलत इरादे से अगर कोई शिकायत दर्ज कराता है तो उसे क्या दंड दिया जाएगा या क्या कार्रवाई होगी, ये तय नहीं है। यानी अगर कोई मनमाने ढंग से गलत आरोप लगा देता है तो उसका नुकसान नहीं होगा पर छात्र या शिक्षक की प्रतिष्ठा और करियर पर नुकसान हो सकता है।
- एक विरोध इस बात पर भी है कि भेदभाव की जो परिभाषा दी गई है, वो बहुत ही व्यापक है। ऐसे में किसी भी सामाजिक या अकेडमिक एक्टिविटी को भी इसमें लाया जा सकता है। यहां भी मिसयूज होने का डर है।

आगरा में बीजेपी विधायक ने खून से लिखा पत्र

यूजीसी 2026 के विरोध में बीजेपी नेता ने अपने खून से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। सवर्ण छात्र-छात्राओं के साथ-साथ शिक्षक भी यूजीसी बिल 2026 का विरोध कर रहे हैं। आगरा के जगदीश पचौरी, जो नगर निगम में उपसभापति रह चुके हैं, उन्होंने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बिल में सुधार करने के लिए एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि इस बिल के जरिए सामान्य छात्र-छात्राओं की प्रतिभाओं को दबाने का काम किया जा रहा है। उनका कहना है कि बेहतर होगा कि इस बिल में जो त्रुटियां हैं, उनमें संशोधन किया जाए, ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिल सके।

हापुड़ में भी खून भरा खत

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में राष्ट्रीय सैनिक संस्था के पदाधिकारियों ने यूजीसी एक्ट के विरोध में राष्ट्रपति के नाम खून से खत लिखा है। सैनिकों द्वारा लिखे गए खून से खत में सरकार के इस यूजीसी एक्ट को काला कानून बताया गया है और राष्ट्रपति से जल्द से जल्द इस एक्ट में सुधार करने अन्यथा इसे निरस्त करने की मांग की गई है। राष्ट्रीय सैनिक संस्था के जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र त्यागी ने बताया कि यूजीसी द्वारा बनाए गए नियम देश के सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों पर समान रूप से लागू किए जाते हैं। ऐसे में वर्तमान सरकार द्वारा यूजीसी एक्ट में किया गया संशोधन समाज में जातीय असमानता को उत्पन्न करेगा। ज्ञानेंद्र त्यागी ने कहा कि इस काले कानून का दुष्प्रभाव हमारे बच्चों के भविष्य में दिखाई देगा। देश के राष्ट्रपति से मांग की जाती है कि वह जल्द से जल्द इस यूजीसी एक्ट को संशोधित करें या फिर इसे निरस्त करें।

गोरखपुर बीजेपी विधायक ने यूजीसी को बताया खलनायक

गोरखपुर के बीजेपी विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह भी यूजीसी बिल के विरोध में शामिल हो गए हैं। देवेंद्र सिंह ने यूजीसी आरक्षण विवाद पर

इन सवालों के जवाब कौन देगा?

यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में जातिगत-भेदभाव के मामलों में बढ़ोतरी को आंकड़ों में बताया। साल 2017-18 में ऐसे 173 मामले सामने आए जबकि 2023-24 में ये आंकड़ा 378 पहुंच गया। यानी इस तरह के मामलों में 118.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये आंकड़े ये तो साफ करते हैं कि इन नए नियमों की बेहद जरूरत है, लेकिन क्या ये नियम सचमुच न्याय करते हैं?

पीड़ित की परिभाषा में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं को शामिल किया गया है। पर अगर जनरल कैटेगरी के छात्र के साथ अन्याय होता है, भेदभाव होता है तो क्या ये नियम उन्हें भेदभाव से बचाएंगे? अगर एक ओबीसी का छात्र ही एससी या एसटी के छात्र पर जातिगत या जन्मगत टिप्पणी करता है, तो क्या उसपर भी दंडात्मक कार्यवाही होगी? या उसे पीड़ित की परिभाषा में आने की वजह से इस कानून में कोई छूट मिलेगी? क्या पीड़ित की परिभाषा में आने वाली कोई महिला किसी पर जातिगत टिप्पणी करती है, तो उसके लिए क्या नियम होंगे? दरअसल सवाल कई हैं और ये नए नियम इन सवालों के बीच कई सारे 'ग्रे एरिया' छोड़ गया है। ऐसे में करियर की दिशा में आगे बढ़ रहे छात्रों के लिए इस तरह के नियमों से डर और भय का माहौल भी पैदा हो रहा है। क्या एक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय करना, न्यायसंगत है?।

मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने यूजीसी के अध्यक्ष और सचिव को को लिखे पत्र का सरकार से संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने यूजीसी को खलनायक बताते हुए कहा कि यह निर्णय हिटलरशाही से बढ़कर रौलट एक्ट की तरह है। बीजेपी विधायक ने दावा किया है कि यूजीसी ने 2025 में एक गजट प्रकाशित किया था जिसके तहत नियम था कि अगर कोई गलत शिकायत करेगा, तो जुमार्ना लगेगा और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 2026 में दंड के प्रावधान को खत्म कर दिया गया। यूजीसी ने 2025 के गजट में केवल एससी/एसटी के लिए प्राविधान था। 2026 के गजट में एससी-एसटी के साथ ओबीसी को भी जोड़ दिया गया। देवेंद्र प्रताप सिंह ने आगे कहा कि ये मान लेना कि सामान्य वर्ग का विद्यार्थी शोषक और उत्पीड़क है, ये गलत अवधारणा है। हमें पहले से ही बिना हमारे जाने और पक्ष सुने मान लिया कि पूरा सवर्ण समाज शोषक है, यह गैरकानूनी है।

नए नियमों में न्याय मिलना संभव नहीं

विधान परिषद सदस्य ने आगे कहा कि इसमें साफ है कि अगर दलित बच्चा शिकायत करता है, तो उसे कोई प्रमाण नहीं देना है। एक शिकायत के बाद विभागाध्यक्ष नोटिस देगा, वो आपको हॉस्टल, परीक्षा और विश्वविद्यालय से बाहर कर सकता है। यूजीसी ने ये जो नियम बनाया है, उसमें सामान्य वर्ग के छात्रों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है, पहले से ही उन्हें आरोपी मान लिया गया। एक माइंडसेट का व्यक्ति शिकायत करेगा, उसी माइंडसेट का व्यक्ति सुनवाई करेगा, तो न्याय मिलना संभव नहीं है।

जो नियम पहले से आरोप मान ले, उसे स्वीकार करना असंभव

देवेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि यूजीसी के कानून और नियम से समाज में नफरत और जातीय संघर्ष बढ़ेगा। देश के सामने सिविल वॉर जैसी स्थिति आएगी। वे देश के पहले विधायक हैं, जिन्होंने सबसे पहले यूजीसी के अध्यक्ष और सचिव को पत्र लिखा है। वे जनता-जनार्दन से अपील करते हैं कि इसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताएं। उन्होंने कहा कि जो नियम पहले से ही आरोपी मान ले, उसे तो स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यूजीसी का गठन शिक्षा के उत्कृटतम संस्थान के रूप में स्थापित हो। यूजीसी आज दुनिया की टॉप 100 विश्वविद्यालय में एक भी कॉलेज नहीं दे पाया।

कानून वापस लें या संशोधन करें: प्रियंका चतुर्वेदी

शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि कैंपस में किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव गलत है, और भारत में पहले ही कई छात्र इसके दुष्परिणाम झेल चुके हैं। लेकिन, क्या कानून को समावेशी नहीं होना चाहिए और यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि सभी को समान रूप से संरक्षण मिले? फिर कानून के लागू होने में यह भेदभाव क्यों? झूठे मामलों की स्थिति में क्या होगा? दोष का निर्धारण कैसे किया जाएगा' उन्होंने कहा है कि इस भेदभाव को कैसे परिभाषित किया जाए- शब्दों से, कार्यों से या धारणाओं से?। कानून के लागू होने की प्रक्रिया स्पष्ट, सटीक और सभी के लिए समान होनी चाहिए। कैंपस में नकारात्मक माहौल बनाने के बजाय, मैं आग्रह करती हूं कि यूजीसी की यह अधिसूचना या तो वापस ली जाए या उसमें आवश्यक संशोधन किया जाए।

स्वामी दयानंद सरस्वती: परंपरा से टकराकर सुधार का साहस

उन्नीसवीं शताब्दी के इस महापुरुष ने धर्म को तर्क, नैतिकता और राष्ट्रबोध से जोड़ा

स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के उन सुधारकों में हैं, जिन्होंने अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों को निर्भीकता से चुनौती दी। उनका चिंतन परंपरा-विरोधी नहीं, बल्कि परंपरा-शुद्धि का प्रयास था-जिसका लक्ष्य समाज को विवेकशील बनाना था।

अरुण मिश्रा

महर्षि दयानन्द सरस्वती (12 फरवरी 1824 - 30 अक्टूबर 1883) आधुनिक भारत के चिन्तक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम 'मूलशंकर' था। 'वेदों की ओर लौटो' प्रमुख नारा था। उन्होंने कर्म सिद्धान्त, पुनर्जन्म तथा सन्यास को अपने दर्शन के स्तम्भ बनाये। उन्होंने ही सबसे पहले 1876में 'स्वराज्य' का नारा दिया। बाद में लोकमान्य तिलक ने इसे आगे बढ़ाया। प्रथम जनगणना के समय स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने आगरा से देश के सभी आर्यसमाजों को यह निर्देश भिजवाया कि सब सदस्य अपना धर्म 'सनातन धर्म' लिखवाएं।

प्रारम्भिक जीवन

दयानन्द सरस्वती का जन्म 12 फरवरी, 1824 ई. (फाल्गुन दशमी, विक्रमी संवत् 1881) को टंकारा में हुआ था, जो वर्तमान में गुजरात के राजकोट जिले में आता है। उस समय यह मोरबी रियासत में था। उनके पिता का नाम श्री कर्षण जी और माँ का नाम यशोदा बाई था। उनके पिता एक कर-कलेक्टर होने के साथ ब्राह्मण कुल के समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे। इनका जन्म मूल नक्षत्र मे होने के कारण बाल्यावस्था में नाम मूलशंकर रखा गया। उनका प्रारम्भिक जीवन बहुत आराम से बीता। दयानंद सरस्वती की माता वैष्णव थीं जबकि उनके पिता शैव मत के अनुयायी थे।

महाशिवरात्रि को बोध

शिव के पक्के भक्त बालक मूलशंकर को उनके पिता ने महाशिवरात्रि के अवसर पर व्रत रखने को कहा। शिव मंदिर में रात्रि में बालक ने चूहों को शिव लिंग पर उत्पात मचाते देखा तो उसको बोध हुआ कि यह वह शंकर नहीं है, जिसकी कथा उसे सुनाई गई थी। इस के बाद मूलशंकर मन्दिर से घर चला गया और उसके मन में सच्चे शिव के प्रति जिज्ञासा उठी।

गृह त्याग

अपनी छोटी बहन और चाचा की हैजे के कारण हुई मृत्यु से वे जीवन-मरण के अर्थ पर गहराई से सोचने लगे और ऐसे प्रश्न करने लगे जिससे उनके माता पिता चिन्तित रहने लगे। तब

उनके माता-पिता ने उनका विवाह किशोरावस्था के प्रारम्भ में ही करने का निर्णय किया (19 वीं सदी के आर्यावर्त (भारत) में यह आम प्रथा थी)। लेकिन बालक मूलशंकर ने निश्चय किया कि विवाह उनके लिए नहीं बना है और वे 1846 में सत्य व ज्ञान की खोज में निकल पड़े।

फाल्गुन कृष्ण संवत् 1846 में शिवरात्रि के दिन उनके जीवन में नया मोड़ आया। वे घर से निकल पड़े और यात्रा करते हुए वह गुरु स्वामी विरजानन्द के पास पहुंचे। गुरुवर स्वामी विरजानन्द ने उन्हें पाणिनी व्याकरण, पातंजल-योगसूत्र तथा वेद-वेदांग का अध्ययन कराया। गुरु दक्षिणा में उन्होंने मांगा- विद्या को सफल कर दिखाओ, परोपकार करो, मत मतांतरों की अविद्या को मिटाओ, वेद के प्रकाश से इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो, वैदिक धर्म का आलोक सर्वत्र विकीर्ण करो। यही तुम्हारी गुरुदक्षिणा है। उन्होंने अंतिम शिक्षा दी- मनुष्यकृत ग्रंथों में ईश्वर और ऋषियों की निंदा है, ऋषिकृत ग्रंथों में नहीं। वे कलकत्ता में बाबू केशवचन्द्र सेन तथा देवेन्द्र नाथ ठाकुर के संपर्क में आए। यहीं से उन्होंने पूरे वस्त्र पहनना तथा हिन्दी (आर्य भाषा) में बोलना व लिखना प्रारंभ किया।

आर्य समाज की स्थापना

महर्षि दयानन्द ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 1932 (सन् 1875) को गिरगांव मुम्बई में आर्यसमाज की स्थापना की। आर्यसमाज के नियम और सिद्धांत प्राणिमात्र के कल्याण के लिए है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।

वैचारिक आन्दोलन, शास्त्रार्थ एवं व्याख्यान

वेदों को छोड़ कर कोई अन्य धर्मग्रन्थ प्रमाण नहीं है - इस सत्य का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने सारे देश का दौरा करना प्रारम्भ किया और जहां-जहां वे गये प्राचीन परम्परा के पण्डित और विद्वान उनसे हार मानते गये। संस्कृत भाषा का उन्हें अगाध ज्ञान था।

संस्कृत में वे धाराप्रवाह बोलते थे। साथ ही वे प्रचण्ड तार्किक थे। उन्होंने ईसाई और मुस्लिम धर्मग्रन्थों का भली-भांति अध्ययन-मन्थन किया था। अतएव अपनें शिष्यों के संग मिल कर उन्होंने

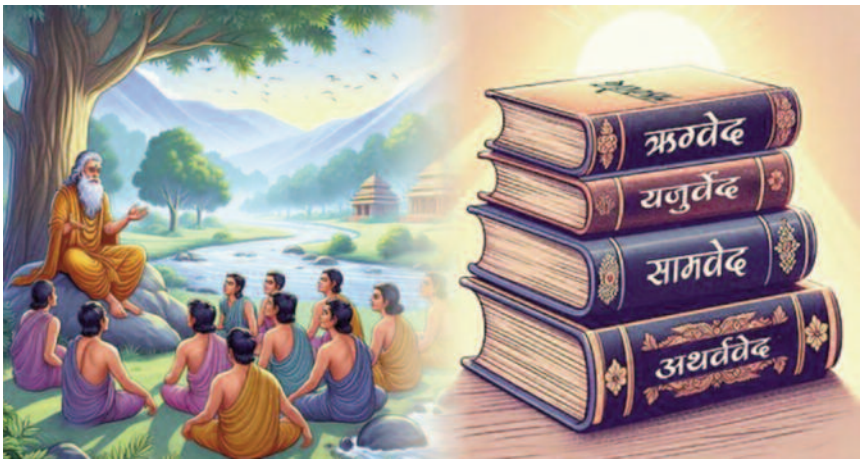

तीन-तीन मोर्चों पर संघर्ष आरंभ कर दिया। दो मोर्चे तो ईसाइयत और इस्लाम के थे, किन्तु तीसरा मोर्चा सनातनधर्मी हिन्दुओं का था। दयानन्द ने बुद्धिवाद की जो मशाल जलायी थी, उसका कोई जवाब नहीं था।

समाज सुधार के कार्य

महर्षि दयानन्द का समाज सुधार में व्यापक योगदान रहा। महर्षि दयानन्द ने तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों तथा अन्धविश्वासों और रूढियों-बुराइयों व पाखण्डों का खण्डन व विरोध किया।

सन् 1867 के हरिद्वार के कुम्भ मेले में धर्म प्रचार करने के उद्देश्य से आये थे। इसका कारण था कि कुम्भ के मेले में हिन्दू स्त्री-पुरुष और साधु लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं। यह लोग समझते हैं कि कुम्भ के मेले पर गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को दुःखों व जन्म-मरण से मुक्ति मिल जाती है। हरिद्वार में उन्होंने देखा कि साधु और पण्डे धर्म का उपदेश देकर लोगों को सीधे रास्ते पर लाने के स्थान पर उन्हें पाखण्ड की शिक्षा देकर लूट रह हैं। उन्होंने पाया कि संसार सत्य धर्म पर चलने के स्थान पर अज्ञान के गहरे गड्ढ़े में गिर रहा है।

हरिद्वार में इन दृश्यों को देखकर स्वामी दयानन्द जी को गहरी चोट लगी। उन्होंने पाया कि इन कृत्यों से लोग दुःखों से छूटने के स्थान पर दुःखों के सागर में डूब रहे हैं। अतः उन्होंने साधुओं और पण्डों के इस पाखण्ड की पोल खोलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने छोटे से निवास-स्थान के आगे एक पताका पर 'पाखण्ड-खण्डिनी पताका' लिखकर गाड़ दिया और अपने विचारों को व्याख्यान के रूप में प्रकट करने लगे।

उस समय तक लोगों ने किसी संन्यासी के मुख से मूर्ति-पूजा का विरोध, श्राद्धों का निराकरण, अवतारों में विश्वास, पुराणों का काल्पनि होना आदि बातें नहीं सुनी थी, इसलिए इस दृश्य को विस्मयपूर्वक देखते थे। कुछ लोग इसे कलिकाल का एक लक्षण बतलाते थे। कुछ पंडित नामधारी स्वामी जी को 'नास्तिक' की पदवी भी देने लग जाते थे। कुछ पंडितों और साधुओं ने स्वामी जी के विरुद्ध भाषण देना आरंभ कर दिया और वे उन्हें तरह-तरह की गालियाँ देने लगे। पर स्वामी जी अपने काम में संलग्न रहे। कई पंडित और साधु उनके स्थान पर वाद-विवाद करने के उद्देश्य से भी आते थे, पर उनकी युक्तियुक्त बातों से निरुत्तर होकर चले जाते थे। स्वामीजी सबसे यही कहते थे कि हर की पैड़ी पर नहाने से पाप नहीं धुलते। वेद की शिक्षा पर चलो, अच्छे काम करो, इसी से सुख और मोक्ष मिलेगा। सद्ग्रन्थों का पढ़ना-सुनना और सच्चे धर्मात्माओं की संगति ही सच्चा तीर्थ होती है।

उनके ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश ने समाज को आध्यात्म और आस्तिकता से परिचित कराया। वे योगी थे तथा प्राणायाम पर उनका विशेष बल था। वे सामाजिक पुनर्गठन में सभी वर्णों तथा स्त्रियों की भागीदारी के पक्षधर थे।

अंतिम शब्द

वे अपने पीछे छोड़ गए एक सिद्धान्त, कृण्वन्तो विश्वमार्यम् - अर्थात सारे संसार को श्रेष्ठ मानव बनाओ। उनके अन्तिम शब्द थे - 'प्रभु! तूने अच्छी लीला की। आपकी इच्छा पूर्ण हो।'

2026 के पहले चार हफ्तों में सोने की कीमत में 17 प्रतिशत से अधिक का इजाफा हुआ। सोने और चांदी के भाव में अभूतपूर्व उछाल असल में विश्व अर्थव्यवस्था में युगांतकारी परिवर्तन का सूचक है। यह कोई फौरी समस्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे इस समय हो रहा ढांचागत बदलाव है। इस बदलाव के बाद कैसी व्यवस्था उभरेगी, अभी यह साफ नहीं है।... भविष्य की विश्व मौद्रिक व्यवस्था को लेकर अस्पष्टता बनी हुई है। मगर वर्तमान डॉलर के दिन लद गए हैं, इस संबंध में अब कोई अस्पष्टता नहीं है।

चमकता सोना और डूबता डॉलर

मनोज शर्मा

पिछले 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत प्रति औंस 5000 डॉलर को पार कर गई। उधर चांदी की कीमत भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। (उसके अगले दिन भारतीय बाजार में प्रति दस ग्राम सोने का भाव एक लाख 61 हजार रुपये और प्रति एक किलोग्राम चांदी की कीमत तीन लाख 70 हजार रुपये से ऊपर हो गई थी।) उसके बाद से इन दोनों धातुओं के भाव में बढ़ोतरी का क्रम जारी है। इनके भाव कहां तक जाएंगे, फिलहाल इसका अनुमान किसी को नहीं है।

इसलिए कि इस बात का अंदाजा किसी को नहीं है कि दुनिया की वित्तीय एवं मौद्रिक व्यवस्थाओं में मची उथल-पुथल किस हद तक बढ़ेगी और उसके परिणास्वरूप मूल्य भंडारण (value storage) एवं अंतरराष्ट्रीय भुगतान की कैसी नई व्यवस्थाएं अस्तित्व में आएंगी। अनुमान यही है कि जब तक इस बारे में स्पष्टता नहीं आती, सोना और चांदी के भाव संभवतः बढ़ते ही रहेंगे।

ये दोनों धातु उत्पन्न आर्थिक मूल्य के भंडारण का माध्यम ऐतिहासिक रूप से रहे हैं। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में कई अन्य धातुओं को भी भंडारण का माध्यम बनाया गया, लेकिन जो टिकाऊपन सोना (और एक हद तक चांदी) का रहा, वह बेमुकाबिल है। अभी 55 साल पहले (1971) तक सोना मौद्रिक व्यवस्था का प्रतिमान था। मगर अपनी आर्थिक शक्ति एवं विश्व वर्चस्व की पराकाष्ठा के दौर में अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी (ब्रेटेन वुड्स) व्यवस्था को तोड़ते हुए अपनी मुद्रा यानी डॉलर को ही प्रतिमान बना दिया था। अमेरिका के हैम्पशर राज्य में स्थित ब्रेटन वुड्स में दूसरे विश्व युद्ध के बाद की विश्व मौद्रिक व्यवस्था को स्वरूप दिया गया था। उसके तहत तय किया गया कि अमेरिका अपने भंडार में मौजूद सोने के अनुपात में डॉलर की छपाई करेगा। हर एक औंस डॉलर के बदले वह 35 डॉलर छाप सकेगा। बाकी दुनिया की मुद्राओं की कीमत डॉलर से जुड़ी होगी। यह एक तरह की स्थिर व्यवस्था थी। प्रावधान यह भी था कि कोई भी देश या व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय कारोबार में कमाए गए डॉलर अमेरिका को सौंप कर उसके बदले सोना ले सकेगा। यानी हर 35 डॉलर पर एक औंस सोना।

इस व्यवस्था में मुद्रास्फीति की गुंजाइश नहीं थी। इसलिए कि मुद्रा की अंधाधुंध छपाई संभव नहीं थी। मुद्रा छापने के लिए अपने भंडार में उसी अनुपात में सोना जुटाना अनिवार्य था। मगर इस व्यवस्था को चलाना अमेरिका को भारी पड़ने लगा। अपने यहां कल्याणकारी योजनाओं पर

आमदनी के अनुपात में अधिक खर्च, कोरिया, वियतनाम आदि जैसी जगहों पर युद्ध का बोझ, एवं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सैन्य अड्डे स्थापित करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता के कारण उसके सामने अतिरिक्त डॉलर छापने की मजबूरी आ गई, जिससे उसकी वित्तीय व्यवस्था पर अविश्वास पैदा होने लगा। नतीजतन, जर्मनी जैसे कई देशों को अपने भंडार में डॉलर रखना जोखिम भरा महसूस होने लगा। तो उन्होंने अपने पास मौजूद डॉलर के बदले सोने की मांग शुरू कर दी। इस मांग को पूरा करना अमेरिका को मुनासिब नहीं लगा।

तो अचानक एक दिन- 15 अगस्त 1971 को- तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म करने का एलान कर दिया। इसका अर्थ था कि अब डॉलर की छपाई सोने की उपलब्धता पर निर्भर नहीं रहेगी। ना ही अमेरिका किसी को डॉलर के बदले सोना नहीं देगा। आम सहमति से बनी विश्व वित्तीय व्यवस्था को इस तरह अमेरिका ने मनमाने और एकतरफा ढंग से तोड़ डाला। मगर तब अमेरिका की हैसियत ऐसी थी कि बाकी दुनिया के पास उसके निर्णय को स्वीकार कर लेने के अलावा कोई चारा नहीं था।

इसके तुरंत बाद अमेरिका ने दबाव बना कर पश्चिम एशिया के तेल उत्पादक देशों- खासकर सऊदी अरब को राजी कर लिया कि वे कच्चे तेल की बिक्री सिर्फ डॉलर से भुगतान पर ही करेंगे। इसके बदले अमेरिका ने सऊदी अरब को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी खुद पर ली। इस तरह पेट्रो-डॉलर का सिस्टम वजूद में आया। पश्चिम एशिया के पेट्रोलियम उत्पादक लगभग सभी देश इस सिस्टम में शामिल हो गए। इस व्यवस्था में यह भी अंतर्निहित था कि वो देश जो तेल बेच कर जो डॉलर कमाएंगे, उसका निवेश अमेरिका सरकार के (ट्रेजरी) बॉन्ड्स में करेंगे। इस तरह उन देशों का मूल्य स्वतः अमेरिका पहुंचने लगा।

चूंकि तेल सबको चाहिए, इसलिए सभी देशों के लिए अपने भंडार में डॉलर रखना जरूरी हो गया। फिर यह चलन बढ़ता गया कि तमाम देश कमाए गए डॉलर का निवेश अमेरिकी बॉन्ड्स में करें। तो चलन यह बना कि तमाम देश अपने संसाधन एवं श्रम से जो कमाएंगे, उसका एक हिस्सा अमेरिका में निवेश करेंगे। उधर विभिन्न देश अपने वास्तविक उत्पाद का निर्यात अमेरिका को करेंगे, जबकि उसके बदले अमेरिका उन्हें डॉलर नाम का छपा हुआ कागज एक टुकड़ा देगा। इसे ही फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जिस्कार देस्तां ने अमेरिका का exorbitant privilege कहा था। अमेरिका का वर्चस्व दुनिया पर बना रहा, तो उसके पीछे यही अर्थव्यवस्था रही है। इससे अमेरिका को सभी देशों को अपने मन-माफिक चलाने की ताकत मिली, क्योंकि जो ऐसा नहीं करता, उस पर प्रतिबंध लगा कर डॉलर की व्यवस्था से वह बाहर कर सकता था। और उसने ऐसा किया भी। मगर, जैसा आम तौर पर होता है, किसी भी चीज की अति बुरी होती है। किसी शक्ति का अत्यधिक दुरुपयोग विपरीत परिणाम पैदा करने लगता है। यही डॉलर और प्रकरांतर में अमेरिका के वर्चस्व के साथ हो रहा है। आमदनी से ज्यादा कर्ज लेने की बढ़ती गई प्रवृत्ति और अंधाधुंध नोट की छपाई ने डॉलर के मूल्य में सेंध लगाई है, तो प्रतिबंधों के दुरुपयोग ने विभिन्न देशों को डॉलर में निवेश घटाने के लिए प्रेरित किया है। इन देशों में भारत भी है....

- भारतीय रिजर्व बैंक अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में अपने निवेश को घटा कर पांच साल के निचले स्तर तक ले आया है। भारत ने 2025 में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में अपना निवेश लगभग 21 प्रतिशत घटाया। ट्रेजरी बॉन्ड्स में रिजर्व बैंक की होल्डिंग्स अक्टूबर 2024 में 241।4 बिलियन डॉलर थी। अक्टूबर 2025 में यह 190।7 बिलियन रह गई।
- इस बीच रिजर्व बैंक ने सोने में अपना निवेश बढ़ाया है। रिजर्व बैंक के पास 2023 में लगभग 760 टन सोना था, जो 2025 तक बढ़कर लगभग 880 टन हो गया। मूल्य के लिहाज से यह वृद्धि लगभग 25-30 बिलियन डॉलर की रही। कुल सोने का भंडार नवंबर 2025 में 106।7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था।
- जो रास्ता भारत ने अपनाया है, उस पर ही दुनिया भर के अनेक देश चले हैं। ट्रेजरी बॉन्ड्स में सबसे ज्यादा निवेश घटाने और सोना खरीदने वाला देश चीन रहा है। यहां तक कि पोलैंड जैसे देश ने भी बड़ी मात्रा में सोने की खरीदारी की है।
- इस परिघटना का परिणाम यह है कि 1990 के दशक के बाद अब ऐसा पहली बार हुआ, जब बीते अक्टूबर में तमाम देशों के सेंट्रल बैंकों के भंडार में मौजूद सोने की कीमत उनके ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश से अधिक हो गई। उसके बाद से यह अंतर (सोने के हक में) बढ़ता ही गया है।

और बात सिर्फ सेंट्रल बैंकों की नहीं है। अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी बॉन्ड्स को लेकर निजी निवेशकों का भरोसा भी चूक रहा है। यानी वे भी अमेरिकी बॉन्ड्स बेच कर सोना खरीद रहे हैं। यही कारण है कि सोने के भाव में अभूतपूर्व तेजी आई हुई है। वैसे, ये परिघटना पुरानी है, मगर डॉनल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद नीतियों में बढ़ी अस्थिरता ने इसे और गति प्रदान कर दी है। गौर करेः

- 2026 के पहले चार हफ्तों में सोने की कीमत में 17 प्रतिशत से अधिक का इजाफा हुआ।
- अमेरिका की प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म फ्रट वर के मुख्य अर्थशास्त्री जो। ब्रूसुएलस ने एक न्यूज वेबसाइट से कहा- सोने में बढ़ रहा निवेश मुख्य रूप से अमेरिका सरकार की अप्रत्याशित नीतियों से पैदा हुए जोखिम का परिणाम हैं।
- एसेट एडवाइजरी फर्म Twin Focus के सीईओ पॉल कार्गर ने कहा कि अमेरिका में 'नीतिगत विखंडन' की स्थिति के बीच सोना एक तरह से बीमा का काम कर रहा है।
- विशेषज्ञों के मुताबिक अनेक केंद्रीय बैंक (खासकर यूरोपीय) अभी भी अमेरिकी ट्रेजरी खरीद रहे हैं, लेकिन इन खरीदारियों की गति धीमी हो गई है।
- अनेक ऐसे देश, जो पहले अपनी राशि डॉलर या ट्रेजरी में रखते थे, अब अमेरिका से दूर होकर अपनी पूंजी के भंडारण लिए नए माध्यम ढूंढ रहे हैं। सोना इसमें उनका सबसे भरोसेमंद माध्यम बना है। साथ ही विभिन्न देश अपने विदेशी मुद्रा भंडारों में यूरो (यूरोपियन यूनियन), येन (जापान), युवान (चीन) आदि जैसी मुद्राओं की मात्रा बढ़ा रहे हैं।

सोशल मीडिया: संवाद का माध्यम या निजता का संकट ?

आज संचार क्रांति का युग है।हर कोइ सोशल मीडिया,एआइ का प्रयोग कर रहा है। आधुनिक दौर में सोशल मीडिया ने हमारे अनेक कार्यों को आसान और सरल बनाया है। दूसरे शब्दों में कहें तो सोशल मीडिया ने संवाद को जितना सरल और व्यापक बनाया है, उतना ही जटिल निजता का प्रश्न भी खड़ा कर दिया है। आज व्यक्ति अपने जीवन के निजी क्षण-तस्वीरें,रील बनाकर अपने विचार, स्थान और दिनचर्या स्वेच्छा से सार्वजनिक मंचों पर साझा कर रहा है। यह सब आमतौर पर सोशल मीडिया मंचों पर साझा करना कभी-कभी आत्म-अभिव्यक्ति

एन के शर्मा

का माध्यम होता है, तो कई बार अनजाने में अपनी निजता को जोखिम में डालने का कारण बन जाता है। 'लाइक' और 'व्यू' की होड़ में निजी सीमाएँ धुंधली होती जा रही हैं। यहां यदि हम सरल शब्दों में कहें तो आज के समय में तकनीक हमारी ज़िंदगी की पल-पल की अहम व महत्वपूर्ण जरूरत बन चुकी है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने काम आसान और तेज कर दिए हैं, लेकिन इसके साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ा है-निजता का खतरा। आज के समय में अधिकांश लोगों के पास स्मार्टफोन है और वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि ऐप या प्लेटफॉर्म पर साइन-अप करते समय जो निजी जानकारी वे देते हैं, उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। कई बार यह जानकारी हमारी अनुमति के बिना किसी और को दी जा सकती है। बहरहाल,यहां पाठकों को बताता चलूं कि भारत ही नहीं आज संपूर्ण विश्व स्तर पर स्मार्टफोन

उपयोग तेजी से सर्वव्यापी हो चुका है। 2025 के आसपास उपलब्ध ताजा वैश्विक अनुमानों के अनुसार दुनिया में लगभग 6.8-7.1 अरब लोग स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं, जबकि सक्रिय स्मार्टफोन डिवाइसों की संख्या 7 अरब से अधिक मानी जाती है, क्योंकि कई उपयोगकताओं के पास एक से अधिक फोन हैं।

इसका अर्थ यह है कि वैश्विक आबादी का करीब 85-90 प्रतिशत हिस्सा किसी न किसी रूप में स्मार्टफोन से जुड़ चुका है। यदि हम यहां पर भारत की बात करें तो देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन चुका है। साल 2024-2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्मार्टफोन उपयोगकताओं की संख्या लगभग 65-70 करोड़ (650-700 मिलियन) है, जो कुल जनसंख्या का करीब 45-50 प्रतिशत बैठती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और 4जी/5जी नेटवर्क के विस्तार के कारण यह संख्या तेजी से बढ़ रही है और विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार 2026 तक भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ता 100 करोड़ के आसपास पहुँच सकते हैं। इस क्रम में यहां यह गौरतलब है कि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और व्हाट्सऐप को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी कंपनी नागरिकों की निजी जानकारी के साथ मनमानी नहीं कर सकती और निजता के अधिकार से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज का जमाना डिजिटल है और इस डिजिटल युग में आज मोबाइल नंबर, बैंक खाता, आधार जैसी जगहों पर हमें अपनी निजी और कभी-कभी बायोमेट्रिक जानकारी भी देनी पड़ती है। अगर यह जानकारी गलत हाथों में चली जाए, तो बड़ा नुकसान हो सकता है। समस्या यह भी है कि यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि हमारी जानकारी आखिर कहां-कहां पहुंच चुकी है।सोशल मीडिया पर भी यही खतरा रहता है, क्योंकि ज्यादातर लोग नियम और शर्तें पढ़े बिना ही 'सहमति' दे देते हैं।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में यह बात कही कि ये शर्तें इतनी जटिल भाषा में लिखी जाती हैं कि आम आदमी उन्हें समझ ही नहीं पाता। इसे निजी जानकारी चुराने का एक 'सभ्य तरीका' कहा गया, जिसे मंजूरी नहीं दी जा सकती। माननीय कोर्ट ने यह भी कहा कि सुरक्षा और पहचान के नाम पर जानकारी लेना ठीक है, लेकिन जो लोग निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता की गतिविधियों का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं-क्या देखा, क्या पसंद किया, कहाँ गए और इस डेटा का उपयोग विज्ञापन, प्रोफाइलिंग और कभी-कभी राजनीतिक या व्यावसायिक हितों के लिए किया जाता है।

वास्तव में, डेटा लीक, अनधिकृत ट्रैकिंग और फेक प्रोफाइल जैसी समस्याएँ निजता के हनन को और गंभीर बनाती हैं। परिणामस्वरूप व्यक्ति की पहचान, सुरक्षा और स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निजता का हनन केवल तकनीकी नहीं, सामाजिक समस्या भी है। बिना अनुमति तस्वीरें साझा करना, ट्रोलिंग, साइबर स्टॉकिंग और ऑनलाइन बदनामी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं।

बच्चों और किशोरों के लिए यह खतरा और बड़ा है, क्योंकि वे डिजिटल जोखिमों को समझे बिना ही ऑनलाइन सक्रिय हो जाते हैं।इस चुनौती का समाधान बहुस्तरीय है। एक ओर सशक्त डेटा संरक्षण कानून, पारदर्शी प्लेटफॉर्म नीतियाँ और कड़ी जवाबदेही आवश्यक है; दूसरी ओर डिजिटल साक्षरता और व्यक्तिगत सावधानी भी उतनी ही जरूरी है-मजबूत पासवर्ड, गोपनीयता सेटिंग्स, सीमित साझा करना और अनुमति की संस्कृति। सोशल मीडिया का विवेकपूर्ण उपयोग ही निजता और अभिव्यक्ति के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है।

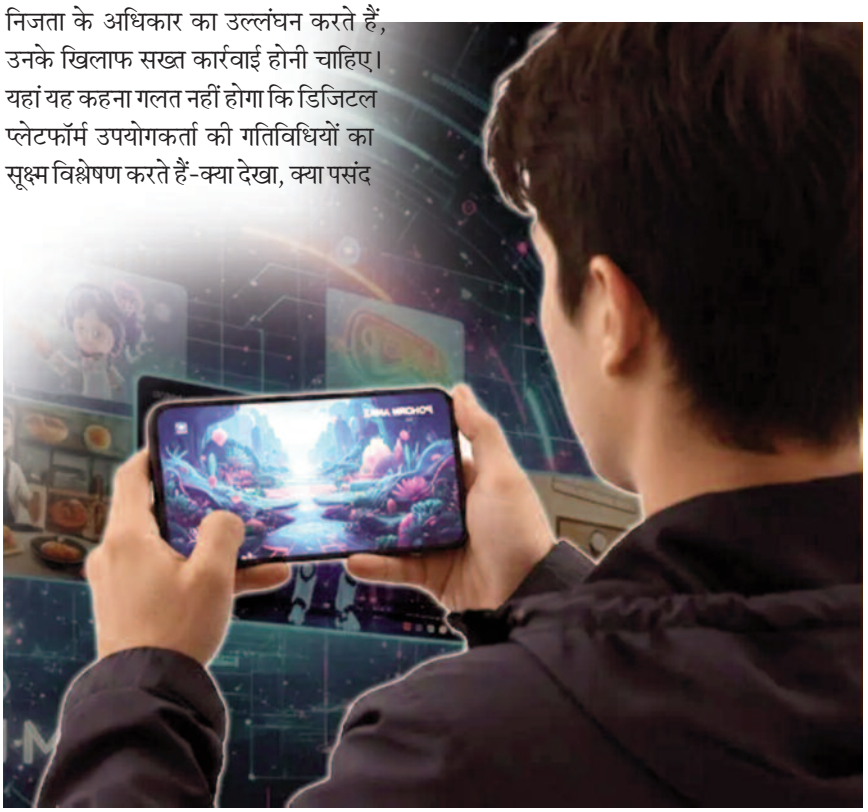

विंटर में हेयर फाल का असली कारण जानें, गर्म पानी और ड्रायर हैं सबसे बड़े विलेन

बालों के झड़ने की वजह

स्कैल्प का सूखा होना

सर्दियों में हवा में नमी की कमी हो जाती है, जिस कारण स्कैल्प सूखने लगता है। सूखा स्कैल्प बालों की जड़ों को सही तरीके से पोषण नहीं दे पाता है, जिससे बाल कमजोर हो जाते हैं और हेयर फॉल होने लगता है।

गर्म पानी से नहाना

सर्दियों के मौसम में अधिकतर लोग गर्म पानी से नहाते हैं, जिससे बालों को नुकसान पहुंचता है। गर्म पानी के कारण बालों में मौजूद प्राकृतिक तेल हट जाता है, जिस कारण बाल और स्कैल्प सूखने लगते हैं और इस मौसम में बाल झड़ने लगते हैं।

स्टेटिक और रूखे बाल

सर्दियों में हवा में नमी होने के कारण बालों में स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है। यह बालों को अधिक कमजोर बनाता है। जिससे आपके बाल झड़ने और टूटने लगते हैं।

ऐसे करें बालों की देखभाल

नारियल तेल से स्कैल्प की मालिश करें

बालों को मजबूत और हेल्दी बनाए रखने के लिए आप स्कैल्प की नारियल तेल से मालिश करें। नारियल तेल बालों को हाइड्रेट करता है और जड़ों तक पोषण पहुंचाता है। इससे भी बालों का झड़ना कम होता है।

गुनगुने पानी से हेयर वॉश

सर्दी में में बालों को गर्म पानी से धोने से बचना चाहिए। इसकी जगह आप गुनगुने पानी से बाल धो सकती हैं। इससे बालों की नमी बनी रहती है और बालों का टूटना भी कम होता है।

माइल्ड शैंपू और कंडीशनर

सर्दियों के मौसम में बालों की नमी बनाए रखने के लिए माइल्ड शैंपू और मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर का इस्तेमाल करें। यह बालों को हाइड्रेट रखने में सहायता करता है। साथ ही यह बालों की संरचना को मजबूत बनाए रखता है।

सर्दियों के मौसम में बालों का झड़ना एक आम समस्या बन जाती है। इस समस्या से कई लोग परेशान रहते हैं।

इस मौसम में न सिर्फ बालों का गिरना बढ़ता है, बल्कि बालों की हालत भी कमजोर और रूखी हो जाती है। सर्दी के मौसम में हवा में नमी की कमी, ठंडी हवाएं और घर में हीटर आदि के इस्तेमाल से बालों को काफी नुकसान होता है। हालांकि सर्दियों में लोग बालों की देखभाल को नजरअंदाज कर देते हैं। जिस कारण हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है।

सर्दियों में बालों के झड़ने की समस्या न सिर्फ बाहरी बल्कि अंदर से भी होती है। कई बार बालों को सही देखभाल और पोषण न मिल पाने की वजह से बाल जल्दी टूटने और गिरने लगते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको इस समस्या से निपटने के लिए कुछ आसान उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको अपनाकर आप सर्दियों में भी बालों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रख सकते हैं।

जिद्दी ब्लैकहेड्स को जड़ से मिटाएंगे ये असरदार ब्यूटी टिप्स, बिना दर्द मिलेगा नेचुरल ग्लो

ब्लैकहेड्स अधिकतर नाक, माथे और ठुड्डी पर नजर आते हैं। ब्लैकहेड्स को कील भी कहा जाता है। नाक पर ब्लैकहेड्स नजर आते हैं, तो स्किन दानेदान और खुरदरी दिखने लगती है। बता दें कि ब्लैकहेड्स तब नजर आते हैं, जब डेड स्किन सेल्स और ऑयल त्वचा के छिद्रों में जम जाते हैं और स्किन की सतह पर आ जाते हैं।

इससे त्वचा पर ब्लैकहेड्स दिखना शुरू हो जाते हैं। अगर इनको किसी टूल से निकाला जाए, तो इसमें दर्द भी होता है और ब्लैकहेड्स दोबारा उतनी ही तेजी से निकल आते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको ब्लैकहेड्स को हटाने के कुछ रामबाण तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं।

अगर ब्लैकहेड्स को किसी टूल से निकाला जाए, तो इसमें दर्द भी होता है और ब्लैकहेड्स दोबारा उतनी ही तेजी से निकल आते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको ब्लैकहेड्स को हटाने के कुछ रामबाण तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं।

नाक के ब्लैकहेड्स हटाने के उपाय

बेकिंग सोडा

ब्लैकहेड्स हटाने के लिए बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को ब्लैकहेड्स पर लगाएं और 10 मिनट लगाए रखने के बाद हल्के हाथों से रगड़ते हुए मलें। फिर धोकर इसको हटा लें। बेकिंग सोडा का यह मिश्रण नाक पर जमे जिद्दी ब्लैकहेड्स को कम करता है।

अंडे की सफेदी

अंडे की सफेदी एक अच्छे पील ऑफ मास्क के रूप में काम करता है। नाक पर अंडे के सफेद हिस्से को लगाएं और इस पर टिशू पेपर की पतली लेयर अप्लाई करें। फिर 10 से 15 मिनट बाद नाक से टिशू को हटा लें। अंडे की सफेदी और टिशू से ब्लैकहेड्स चिपककर हट जाएगी।

चीनी और नमक का स्क्रब लगाएं

ब्लैकहेड्स को आसानी से रिमूव करने के लिए एक कटोरी में शहद और चीनी या फिर नमक में तेल मिलाकर स्किन पर हल्के हाथों से स्क्रब करें। इससे नाम पर नजर आने वाले ब्लैकहेड्स पर अप्लाई करें। इस स्क्रब से स्किन एक्सफोलिएट होती है और ब्लैकहेड्स आसानी से रिमूव हो जाते हैं।

ओट्स से करें क्लेंज

सप्ताह में 2 से 3 बार त्वचा को क्लेंज किया जाए, तो नाक पर जमे जिद्दी ब्लैकहेड्स हटते हैं। त्वचा तो क्लेंज करने के लिए किसी अच्छे क्लेंजर या फिर ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओट्स को पीसकर इसमें डालें और फिर इस पेस्ट को फेस पर मलकर हल्के से मलें और फेसवॉश कर लें।

तनाव, आतंक और अंधकार के बीच शिव का प्रकाश

शिव का स्वरूप द्वंद्वों से परे है। वे संहारक भी हैं और सृजनकर्ता भी। यह संदेश आज के समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो जड़, जर्जर और अनैतिक है, उसका विनाश आवश्यक है ताकि नवजीवन अंकुरित हो सके। जब हम अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह का संहार करते हैं, तभी सच्चा निर्माण संभव होता है।

मुहम्मद परवेज अख्तर
संतकबीरनगर

15 फरवरी 2026 को जब समूचा भारत महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाएगा, तब यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगा, बल्कि आत्मजागरण का विराट अवसर होगा। महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब साधक अपने भीतर के अंधकार को पहचानकर शिवत्व के प्रकाश से उसे आलोकित करने का संकल्प लेता है। शिव केवल देवता नहीं, वे चेतना के शाश्वत आयाम हैं-महाकाल, जो समय से परे हैं, नटराज, जो सृष्टि की लय और ताल के अधिपति हैं और नीलकंठ, जो विष को पीकर भी अमृत का संदेश देते हैं। आज का युग विज्ञान, तकनीक और उपभोग का युग है। मानव ने अंतरिक्ष को नापा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित की, लेकिन अपने भीतर की शांति खो बैठा। तनाव, अवसाद, असंतोष, युद्ध, आतंकवाद और नैतिक विघटन की घटनाएँ विश्व को विचलित कर रही हैं। ऐसे दौर में शिव की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। शिव भक्ति कोई चमत्कारिक जादू नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित करने का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मार्ग है।

शिव का स्वरूप द्वंद्वों से परे है। वे संहारक भी हैं और सृजनकर्ता भी। यह संदेश आज के समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो जड़, जर्जर और अनैतिक है, उसका विनाश आवश्यक है ताकि नवजीवन अंकुरित हो सके। जब हम अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह का संहार करते हैं, तभी सच्चा निर्माण संभव होता है। यही शिव का वास्तविक चमत्कार है भीतर के विष का रूपांतरण। समुद्र-मंथन की कथा केवल पौराणिक आख्यान नहीं, बल्कि मानवीय जीवन का प्रतीक है। जब संसार अमृत की खोज में लगा, तब सबसे पहले विष निकला। आज भी जब मानव प्रगति की दौड़ में है, तो साथ में प्रदूषण, हिंसा और असंतुलन का विष भी उत्पन्न हो रहा है। उस विष को कौन पियेगा? शिव का नीलकंठ रूप हमें सिखाता है कि समाज के संकट को दूर करने के लिए त्याग और सहनशीलता आवश्यक है। जब हम अपने स्तर पर

कटुता को निगल लेते हैं और उसे बाहर नहीं फैलाते, तभी समाज में शांति बनी रहती है। इसी प्रकार गंगा के अवतरण की कथा बताती है कि अनियंत्रित शक्ति विनाशकारी हो सकती है। शिव ने उसे अपनी जटाओं में धारण कर संतुलित प्रवाह दिया। आज के संदर्भ में यह संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। तकनीक, धन, सत्ता-ये सभी शक्तियाँ हैं। यदि वे अनियंत्रित हों तो विध्वंसक बनती हैं, और यदि शिव-संयम में हों तो कल्याणकारी। अतः शिव भक्ति का अर्थ है-शक्ति का संतुलन।

आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है-तनाव। प्रतिस्पर्धा, अपेक्षाएं और असुरक्षा ने उसे अशांत बना दिया है। शिवरात्रि की रात्रि जागरण की रात्रि है, लेकिन यह बाह्य जागरण से अधिक आंतरिक जागरण है। जब साधक 'ॐ नमः शिवाय' का जप करता है, तो वह अपने भीतर के कंपन को संतुलित करता है। यह पंचाक्षरी मंत्र मन, प्राण और चेतना को एकाग्र करता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि नियमित ध्यान और मंत्रजाप से तनाव कम होता है, रक्तचाप संतुलित होता है और मानसिक स्थिरता बढ़ती है। यह शिव साधना का प्रत्यक्ष प्रभाव है। शिव पुराण में वर्णित है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की निशीथ बेला में ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। यह ज्योति केवल पत्थर की आकृति नहीं, बल्कि अनंत प्रकाश का प्रतीक है। शिवलिंग का अर्थ है-चिह्न, जो निराकार ब्रह्म का संकेत देता है। आधुनिक मनुष्य के लिए यह बोध आवश्यक है कि ईश्वर किसी सीमित रूप में बंधा नहीं है। वह ऊर्जा है, चेतना है, जो प्रत्येक कण में विद्यमान है।

आज विश्व युद्ध और आतंकवाद की विभीषिका से जूझ रहा है। हिंसा की ज्वाला में मानवता झुलस रही है। शिव का तांडव केवल विनाश नहीं, बल्कि संतुलन का नृत्य है। जब अन्याय बढ़ता है, तब परिवर्तन अनिवार्य होता है। किंतु शिव का संदेश यह भी है कि क्रोध नहीं, करुणा से परिवर्तन संभव है। वे रुद्र हैं-दुःखों का हरण करने वाले। शिव भक्ति का चमत्कार यह है कि वह मनुष्य के भीतर करुणा, सहिष्णुता और क्षमा का विकास करती है। जब व्यक्ति बदलता है, तब समाज बदलता है और जब समाज बदलता है, तब विश्व में शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। शिव और शक्ति का मिलन भी आधुनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह पुरुष और प्रकृति, चेतना और ऊर्जा, विचार और क्रिया का समन्वय है। आज परिवारों में विघटन, संबंधों में दूरी और जीवन में असंतुलन इसलिए है क्योंकि यह समरसता टूट रही है। शिवरात्रि हमें स्मरण कराती है कि संतुलन ही जीवन का आधार है। व्रत और उपवास का आध्यात्मिक महत्व भी आज समझने योग्य है। उपवास केवल भोजन त्याग नहीं, बल्कि इंद्रियों का संयम है। यह आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति एक दिन के लिए भी भोगों से दूर रहता है, तो उसे अपनी आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। उपभोक्तावादी संस्कृति में यह अत्यंत आवश्यक साधना है।

शिव भक्ति का सिद्ध प्रभाव उन असंख्य भक्तों के अनुभवों में दिखाई देता है, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी आस्था नहीं छोड़ी। सच्चे मन से की गई प्रार्थना व्यक्ति को आंतरिक शक्ति देती है। यह शक्ति उसे संकटों से जूझने का साहस देती है। चमत्कार बाहर नहीं, भीतर घटित होता है-जब निराशा आशा में बदलती है, भय विश्वास में और अशांति शांति में। आज आवश्यकता है कि शिव को केवल मंदिरों तक सीमित न रखा जाए। वे काठ, पत्थर या मूर्ति में नहीं, बल्कि भाव में निवास करते हैं। जब हम सत्य बोलते हैं, करुणा का व्यवहार करते हैं, प्रकृति की रक्षा करते हैं, तब हम शिव की आराधना करते हैं। पर्यावरण संरक्षण भी शिव भक्ति है, क्योंकि वे कैलाशवासी योगी हैं, प्रकृति के संरक्षक हैं। जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी के संतुलन की रक्षा करना ही शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा है।

महाशिवरात्रि 2026 हमें यह संकल्प लेने का अवसर देती है कि हम अपने भीतर के विष को पहचानें और उसे शिवचेतना में रूपांतरित करें। हम अपने जीवन में संयम, संतुलन और साधना को स्थान दें। हम क्रोध के स्थान पर क्षमा, अहंकार के स्थान पर विनम्रता और अशांति के स्थान पर ध्यान को अपनाएं। शिवत्व की प्राप्ति कोई दूर की वस्तु नहीं। यह हमारे भीतर ही सुप्त है। आवश्यकता केवल जागरण की है। जब मनुष्य स्वयं को जीत लेता है, तभी वह सच्चे अर्थों में विजयी होता है। यही आत्मयुद्ध है, यही शिव की साधना है। इस महाशिवरात्रि पर हम सब मिलकर यह प्रार्थना करें-

'हे नीलकंठ! हमारे भीतर के विष को शांत करो।
हे महाकाल! हमें समय का सदुपयोग सिखाओ।
हे शंकर! हमारे जीवन में कल्याण का संचार करो।'

जब यह प्रार्थना सच्चे मन से होगी, तब निश्चित ही उसका प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि शिव भाव के भूखे हैं। जहाँ निष्कपट श्रद्धा है, वहाँ शिव की कृपा अवश्य बरसती है। आधुनिक युग की जटिलताओं के बीच शिव भक्ति ही वह सेतु है, जो मनुष्य को स्वयं से, समाज को शांति से और विश्व को अमन से जोड़ सकती है। यही महाशिवरात्रि का सच्चा संदेश है-अंधकार से प्रकाश की ओर, अशांति से शांति की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर।

हाई बीपी का नया टारगेट बच्चे और युवा

हार्ट अटैक से बचना है तो जानें उम्र के हिसाब से सही रीडिंग

डॉ. निमित त्यागी

गलत खानपान, लाइफस्टाइल में गड़बड़ी, फिजिकल एक्टिविटी में कमी, तनाव और नींद की अनियमितता की वजह से हाई बीपी की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीपी का नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए।

अगर आप भी शरीर को सेहतमंद बनाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों को कंट्रोल में रखें। क्योंकि ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर बढ़ने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। जिन लोगों का अक्सर बीपी हाई रहता है, उनको तंत्रिकाओं, आंखों और किडनी से संबंधित दिक्कतें होने का खतरा रहता है। वहीं यह हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक जैसी समस्याओं की वजह बन सकती है। हाई बीपी को हेल्थ एक्सपर्ट 'साइलेंट किलर' भी कहते हैं। क्योंकि इसके लक्षण लंबे समय तक सामने नहीं आते हैं। यह अंदर ही अंदर शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचाता है। गलत खानपान, लाइफस्टाइल में गड़बड़ी, फिजिकल एक्टिविटी में कमी, तनाव और नींद की अनियमितता की वजह से हाई बीपी की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीपी का नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए और कब आपको सावधान होने की जरूरत होती है।

हाई बीपी की समस्या

हेल्थ एक्सपर्ट की मानें, तो बीपी वह दबाव है, जो ब्लड सकुर्लेशन के दौरान हमारी रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर पड़ता है। समस्या यह है कि अधिकतर मामलों में व्यक्ति को इस समस्या का तब तक पता नहीं चलता है, जब तक कोई गंभीर समस्या सामने न आ जाए।

वहीं समय रहते इनके लक्षणों को पहचान करना और साथ ही इसको कंट्रोल करने के उपाय करना चाहिए। जिससे कि दिल, दिमाग, आंखों और किडनी को होने वाले स्थायी नुकसान से बचा जा सके।

इसके नियमित अंतराल पर अपने बीपी को चेक करते रहें। ऐसे में आइए जानते हैं इसकी रीडिंग कितनी होनी चाहिए।

कितनी होनी चाहिए बीपी रीडिंग

बता दें कि 18 साल से अधिक के लोगों के लिए सामान्य बीपी 120/80 mmHg माना जाता है।

- छोटे बच्चे, जिनकी उम्र 5 से 12 साल के बीच है, उनका बीपी करीब 90/60 से 110/70 mmHg के बीच होना चाहिए।
- बच्चों में बीपी लंबाई, उम्र और वजन पर निर्भर करता है।
- इसी तरह से वयस्कों की शारीरिक स्थिति और वेट के हिसाब से ब्लड प्रेशर की रीडिंग अलग हो सकती है।
- अगर इससे ज्यादा की रीडिंग लंबे समय तक बनी रहती है, तो आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए।

बच्चों के क्यों जरूरी बीपी की जांच

हेल्थ एक्सपर्ट ने एक अध्ययन में पाया कि उम्र बढ़ने के साथ हृदय रोगों की समस्या से बचे रहने के लिए जरूरी है कि आप नियमित रूप से बच्चों के बीपी की जांच की जाती रहे। वहीं नए अध्ययन में पाया गया है कि 10 साल के कम उम्र के बच्चों में भी हाइपरटेंशन के मामले बढ़ते जा रहे हैं।

वहीं 7 साल के बच्चों में उच्च रक्तचाप की समस्या थी। इनमें 50 साल की उम्र तक हृदय रोगों से मृत्यु का खतरा 50% तक ज्यादा था। यानी की अगर कम उम्र से ही ब्लड प्रेशर पर ध्यान दिया जाए, तो यह भविष्य में हृदय संबंधित खतरों को कम करने में सहायक हो सकती है।

महंगे प्रोबायोटिक भूल जाएं
बस 10 रुपए में सुधारें अपना हेल्थ

डॉ. मुकुल शर्मा

अगर आपका पेट ठीक है, तो इम्यूनिटी, दिमाग और मूड सब सही रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेट को हेल्दी रखने के लिए आपको किसी महंगे प्रोबायोटिक की जरूरत नहीं है, बस आपको कुछ सादे और सस्ते फर्मेंटेड फूड्स ही काफी हैं।

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने स्वास्थ्य का सही तरीके से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। जिस कारण लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खराब खानपान की वजह से पेट को ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे में अधिकतर लोग गैस, पेट की तकलीफ या कब्ज जैसी दिक्कतों से परेशान रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा पेट यानी की गट ही हमारी पूरी सेहत की जड़ है। अगर आपका पेट ठीक है, तो इम्यूनिटी, दिमाग और मूड सब सही रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेट को हेल्दी रखने के लिए आपको किसी महंगे प्रोबायोटिक की जरूरत नहीं है, बस आपको कुछ सादे और सस्ते फर्मेंटेड फूड्स ही काफी हैं। जो 10 रुपए से कम में आपका पेट फिट रख सकते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको तीन आसान फर्मेंटेड फूड के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं।

यह एक सस्ती, देसी और असरदार रेसिपी है। जोकि पेट की सफाई तो करती है, साथ ही यह डाइजेशन को भी बेहतर बनाता है। फर्मेंटेड राइस कांजी बनाने के लिए दो चम्मच पके हुए चावल और दो चम्मच दही को एक गिलास पानी में मिलाना होगा।

इसको रातभर ढककर रख दें, जिससे कि यह फर्मेंट हो जाए। अब सुबह इसको अच्छे से मसलें या फिर ब्लेंड कर लें।

इसके बाद इसमें नमक डालें और चाहें तो बारीक कटी हरी मिर्च और प्याज डाल सकती हैं। अब इसको डाइट में शामिल करें, इसमें मौजूद नेचुरल बैक्टीरिया आंतों की लाइनिंग को हील करते हैं और डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं।

वहीं रागी अपने आप में एक सुपरफूड है। जब इसको फर्मेंट किया जाता है, तो इसका फायदा दोगुना

हो जाता है। रागी कांजी बनाने के लिए आपको 4 चम्मच रागी आटे में आधा कप पानी मिलाकर पतला सा घोल तैयार कर लें।

फिर एक पैन में दो कप पानी उबालें और धीरे-धीरे रागी घोल डालते हुए चलाते रहें। अब करीब 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। जब यह ठंडा हो जाए, तो इसको कांच या मिट्टी के बर्तन में डालें। इसको रात भर ढककर रखें। सुबह इसमें थोड़ा सा नमक, मट्ठा, हरी मिर्च और प्याज डालकर पिएं। इसमें मौजूद आयरन, कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स हड्डियों और पेट दोनों के लिए फायदेमंद है।

बता दें कि अगर आप जल्दी में हैं, तो यह सबसे आसान तरीका है। लंच के बाद एक कटोरी दही खाएं। अगर आ ग्रीक योगर्ट लेते हैं, तो इसमें 12 ग्राम तक प्रोटीन भी मिलता है, यह शरीर को एनर्जी देता है और पाचन को आसान बनाता है।

रानी मुखर्जी

सिनेमा के 30 साल और निडर सफर!

भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक, रानी मुखर्जी ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने शानदार तीन दशक पूरे कर लिए हैं। 'राजा की आएगी बारात' से शुरू हुआ यह सफर आज उस मुकाम पर है जहाँ वे अपनी शर्तों पर फिल्में चुनती हैं। हाल ही में एक बातचीत के दौरान रानी ने अपनी यात्रा, सिनेमा के प्रति अपने साहस और बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मदार्नी 3' पर दिल खोलकर चर्चा की। एक्ट्रेस ने यश राज फिल्म्स के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक पर्सनल नोट शेयर करके इस मील के पत्थर को सेलिब्रेट किया। उन्होंने अपने करियर पर बात की, और कहा कि यह इंस्टिंक्ट से बना है, न कि एम्बिशन से। मुखर्जी ने अपनी जर्नी को कहानी कहने के प्यार, इमोशनल ईमानदारी और एक ऐसी मजबूती से भरा बताया जिसने सालों से उनके फैसलों को तय किया है। इस पल को 'अनरियल' बताते हुए, मुखर्जी ने लिखा कि समय बहुत जल्दी बीत गया क्योंकि उन्होंने एक्टिंग को कभी मंज़िल नहीं माना। उन्होंने कहा, 'मैं फिल्मों में कोई मास्टर प्लान लेकर नहीं आई थी,' यह याद करते हुए कि सिनेमा उन्हें लगभग इत्तेफाक से मिला। अपनी पहली फिल्म के सेट पर एक नर्वस लड़की से लेकर हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा फीमेल स्टार्स में से एक बनने तक, उन्होंने खुद को अभी भी उस शुरूआती कमजोरी और जिज्ञासा को हर रोल में ले जाने वाला बताया।

एक्ट्रेस ने यश राज फिल्म्स के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक पर्सनल नोट शेयर करके इस मील के पत्थर को सेलिब्रेट किया। उन्होंने अपने करियर पर बात की, और कहा कि यह इंस्टिंक्ट से बना है, न कि एम्बिशन से।

सिनेमा और साहस का संगम

'ब्लैक' से लेकर 'हिचकी' और 'मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे' तक, रानी ने हमेशा चुनौतीपूर्ण भूमिकाएँ चुनी हैं। उन्होंने कहा कि एक अभिनेत्री के तौर पर उनका साहस तब दिखता है जब वे व्यावसायिक सफलता के बजाय सार्थक सिनेमा को चुनती हैं। 30 वर्षों के इस पड़ाव पर भी वे उतनी ही ऊजार्वान हैं और मानती हैं कि सिनेमा को सामाजिक बदलाव का जरिया होना चाहिए। मुखर्जी ने राजा की आएगी बारात (1997) से डेब्यू किया, एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में वह कहती हैं कि इसने सिनेमा को ग्लैमर नहीं, बल्कि ज़िम्मेदारी के तौर पर समझने में मदद की। अपने करियर की शुरूआत में गरिमा के लिए लड़ने वाली महिला का किरदार निभाने का उन किरदारों पर गहरा असर पड़ा जिनकी तरफ वह बाद में आकर्षित हुईं -- ऐसी महिलाएं जो सिस्टम को चुनौती देती हैं, पितृसत्ता पर सवाल उठाती हैं, और पीछे हटने से इनकार करती हैं। उन्होंने याद किया कि 1990 के दशक का आखिर का समय, न सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि इमोशनली भी, बदलाव लाने वाला था। उन्होंने कहा कि उस दौर की फिल्मों ने उन्हें यह समझने में मदद की कि हिंदी सिनेमा लोगों की ज़िंदगी में कैसे जुड़ा हुआ है। उन्होंने लिखा, 'दर्शक ही आपकी किस्मत तय करते हैं,' अपनी जर्नी को आकार देने का श्रेय दर्शकों को देते हुए।

रश्मिका मंदाना 26 फरवरी को विजय देवरकोंडा से करेंगी शादी

एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इस साल 26 फरवरी को शादी करने वाले हैं। हालांकि शादी की जगह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि दोनों उदयपुर में एक डेस्टिनेशन वेडिंग में शादी कर रहे हैं। कपल 3 मार्च को हैदराबाद में एक वेडिंग रिसेप्शन होस्ट करेगा।

एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इस साल 26 फरवरी को शादी करने वाले हैं। हालांकि शादी की जगह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि दोनों उदयपुर में एक डेस्टिनेशन वेडिंग में शादी कर रहे हैं। कपल 3 मार्च को हैदराबाद में एक वेडिंग रिसेप्शन होस्ट करेगा।

मीडिया में शेयर हो रहे एक वेडिंग रिसेप्शन इनवाइट में कपल के शेयर्ड जर्नी के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि वे उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करने में कैसे विश्वास करते हैं जो इसका हिस्सा रहे हैं। देवरकोंडा की ओर से भेजे गए इनवाइट में रिसेप्शन की जगह का ज़िक्र है, और यह भी बताया गया है कि सेलिब्रेशन शाम 7 बजे से शुरू होगा।

वेडिंग रिसेप्शन इनवाइट में क्या है: 'मैं कुछ खास खबरें शेयर करने और आपको हमारी ज़िंदगी के एक बहुत बड़े पल का हिस्सा बनने के लिए इनवाइट करने के लिए लिख रहा हूँ। हमारे परिवारों के प्यार और आशीर्वाद से, रश्मिका और मैं 26.02.26 को एक छोटी और छोटी सी सेरेमनी में शादी करेंगे।

जैसे ही हम यह नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं- अपने रिश्ते को सेलिब्रेट करना और यादें बनाना -- हमारे लिए उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करना सच में बहुत मायने रखेगा जो हमारे सफर का हिस्सा रहे हैं। आपकी मौजूदगी और आशीर्वाद इस मौके को हमारे लिए और भी खास बना देंगे। हम आपको हमारे वेडिंग रिसेप्शन में शामिल होने और हमें आशीर्वाद देने के लिए दिल से इनवाइट करते हैं। हम साथ में सेलिब्रेट करने का इंतजार कर रहे हैं।'

हैदराबाद में होगा भव्य रिसेप्शन

शादी भले ही राजस्थान में हो रही हो, लेकिन जश्न का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा। शादी के कार्ड के अनुसार, 4 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित ताज कृष्णा (Taj Krishna) होटल में एक भव्य रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा। हाल ही में 'अर्जुन रेड्डी' स्टार विजय देवरकोंडा को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते देखा गया था। रिपोर्ट्स की मानें तो विजय व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री को अपनी शादी का निमंत्रण देने पहुंचे थे।

महमूद रजा
बिजनौर

11 साल की आतिका ने मुश्किल हालात में रचा इतिहास, लहराया भारत का परचम

भारतीय मोटरस्पोर्ट जगत से एक प्रेरक खबर सामने आई है, जहां महज 11 वर्ष की उम्र में आतिका ने अंतरराष्ट्रीय कार्टिंग सर्किट पर अपनी प्रतिभा का दमदार परिचय दिया है। मिनी वर्ग से सीधे जूनियर कैटेगरी में स्वैच्छिक रूप से कदम रखना अपने आप में बड़ा जोखिम माना जाता है, लेकिन आतिका ने शुरूआती दौर में ही उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर सबका ध्यान खींचा है।

बता दें कि 2026 सत्र में वह यूरोप की कड़ाके की ठंड और अपरिचित ट्रैकों पर प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। डब्ल्यूएसके सुपर मास्टर्स श्रृंखला के शुरूआती चरण में क्वालीफाइंग में दूसरा स्थान हासिल कर उन्होंने पैडॉक में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। गौरतलब है कि इस ग्रिड पर वह इकलौती महिला ड्राइवर हैं। इसके बाद इटली के प्रतिष्ठित सर्किट डि नेपोली में गीली और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में छठा सबसे तेज समय निकालना उनकी परिपक्वता को दशार्ता है। रेस के दौरान 45 से अधिक काट्र्स के बीच 16 स्थानों की बढ़त बनाना उनके आत्मविश्वास और रेस क्राफ्ट का प्रमाण है।

मौजूद जानकारी के अनुसार, मिनी वर्ग (8-12 वर्ष) से ओकेएनजे जूनियर (12-14 वर्ष) में जाना तकनीकी रूप से बड़ा बदलाव है। जूनियर काट्र्स का वजन लगभग 30 किलोग्राम अधिक होता है और इनकी शक्ति लगभग तीन गुना तक बढ़ जाती है। ऐसे में कम उम्र में इस स्तर की मशीनरी को संभालना आसान नहीं माना जाता।

आतिका के कोच फेलिसे टिएने, जिन्हें कार्टिंग जगत के अनुभवी मार्गदर्शकों में गिना जाता है, ने उनकी कार्यशैली और सीखने की क्षमता की सराहना की है। उन्होंने कहा कि नए माहौल और नई श्रेणी में पहली ही क्वालीफाइंग में दूसरा स्थान हासिल करना असाधारण उपलब्धि है। टिएने के अनुसार, आतिका तेजी से सीखती हैं और अनजान ट्रैकों पर भी तुरंत प्रतिस्पर्धी बन जाती हैं।

उनके पिता आसिफ मीर, जो शुरूआती 2000 के दशक में एशियाई फॉमूर्ला श्रृंखला में उपविजेता रह चुके हैं, ने स्वीकार किया कि जूनियर वर्ग में इतनी जल्दी प्रवेश कराना बड़ा जोखिम था। उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात और अन्य चैंपियनशिप छोड़कर सीधे उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा में उतरना चुनौतीपूर्ण फैसला था, लेकिन आतिका ने अपेक्षाओं से बढ़कर प्रदर्शन किया है।

गौरतलब है कि मोटरस्पोर्ट में महिला भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ऐसे प्रदर्शन महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आतिका का लक्ष्य भविष्य में प्रमुख फॉमूर्ला श्रृंखलाओं में जगह बनाना है। इस सप्ताह वह इटली में हरड सुपर मास्टर्स के तीसरे चरण में फिर ट्रैक पर उतरेंगी, जहां उनसे एक और मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।

BBC 'इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर 2025' बनीं स्मृति मंधाना

वर्ल्ड कप जीतने वाली क्रिकेटर स्मृति मंधाना को भारत के लिए उनके शानदार प्रदर्शन के बाद 2025 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर चुना गया। 29 साल की मंधाना ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जीतने में भारत की वाइस-कैप्टन के तौर पर अहम भूमिका निभाई थी, उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान 434 रन बनाए थे। इस सम्मान के लिए भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर, शतरंज चैंपियन दिव्या देशमुख, शूटर सुरुचि सिंह और हर्डलर ज्योति याराजी को भी नॉमिनेट किया गया था। अवार्ड लेते हुए, मंधाना ने इसे महिला क्रिकेट के लिए एक यादगार दौर बताया।

उन्होंने कहा, 'यह एक खास साल रहा है। बीबीसी, मुझे बेस्ट स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर का अवॉर्ड देने के लिए धन्यवाद।' 'मुझे खुशी है कि मैं योगदान दे सकी और भारत को मैच जीतने में मदद कर सकी।' मंधाना को एक जूरी ने चुना था जिसमें पूर्व टेनिस स्टार लिएंडर पेस, पैरालंपिक मेडलिस्ट दीपा मलिक और लॉन्ग जम्पर अंजू बॉबी जॉर्ज शामिल थीं। उन्होंने 16 साल की उम्र में इंडिया के लिए डेब्यू किया था और सभी फॉर्मेट में 17 इंटरनेशनल सेंचुरी बनाई हैं, जिससे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। मंधाना ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ दो विमेंस प्रीमियर लीग टाइटल भी जीते हैं।

दूसरे अवॉर्ड विनर्स में, दिव्या देशमुख को 20 साल की उम्र में विमेंस वर्ल्ड कप जीतने के बाद एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। पैरा-एथलीट प्रीति पाल को 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप में दो मेडल जीतने के बाद बीबीसी पैरा स्पोर्ट्सवुमैन ऑफ द ईयर अवॉर्ड मिला, जबकि पूर्व शूटर अंजलि भागवत को इंडियन शूटिंग में उनके योगदान के लिए बीबीसी लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। सिडनी 2000 में, अंजलि ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला इंडियन शूटर बनीं। उन्होंने चार कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल भी जीते, जिसमें मैनचेस्टर में 2002 गेम्स में दो इंडिविजुअल टाइटल शामिल हैं।

CG POWER & INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD.
VCB PANEL, CRP, TRANSFORMER, RMU ETC

SECURE METERS LTD.
ENERGY METER (POSTPAID/PREPAID/ SOLAR/ABT)

SECURE

MITSUBISHI ELECTRIC
MCB/MCCB/ACB/ CONTRACTOR/DB

MITSUBISHI ELECTRIC

Kumar Enterprises

GF-150 | DURGA TOWER | RDC | RAJ NAGAR | GHAZIABAD (UP) - 201001
TEL. : 0120-4137613 | EMAIL : ke.ghaziabad@gmail.com
SANJEEV KUMAR 9268566079

SHANTI NATH MANUFACTURERS
A-2/14, Sector-17, Kavi Nagar, Industrial Area, Ghaziabad-201002 (U.P.)
Website: www.shantinathsupreme.com; E-mail: snmsupreme@gmail.com
Toll Free No.: 18001035266; Mob.: 8860638266

आयुष्मान भारत

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

70 वर्ष और उससे अधिक आयु के

सभी वरिष्ठ नागरिकों

को मिल रहा वय वंदना योजना का लाभ

योजना की विशेषताएं

- सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में ₹5 लाख तक का निःशुल्क उपचार
- मौजूदा बीमारियों का कवरेज पहले दिन से लागू
- 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग, जिनके पास पहले से कोई निजी बीमा है, वे भी पात्र होंगे
- 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के राज्य बीमा योजना (ESIC) के लाभार्थी भी पात्र होंगे

कैसे बनवाएं आयुष्मान वय वंदना कार्ड?

प्ले स्टोर से आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें → मोबाइल नंबर से लॉगिन करें → सभी आवश्यक जानकारी भरें और e-KYC करें → अपना कार्ड डाउनलोड करें

आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर

पात्रता के मापदंड

लाभार्थी की आयु 70 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है

आयु का सत्यापन आधार e-KYC के माध्यम से ही पूरा होगा

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत

15 जनवरी से 15 अप्रैल, 2026 तक विशेष अभियान

इस दौरान अपने नजदीकी कैंप पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं

सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची जानने के लिए QR कोड स्कैन करें

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें : 1800-1800-4444/14555

कार्यालय का पता — दूसरी और चौथी मंजिल, नवचेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

अब इंतजार किस बात का,
आज ही ऐप डाउनलोड कर बनवाएं

आयुष्मान वय वंदना कार्ड

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश · UPGovtOfficial · CMOUttarpradesh · CMOfficeUP